राष्ट्रीय संस्करण

वर्ष 9 अंक 290

दैनिक जागरण

मूल्य ₹8.00 नई दिल्ली, सोमवार, 30 मार्च, 2026

www.jagran.com

पृष्ठ 14

ईंधन की खेप भेजने के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति ने मोदी को दिया धन्यवाद

>> 10

जागरण विशेष

पद्म विभूति

लीची के वर्षों पुराने पेड़ों को दिया नया जीवन, बढ़ी आय

मुजफ्फरपुर : पद्मश्री डा. गोपालजी त्रिवेदी की कैनोपी मैनेजमेंट तकनीक लीची उत्पादकों के लिए वरदान साबित हुई है। • पेज-6

संपादकीय

ट्रंप के लिए वियतनाम बना ईरान : ईरान को लेकर अगर ट्रंप के लक्ष्य पूरे नहीं होते तो उन्हें मागा राष्ट्रपति के रूप में नहीं, वियतनाम से हारे निक्सन और इराक से पस्त बुश की तरह देखा जाएगा। **शिवकांत शर्मा** का विश्लेषण।

समान संहिता पर राह दिखाते राज्य : उत्तराखंड एवं गुजरात का यूसीसी की दिशा में बढ़ना अन्य राज्यों के साथ केंद्र को भी कानून बनाने के लिए प्रेरित करेगा। **डा. जगदीप सिंह** का आकलन। • पेज-8

विमर्श

इतिहास से आधुनिक प्रगति तक का सफर : जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस क्षेत्र की आर्थिक गति को तेज करने वाला कारक साबित होगा। **मनु त्यागी** का विश्लेषण।

'गांव के चुनाव के नाम पर पसरा सन्नाटा : राजनीतिक रूप से मुखर रहने वाले उत्तर प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, लेकिन चुनाव के नाम पर राजनीतिक दल चुप्पी साधे बैठे हैं। **अजय शुक्ला** की डायरी। • पेज-9

दैनिक जागरण

सप्तरंग

साहित्य और संगीत का

रोज एक कहानी लिख सकती हूं

गायन में जीवन-अनुभूतियों की छटाएं

• पेज-13

यह चुनौतीपूर्ण समय, स्वार्थ भरी राजनीति का कोई स्थान नहीं : मोदी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- 'मन की बात' में बोले पीएम, एक दशक में बने सामर्थ्य से परिस्थितियों का डटकर सामना कर रहा भारत
- एक करोड़ से अधिक भारतीयों की मदद के लिए प्रधानमंत्री ने खाड़ी देशों के प्रति आभार व्यक्त किया
- एक दशक में देश का जो सामर्थ्य बना है, उसके दम पर भारत संकट का डटकर कर रहा है मुकाबला

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। फाइल फोटो

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के माध्यम से एक बार फिर वैश्विक परिस्थितियों की चर्चा करते हुए एकजुटता की अपील की। खाड़ी देशों में एक माह से चल रहे युद्ध से विशेष तौर पर ऊर्जा अवश्यकताओं पर पड़े प्रभाव का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर यह चुनौतीपूर्ण समय है। देशवासियों से एकजुट होकर इस चुनौती से बाहर निकलने का आग्रह करते हुए पीएम मोदी ने बिना किसी का नाम लिए विपक्ष के रुख की आलोचना की। कहा कि जो लोग इस विषय पर राजनीति कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यह 140 करोड़ देशवासियों के हित से जुड़ा विषय है। इसमें स्वार्थ भरी राजनीति का कोई स्थान नहीं है।

'मन की बात' के 132वें संस्करण में पीएम मोदी ने कहा कि मार्च का यह महीना वैश्विक स्तर पर बहुत हलचल भरा रहा है। पूरा विश्व कोरोना के कारण लंबे समय तक अनेक समस्याओं से गुजरा था। सभी की अपेक्षा थी कि कोरोना के संकट से निकलने के बाद दुनिया नए सिरे से प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगी। लेकिन, दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रों में लगातार युद्ध और संघर्ष की परिस्थितियां बनती चली गईं। पड़ोस में एक माह से भीषण युद्ध का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे लाखों परिवारों के सगे-संबंधी इन देशों में रहते हैं, खासतौर पर खाड़ी देशों में काम करते हैं। प्रधानमंत्री ने एक करोड़ से अधिक भारतीयों की मदद के लिए खाड़ी देशों के प्रति आभार भी व्यक्त किया। साथ ही कहा कि जिस क्षेत्र में अभी युद्ध चल रहा है, वह क्षेत्र हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा केंद्र है। इसकी वजह से दुनियाभर में पेट्रोल-डीजल को लेकर संकट की स्थिति बनती जा रही है। हमारे वैश्विक संबंध, अलग-अलग देशों से मिल रहा सहयोग और पिछले एक दशक में देश का जो सामर्थ्य बना है, इनकी वजह से भारत इन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला कर रहा है। इसके अलावा पीएम ने पहली बार रणजी ट्राफी जीतने वाली जम्मू-कश्मीर की क्रिकेट टीम सहित समाज के लिए उल्लेखनीय कार्य कर रहे व्यक्तियों व संस्थाओं की भी चर्चा की।

देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे अफवाह फैलाने वाले

परिस्थितियों को चुनौतीपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जो भी लोग अफवाह फैला रहे हैं, वे देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। देशवासियों से अपील है कि वे जागरूक रहें, अफवाहों के बहकावे में न आएं। सरकार की तरफ से जो निरंतर जानकारी दी जा रही है, उस पर भरोसा करें और तदनुसार कोई कदम उठाएं। उन्होंने दोहराया कि जैसे हमने 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य से पुराने संकटों को हराया था, इस बार भी हम सब मिलकर इस कठिन हालात से बहुत ही अच्छी तरह बाहर निकल जाएंगे।

मोटापे से बचने के लिए चीनी और तेल का सेवन कम करें

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से चीनी का सेवन कम करने और खाना पकाने के तेल का उपयोग 10 प्रतिशत तक घटाने का आग्रह किया। ऐसे छोटे प्रयास लोगों को मोटापे और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से बचाएंगे। मैं आप सभी से चीनी का सेवन कम करने का आग्रह करता हूं। हमें खाना पकाने के तेल का उपयोग भी 10 प्रतिशत तक कम करना होगा।

अब होर्मुज पर हमला, खार्ग पर कब्जे की तैयारी

पेंटागन की ईरान पर सीमित, पर निर्णायक प्रहार की है तैयारी

- पश्चिम एशिया पहुंचे 3500 अमेरिकी नौसैनिक
- अमेरिकी सेना ने कहा- दो टुकड़ियों में से पहली टुकड़ी पश्चिम एशिया पहुंची
- खार्ग, लारक और अबू मूसा द्वीप निशाने पर, तेहरान ने दी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में महीनेभर से अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी सैन्य संघर्ष नया मोड़ लेता दिख रहा है। हवाई हमलों से ईरान को 15 सूत्रीय समझौते के लिए झुका न पाने के चलते अमेरिका अब जमीनी सैन्य अभियान चलाने की तैयारी में जुट गया है। अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली करीब 3,500 मरीन और नेवी सैनिकों के साथ इस इलाके में पहुंच गया है। जबकि दूसरी टुकड़ी रास्ते में है। इसके साथ ही 82वीं एयरबोर्न डिवीजन का कमांड भी भेजा जा रहा है, जिससे त्वरित तैनाती और सीमित अवधि के हमलों की क्षमता बढ़ेगी। हालांकि, हालात को बिगड़ने से बचाने के लिए पाकिस्तान में तीन देशों, सऊदी अरब, तुर्किए और मिस्र के विदेश मंत्रियों की बैठक रविवार से शुरू हुई, जो सोमवार को भी जारी रहेगी।

अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली करीब 3,500 मरीन और नेवी सैनिकों के साथ अमेरिकी सेंट्रल कमांड के नियंत्रण वाले क्षेत्र में पहुंचा। एपी

पेंटागन ने हफ्तों की अवधि वाले अभियानों का खाका किया है तैयार

न्यूयार्क टाइम्स के अनुसार, पेंटागन ने महीनों नहीं, बल्कि हफ्तों की अवधि वाले अभियानों का खाका तैयार किया है। इसमें विशेष बलों और पारंपरिक पैदल सेना की तेज कार्रवाई शामिल है, जो लक्ष्य पर प्रहार कर शीघ्र वापसी करेगी ताकि ईरान को लंबी जवाबी लड़ाई का अवसर न मिले। यह तैयारी पहले से कई दौर के युद्धाभ्यासों के बाद की गई है।

रायटर के अनुसार, पेंटागन ने ईरान के खिलाफ सीमित लेकिन अत्यधिक प्रभावी जमीनी अभियानों की विस्तृत तैयारी तेज कर दी है। ऐसे सैन्य विकल्पों पर विचार चल रहा है जिनमें पूर्ण पैमाने पर आक्रमण नहीं, बल्कि चुनिंदा रणनीतिक ठिकानों पर त्वरित छापामार कार्रवाई, विशेष बलों की घुसपैठ और सीमित अवधि के कब्जे शामिल हैं।

खार्ग द्वीप पर अमेरिकी कब्जे से ईरान को लगेगा भारी आर्थिक झटका पेज>>11

अमेरिकी सैनिक हमारी भूमि पर उतरे तो कड़ा सबक सिखाएंगे : ईरान

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

- ईरानी संसद के स्पीकर ने कहा- अमेरिका के मुंह में बात और बगल में है घात
- अमेरिका की 15-सूत्री योजना पर ईरान का पलटवार, गलीबाफ बोले- अपमान कभी स्वीकार नहीं

अमेरिका और इजरायल के साथ संभावित जमीनी सैन्य टकराव को लेकर ईरान ने कड़ी चेतावनी जारी की है। ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलीबाफ चेतावनी दी कि यदि अमेरिकी सैनिक ईरानी भूमि पर उतरे तो उन्हें 'ऐसी आग में झोंक दिया जाएगा जिसे क्षेत्रीय सहयोगी भी लंबे समय तक याद रखेंगे।' ईरान की मिसाइलें तैनात हैं, जवाबी हमले जारी हैं और देश की सैन्य प्रतिबद्धता पहले से अधिक मजबूत हुई है। गलीबाफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के जरिये तेहरान तक पहुंचाई गई अमेरिकी 15-सूत्री योजना वस्तुतः वाशिंगटन की इच्छाओं की सूची है, न कि स्वीकार्य कूटनीतिक प्रस्ताव।

ईरानी सरकारी मीडिया फार्स के अनुसार गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका बातचीत की भाषा बोल रहा है, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य जमीनी हमला कर ईरान को झुकाना है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दुश्मन वार्ता की बात करता है, लेकिन जमीन पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है। अमेरिका 15 बिंदुओं की सूची के जरिये वह हासिल करना चाहता है, जो युद्ध में नहीं कर सका। हमारी सेनाएं तैयार हैं और हम कभी अपमानित नहीं होंगे।

तेहरान पहले ही कह चुका है कि वह किसी भी ऐसी शर्त को स्वीकार नहीं करेगा जिसे आत्मसमर्पण के रूप में देखा जाए।

'अमेरिका-इजरायल युद्ध का दायरा बढ़ाने की कर सकते हैं कोशिश' पेज>>11

ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गलीबाफ। (फाइल फोटो- रायटर)

उड़ानों में 20 अप्रैल से बिना अतिरिक्त शुल्क 60% सीटें

नई दिल्ली : एयरलाइन कंपनियां 20 अप्रैल से किसी भी उड़ान में कम से कम 60% सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराना शुरू कर देंगी। एयरलाइन कंपनियां पारदर्शी सीट आवंटन नीति भी बनाएंगी। मौजूदा व्यवस्था में केवल करीब 20% सीटें ही बिना शुल्क के उपलब्ध होती हैं, जबकि बाकी सीटों के चयन के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है। (पेज-3)

एक दशक में 10 हजार से अधिक माओवादियों का समर्पण

नई दिल्ली : सुरक्षा दबाव और पुनर्वास प्रयासों के संयोजन ने देश के सबसे लंबे समय तक चलने वाले विद्रोहों में से एक माओवाद को घातक झटका दिया है। पिछले दशक में 10 हजार से अधिक माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश से माओवाद को समाप्त करने की समयसीमा 31 मार्च तय की है। (पेज-6)

'मुस्लिमों पर भी लागू होता है संरक्षक व प्रतिपाल्य अधिनियम'

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम कानून से शासित होने वाले पक्षकार भी अपने नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा प्राप्त करने के लिए संरक्षक व प्रतिपाल्य अधिनियम का सहारा ले सकते हैं। यह अधिनियम धर्म पर ध्यान दिए बिना सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। मुस्लिम पर्सनल ला के तहत आने वाले लोग भी इसमें राहत पाने के हकदार हैं। (पेज-7)

'बिना मुकदमा चलाए जेल में रखना है सजा'

- दो वर्षों से जेल में बंद हत्या के प्रयास के पंजाब निवासी आरोपित को दी जमानत
- कहा- न तो सुनवाई शुरू हुई है, न ही अभी नतीजा आने की उम्मीद

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने बिना मुकदमा चलाए कारावास में रखने को सजा के समान बताते हुए हत्या के प्रयास के एक मामले में पंजाब के एक व्यक्ति को जमानत दे दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि आरोपित व्यक्ति दो वर्षों से जेल में है, जबकि मुकदमे की सुनवाई शुरू तक नहीं हुई है।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीवी वराले की पीठ ने 13 मार्च के अपने आदेश में कहा कि प्रदीप कुमार उर्फ बानू के विरुद्ध फरवरी, 2024 में हत्या के प्रयास सहित विभिन्न अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष ने अभी तक मामले से संबंधित 23 गवाहों में से किसी से भी जिरह नहीं की है। प्रदीप की गिरफ्तारी को लगभग दो वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन न तो मुकदमा शुरू हुआ है और न ही अभी इसका नतीजा आने की कोई उम्मीद है। बिना मुकदमे के

कारावास सजा के समान है। मामले का समग्र रूप से अवलोकन करते हुए अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मुकदमे की सुनवाई तक अपीलकर्ता को कैद में रखना आवश्यक नहीं है। चूंकि अपील स्वीकार करने योग्य है, इसलिए अपीलकर्ता को जमानत दी जा सकती है। पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के 11 जुलाई, 2025 के उस आदेश को रद कर दिया, जिसमें प्रदीप की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

शीर्ष अदालत ने प्रदीप कुमार को ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के अनुरूप जमानत बांड प्रस्तुत करने और अन्य नियम-शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया। अगर जमानत शर्तों और नियमों का कोई उल्लंघन होता है, तो ट्रायल कोर्ट अपीलकर्ता की जमानत रद करने के लिए स्वतंत्र होगा। शीर्ष न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए प्रदीप कुमार को निर्देश दिया कि वह मुकदमे की सुनवाई में नियमित रूप से उपस्थित रहेगा जब तक कि उसे छूट न दी जाए। अगर वह बिना किसी उचित कारण के सुनवाई से अनुपस्थित होता है, तो इसे जमानत शर्तों का उल्लंघन माना जा सकता है और ट्रायल कोर्ट उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

असम में भाजपा सरकार लागू करेगी यूसीसी : शाह

गुवाहाटी : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को असम में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए राज्य की सुरक्षा और जनसांख्यिकीय बदलाव को लेकर बड़े एलान किए। कहा कि भाजपा की सरकार आने वाले दिनों में असम में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करेगी। (पेज-4)

मुद्दा

पश्चिम एशिया की जंग बनेंगे नए समीकरण • पेज-7

आइपीएल 19 धूम धड़ाका

आज का मैच

राजस्थान रायल्स *vs* चेन्नई सुपर किंग्स

शाम 7:30 बजे स्थान : गुवाहाटी

प्रसारण : स्टार स्पोर्ट्स/जियो हाटस्टार

पीएनजी धारकों ने लौटाए 6,000 एलपीजी कनेक्शन

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

- एलपीजी किल्लत के बीच सरकार ने किया था अनुरोध ताकि जरूरतमंदों को एलपीजी मिल सके
- कहा- 'माईपीएनजीडी' पोर्टल के माध्यम से अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करें पीएनजी धारक

पेट्रोलियम मंत्रालय की अपील के बाद देश में लगभग 6,000 पीएनजी उपभोक्ताओं ने अपने एलपीजी कनेक्शन लौटा दिए हैं। सरकार ने उनका आभार व्यक्त किया है। पश्चिम एशिया में युद्ध के चलते एलपीजी किल्लत के बीच सरकार ने पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं से अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने की अपील की थी ताकि जरूरतमंद परिवारों को एलपीजी सिलिंडर मिलने में दिक्कत न हो। यही नहीं, सरकार ने बताया है कि मार्च में 2.90 लाख से ज्यादा नए पीएनजी कनेक्शन दिए गए हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव नीरज मित्तल ने एक्स पर पोस्ट किया- ' बीते रोज तक 6,000 पीएनजी उपभोक्ताओं ने अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं। उनका बहुत-बहुत आभार।' साथ ही उन्होंने पात्र पीएनजी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया कि वह 'माईपीएनजीडी' पोर्टल के माध्यम से अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करें। बता दें कि बीते मंगलवार को मंत्रालय ने आदेश में कहा था कि घर में पीएनजी कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद यदि आप एलपीजी सिलिंडर का उपयोग जारी रखते हैं तो तीन महीने बाद आपकी एलपीजी सप्लाई बंद कर दी जाएगी।

एलपीजी। फाइल

कालाबाजारी रोकने को 2,900 जगह छापेमारी, 1,000 सिलिंडर जब्त

एएनआइ के अनुसार, सरकार ने उपभोक्ताओं से यह भी अनुरोध किया है कि वे एलपीजी बुकिंग आनलाइन करें और एलपीजी वितरण केंद्रों पर जाने से बचें। सरकार की ओर से बताया गया कि एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छापेमारी जारी है। शनिवार को लगभग 2,900 स्थानों पर छापे मारे गए और लगभग 1,000 सिलिंडर जब्त किए गए।

सकारात्मक कदम

तेलंगाना विधानसभा से विधेयक सर्वसम्मति से पारित, निजी क्षेत्र के कर्मचारी और जनप्रतिनिधि भी दायरे में

माता-पिता की उपेक्षा की तो तेलंगाना में वेतन से कटेंगे 10 हजार रुपये

हैदराबाद, प्रेट्र : तेलंगाना विधानसभा ने रविवार को 'तेलंगाना कर्मचारी की जवाबदेही और माता-पिता के भरण-पोषण की निगरानी विधेयक, 2026' को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। बिल में माता-पिता की उपेक्षा करने वाले कर्मचारियों के कुल वेतन से 15 प्रतिशत या 10,000 रुपये (जो भी कम हो) तक की कटौती का प्रविधान है। काटी गई राशि सीधे उनके माता-पिता को दी जाएगी। इसके दायरे में केवल सरकारी कर्मचारी ही नहीं, बल्कि निजी क्षेत्र के कर्मचारी और विधायक, एमएलसी, कारपोरेटर, पार्षद एवं सरपंच जैसे जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं।

प्रदेश के एससी-एसटी कल्याण एवं वरिष्ठ नागरिक मंत्री अड्लूरी लक्ष्मण कुमार ने इसे पेश किया। सभी दलों ने इसका समर्थन किया और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने बताया कि देश में पहले से ही एक राष्ट्रीय कानून मौजूद है, जिसका नाम 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007' है। लेकिन राज्य का यह नया विधेयक जनप्रतिनिधियों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी अपने दायरे में लाएगा।

तेलंगाना विधानसभा। फाइल

भाजपा विधायक ने कहा, देश में अपनी तरह का पहला विधेयक

भाजपा विधायक पायल शंकर ने इसे देश में अपनी तरह का पहला विधेयक बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी इस विधेयक का समर्थन करती है। उन्होंने सुझाव दिया कि इसमें निर्धारित राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। भाकपा सदस्य के. संबाशिव राव ने कहा कि उनकी पार्टी भी इस विधेयक का समर्थन करती है।

'हेट स्पीच' बिल भी विधानसभा में पेश

तेलंगाना सरकार ने रविवार को विधानसभा में "तेलंगाना हेट स्पीच और हेट क्राइम (प्रिवेंशन) बिल, 2026" पेश किया। इस बिल में संबंधित अपराधों के लिए 50 हजार से एक लाख रुपये तक जुर्माने और एक से 10 वर्ष तक जेल की सजा का प्रस्ताव है। इस तरह का बिल पारित करने वाला कर्नाटक के बाद तेलंगाना दूसरा राज्य होगा। इस बिल के तहत किए गए अपराध गैर-जमानती होंगे।

इस विधेयक में कर्मचारियों के लिए माता-पिता की देखभाल और भरण-पोषण के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को स्पष्ट निर्धारित किया गया है। इसमें बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवा, आवास और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेही तय की गई है। साथ ही इसमें उपेक्षा से निपटने के भी प्रविधान हैं और ऐसी व्यवस्था है जिसमें अधिकारी जरूरत पड़ने पर दखल देकर नियमों का पालन करवा सकें।

मुख्यमंत्री ने चर्चा के दौरान उद्योगपति विजयपत सिंघानिया का उदाहरण दिया,, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेटे को दे दी थी और बाद में उसने उन्हें घर से निकाल दिया। रेड्डी ने कहा कि जो लोग अपने माता-पिता की उपेक्षा करते हैं, उन्हें समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने बताया कि वह एक ऐसे जनप्रतिनिधि को जानते हैं, जिसने अपने पिता को कैंसर होने पर उनकी देखभाल नहीं की। हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने समाज से ऐसे लोगों का बहिष्कार करने का आह्वान किया।

दिव्यांगजनों की तर्ज पर बुजुर्गों के लिए भी एक नया विभाग बनाने की सिफारिश पेज>>3

धमकी भरे फोन काल पर चुनाव आयोग सतर्क, कहा-दर्ज कराएं शिकायत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- बंगाल से बाहर रह रहे वोटरों के पास आ रहे धमकी भरे फोन की शिकायतों पर आयोग ने बढ़ाई निगरानी

बंगाल विधानसभा के लिए 23 और 29 अप्रैल को होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने या फिर नहीं लेने को लेकर राज्य के बाहर रह रहे मतदाताओं के पास आ रहे फोन काल की शिकायतों पर चुनाव आयोग ने सतर्कता बढ़ा दी है। साथ मतदाताओं से इसकी शिकायत दर्ज कराने को कहा है। इस दौरान जिन नंबरों से ऐसे फोन आ रहे हैं, उनकी भी जानकारी साझा करने को कहा है। वहीं राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इसे लेकर सतर्क किया गया है। ऐसे वोटरों को धमकाने वालों से सख्ती से निपटने के लिए कहा है।

आयोग ने इस दौरान मतदाता से स्थानीय स्तर पर पुलिस के पास इसकी शिकायत दर्ज कराने के साथ हेल्पलाइन नंबर 1950, सी-विजिल एप और वोटर सर्विस हेल्पलाइन के जरिये आनलाइन शिकायत दर्ज कराने जैसे विकल्प भी दिए हैं। आयोग से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक उनके पास भी ऐसी शिकायत पहुंच रही हैं लेकिन जिन नंबरों से ये फोन आ रहे हैं, उनके न मिलने से वह आगे जांच नहीं कर पा रहे। ऐसे में जरूरी है कि बंगाल से बाहर रह रहे जिन मतदाताओं के पास ऐसे फोन आ रहे हैं वे उन नंबरों को भी साझा करें, जिनसे ऐसे फोन आ रहे हैं। गौरतलब है कि आयोग ने बंगाल में हिंसा की घटनाओं को देखते हुए निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए राज्य में 478 पर्यवेक्षकों के साथ ही केंद्रीय पुलिस बल की बड़े स्तर पर तैनाती की है।

आज का मौसम

सामान्यतया बादल छाए रहेंगे। गर्जन वाले बादल बनने, 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवाएं चलने के साथ- साथ हल्की वर्षा होने के भी आसार हैं।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
30 मार्च	31.0	21.0
31 मार्च	31.0	18.0
नोएडा		
30 मार्च	30 .0	17.0
31 मार्च	30 .0	18.0
गुरुग्राम		
30 मार्च	30 .0	20.0
31 मार्च	30 .0	20.0
डिग्री सेल्सियस में		

न्यूज गैलरी

रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़ गिरोह का शूटर गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़-वीरेंद्र चारण गिरोह के शूटर दीपक उर्फ दिलावर को पंजाब के सैनिक विहार से गिरफ्तार किया है। वह उन्नाव का रहने वाला है। आरोपित के घर से एक लोडेड सेमी-आटोमैटिक पिस्टल बरामद की गई। मामले में स्पेशल सेल ने आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया है। (जासं)

छह महीने में टोल दर में कर दी 20 रुपये की बढ़ोतरी

गुरुग्राम : असुविधाओं के प्रतीक दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे के खेड़कीदौला टोल प्लाजा से निकलना एक अप्रैल से और महंगा हो जाएगा। छह महीने के भीतर टोल दर में 20 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी गई, लेकिन सुविधाएं बढ़ाने के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। जैसी स्थिति एक्सप्रेसवे की छह महीने पहले थी, कमोवेश वैसी आज भी है। न सड़क की मरम्मत हुई, न अवैध कट बंद हुए, न रेलिंग दुरुस्त हुई और न ही लाइटों की स्थिति में कोई सुधार हुआ। हीरो होंडा चौक फ्लाईओवर पिछले दो साल से मरम्मत की बाट जोह रहा है। (जासं)

50 हजार का इनामी वांछित हथियार सप्लायर गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली, हरियाणा और यूपी में छह आपराधिक मामलों में शामिल हथियार सप्लायर मोहम्मद इसरार उर्फ कट्टा को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। वह शामली का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस की तरफ से उस पर 50 हजार का इनाम था। सोनीपत पुलिस से भी उस पर एक मामले में पांच हजार का इनाम था। (जासं)

ग्रेनो में 1365 हेक्टेयर में विकसित होगा एमआरओ हब

फेसिलिटी सेंटर ▶ कोड एफ होने से 85 मीटर लंबे पंखों वाले विमान उतरेंगे, एक ही जगह यात्री व मेंटेनेंस की सुविधा

अभी 90 प्रतिशत विदेश पर निर्भरता, इसके बनने से एयरबस और बोइंग जैसे विमान होंगे दुरुस्त

अर्पित त्रिपाठी • जागरण

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फाइल

ग्रेटर नोएडा : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एनआइए) के लोकार्पण के दौरान 40 एकड़ में हवाई जहाजों की मरम्मत के लिए मेंटेनेंस, रिपेयर और आपरेशन (एमआरओ) सेंटर का शिलान्यास किया था। यह तो सिर्फ शुरुआती चरण है। एमआरओ फेसिलिटी 1365 हेक्टेयर जैसे विशाल क्षेत्र में विकसित होगी, जो देश दुनिया के सबसे बड़े फेसिलिटी सेंटर में से एक होगी। दरअसल भारतीय एयरलाइंस ने 1,700 से अधिक विमानों का आर्डर दिया है, जिसके चलते देश में एडवांस्ड मेंटेनेंस की मांग बढ़ रही है। भविष्य में यह संख्या और बढ़ेगी। वहीं दूसरी तरफ दुनियाभर में हवाई ट्रैफिक में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिस कारण उपकरण बनाने वाली कंपनियां जैसे कि बोइंग और एयरबस पर उपकरण उपलब्ध कराने का दबाव है। ऐसे में एनआइए का एमआरओ देश ही नहीं दुनिया के एविएशन सेक्टर के लिए हब के रूप में उभरेगा।

एयरपोर्ट के निर्माण के शुरुआती दौर में उत्तर प्रदेश सरकार ने ज्यूरिख के साथ कंसेशन एग्रीमेंट कर 10 साल में एमआरओ विकसित करने की रूपरेखा तैयार की थी। एनआइए के सभी पांच चरणों के लिए 1334 हेक्टेयर जमीन में से 40 एकड़ में एमआरओ को विकसित किया जाना है। योगी आदित्यनाथ ने आगे की सोचते हुए दूसरे फेज के लिए 1365 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण कर इस जमीन पर डेडिकेटेड एमआरओ हब विकसित करने का निर्णय लिया है।

एयरबस व बोइंग जैसे विशाल विमानों की भी होगी मरम्मत : इस एमआरओ में एयरबस और बोइंग जैसे विशाल विमानों की भी मरम्मत होगी। यही कारण है कि इस एयरपोर्ट को कोड-एफ प्रदान किया गया है। कोड एफ एयरपोर्ट में 65 से 80 मीटर लंबे पंखों के फैलाव वाले विमान उतर सकते हैं।

एमआरओ के बनने से कलपुर्जे के साथ ही अन्य उपकरण और मशीनें बनाने के लिए वेंडर कंपनियां और सब्सिडी कंपनी का जमावड़ा होगा, जिससे रोजगार उत्पन्न होने के साथ ही आर्थिक रूप से मजबूती भी आएगी। हालांकि इसे 2040 तक विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन प्रदेश सरकार ने भविष्य के मद्देनजर एमआरओ के निर्माण में किसी प्रकार की बाधा न आए उससे पहले ही इस जमीन का अधिग्रहण कर लिया है। यह भी सामने आ रहा है कि एमआरओ को 2040 से पहले ही शुरू करा दिया जाए। ओरिजनल इक्विपमेंट मैन्यूफैक्चरर्स (ओईएम), शोध और विकास इकाइयां, प्रशिक्षण और सप्लायर्स के अलावा अन्य को यह क्षेत्र आकर्षित करेगा।

अकासा का दूसरा बेस नोएडा एयरपोर्ट : विमान कंपनी अकासा एयर मुंबई के बाहर अपना पहला बेस नोएडा में बनाने की योजना बना रही है, जहां एमआरओ की पूरी सुविधा होगी, ताकि विमानों की यात्री मिलने के साथ ही मरम्मत भी हो सके।

विमानों का घटेगा डाउन टाइम समय : एमआरओ बनने से एयरपोर्ट में खराब हुए किसी विमान के डाउन टाइम में कमी आएगी। डाउन टाइम वह समय होता है जब विमान ठीक होने के लिए खड़ा रहता है। एमआरओ होने से समय रहते विमान दुरुस्त हो सकेगा। इसके साथ ही टर्न अराउंड टाइम में भी कमी आएगी। टर्न अराउंड टाइम वह होता है जिसमें जहाज जब उतरता है और उड़ान भरता है उसके बीच का समय।

अभेद्य होगी नोएडा एयरपोर्ट की सुरक्षा, एंटी ड्रोन और रोबोटिक सिस्टम तैनात

जागरण संवाददाता, जेवर

▶ जमीन से आसमान तक पलक झपकते ही होगा दुश्मन का काम तमाम

भारत में निर्मितमिनी रिमोटली आपरेटेड व्हीकल (एमआरओवी) रोबोटिक सिस्टम से ट्रायल करते सुरक्षाकर्मी। जागरण आर्काइव

नोएडा एयरपोर्ट के लोकार्पण के बाद यापल संचालन की तैयारियों में जुटा है। एयरपोर्ट पर यात्रियों को विश्वस्तरीय सुरक्षा देने के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। रनवे पर निगरानी के लिए हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं। भारत में निर्मित अत्याधुनिक मिनी रिमोटली आपरेटेड व्हीकल (एमआरओवी) रोबोटिक सिस्टम बेहद जोखिम वाले बम का पता लगाने और निष्क्रिय करने के लिए सीआइएसएफ की क्विक रिएक्शन टीम को सौंपा जा चुका है।

एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा.लि. ने सिक्योरिटी डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित मिनी रिमोटली आपरेटेड व्हीकल को तैनात किया है। भारत में निर्मित एमआरओवी रोबोटिक सिस्टम बेहद जोखिम वाले बम का पता लगाने और निष्क्रिय करने के लिए तैयार किया गया है। इसे दूर बैठकर वायरलेस सिस्टम से आपरेट किया जाता है। एमआरओवी में लगे सेंसर संदिग्ध वस्तु या बम का पता लगाकर कम समय में सुरक्षित स्थान पर ले जाकर बम आदि को निष्क्रिय करने की क्षमता है। इस सिस्टम से सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षित रखते हुए तेजी से सटीक और जीवन रक्षक आपरेशन को आपातकाल में पूरा किया जा सकता है। 4200 मीटर लंबे रनवे की निगरानी के लिए प्रत्येक 50 मीटर पर हाई रेजोल्यूशन एआइ कैमरे लगाए गए हैं। उधर, सीआइएसएफ ने एयरपोर्ट की सुरक्षा को संभाल लिया है। उप्र पुलिस की तरफ से यात्रियों की सुरक्षा के लिए दो पुलिस थानों में विशेष प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है।

'स्थानांतरण वाली नौकरी में कर्मी खास स्थान पर तैनाती नहीं मांग सकता'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के एक शिक्षक के स्थानांतरण को दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहते हुए बरकरार रखा है कि स्थानांतरण नौकरी का एक हिस्सा है और स्थानांतरण हो सकने वाले पद पर काम करने वाला कर्मचारी अपने अधिकार के तौर पर किसी खास जगह पर तैनाती की मांग नहीं कर सकता। याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल व न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने कहा कि अगर दिव्यांगता प्रमाणपत्र न हो, तो बाइपोलर डिसआर्डर के संबंध में लागू स्थानांतरण नीति मेडिकल दिव्यांगता वाले नियम के तहत नहीं आता।

याचिकाकर्ता ने दिल्ली से बाबूपाड़ा कैंट स्थित केंद्रीय विद्यालय में स्थानांतरण रोकने से इन्कार करने के कैट के आदेश को चुनौती दी थी। केवीएस में प्राइमरी शिक्षक के तौर पर कार्यरत याचिकाकर्ता स्थानांतरण में बदलाव की मांग करते हुए तर्क दिया था कि उन्हें बाइपोलर अफेक्टिव डिसआर्डर है और उन्हें इलाज के साथ परिवार के सहारे की भी जरूरत है। हालांकि, उनकी मांग को अदालत ने यह नोट करते हुए ठुकरा दिया कि 30 जून 2023 से लागू स्थानांतरण नीति में मेडिकल आधारों को सिर्फ कुछ खास मामलों में ही मान्यता दी गई है। इनमें 50 प्रतिशत से ज्यादा मानसिक दिव्यांगता वाली कोई दूसरी बीमारी भी शामिल है।

अगले दो साल में डीडीए तैयार करेगा 26 हजार नए किफायती घर

संजीव गुप्ता • जागरण

▶ दिल्ली का नया संकल्प : झुग्गीमुक्त भविष्य और 3,484 करोड़ रुपये का आवंटन

डीडीए की जहां झुग्गी, वहीं मकान योजना के तहत कठपुतली कालोनी में तैयार किए जा रहे फ्लैट। आर्काइव

नई दिल्ली : दिल्ली की स्काईलाइन अब सिर्फ ऊंची इमारतों की नहीं, बल्कि 'किफायती सम्मान' की पहचान बनने वाली है। दिल्ली आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि राजधानी में 'जहां झुग्गी, वहीं मकान' का सपना अब फाइलों से निकलकर धरातल पर कंक्रीट का आकार ले रहा है।

इस रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत अनेक आवास परियोजनाओं के तहत कुल 2750.91 करोड़ रुपये की लागत 52,584 फ्लैटों का निर्माण कार्य किया जाएगा। अब तक 24,524 फ्लैटों का निर्माण किया जा चुका है। 28,060 फ्लैटों का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों के तहत किया जा रहा है।

आंकड़ों की जुबानी : घर का सफर : रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से स्वीकृत आवास परियोजनाओं में तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की योजनाओं व कार्यक्रमों व परियोजनाओं के लिए 2025-26 बजट आवंटन में आवास व शहरी विकास के लिए 3,484 करोड़ रुपये यानी कुल बजट का छह प्रतिशत बजट आवंटित किया गया। जबकि जलापूर्ति व सफाई को लेकर 9 हजार करोड़ रुपये यानी 15 प्रतिशत बजट आवंटित किया गया।

26 हजार से अधिक फ्लैटों का निर्माण होगा : डीडीए के अधिकारियों ने बताया कि जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के तहत अगले दो वर्षों में दिल्ली में 26 हजार से अधिक फ्लैटों का निर्माण कार्य किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न झुग्गियों के क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। इससे पहले कुछ स्थानों पर डीडीए द्वारा झुग्गी वासियों के लिए निर्मित फ्लैटों को भी आवंटित किया गया है। ये फ्लैट केवल ईंट-पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि उन परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा है जो दशकों से झुग्गियों में बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे थे।

दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं ढांचागत विकास निगम (डीएसआइआइडीसी) के आठ प्रोजेक्ट, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) के छह प्रोजेक्ट व एक प्रोजेक्ट एनडीएमसी के अधीन है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025-26 के

बाढ़ क्षेत्र में अतिक्रमण हटा 1426.6 एकड़ भूमि पर वापस लिया कब्जा: डीडीए

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : वर्ष 2023 में आई बाढ़ को लेकर प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा शुरू की गई याचिका पर दिल्ली सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है। इसमें कहा है कि यमुना बाढ़ क्षेत्र से 1426 एकड़ भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है। दिल्ली में भविष्य में बाढ़ को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी हलफनामे में दी गई है।

दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि मई 2022 से फरवरी 2026 के बीच 1426 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस पर कब्जा प्राप्त किया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2023 में आई बाढ़ जैसी स्थिति से बचने के लिए विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत मजनू का टीला से लेकर निगम बोध घाट तक बाढ़ के पानी को रोकने के लिए दीवार बनाने की योजना है।

एक तरफ अहंकारी तो दूसरी तरफ पीड़ित: अखिलेश

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

▶ दादरी स्थित मिहिर भोज डिग्री कालेज में समानता भाईचारा सम्मेलन में बोले सपा प्रमुख

दादरी के मिहिर भोज डिग्री कालेज में आयोजित रैली में लागों को संबोधित करते सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। सौरभ राय

पांच प्रतिशत लोग 95 प्रतिशत लोगों का शोषण कर अधिकारों से वंचित करने का काम कर रहे हैं। एक तरफ अहंकारी है तो दूसरी तरफ पीड़ित, जो पीड़ित है वो पीडीए हैं। सपा ने पीडीए यानी पीड़ितों को एक साथ लाने का काम किया है। यह केवल रैली नहीं बल्कि आह्वान है। आने वाले समय में हम पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक (पीडीए) के लोग मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। यह बात सपा अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दादरी स्थित मिहिर भोज डिग्री कालेज में समानता भाईचारा सम्मेलन के दौरान कहीं।

उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर हुई जनसभा की पोल बहुत लोगों ने खोल दी। कोई कैमरे से नहीं बच सकता। लोगों की भीड़ जुटाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को सरकारी कर्मचारियों का सहारा लेना पड़ा। रैली में लोग आए नहीं, लाया गया था। जेवर के एयरपोर्ट को किसी ने एनओसी दिलाने का काम किया था तो वह सपा थी। उसी का परिणाम है जो यहां एयरपोर्ट बना, जो लोग एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे थे, वे पहले भी सात एयरपोर्ट का उद्घाटन कर चुके हैं, जिनमें से छह बंद हो गए। उन्हें वादा करना चाहिए कि जिसका उद्घाटन किया उसे बेचेंगे नहीं।

लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है घुसपैठ रूके: इंद्रेश कुमार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (एमआरएम) के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार ने घुसपैठियों पर सख्ती से रोक लगाने जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची व चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी देश की एकता और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। वह राजघाट स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान के सभागार में एमआरएम की राष्ट्रीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। इसके बाद ईद मिलन समारोह आयोजित किया गया।

बैठक में इंद्रेश कुमार ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित हो। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध को तत्काल बंद किए जाने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि देश में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। तेल व गैस को लेकर अनावश्यक भ्रम व डर फैलाने की जरूरत नहीं है। आज भारत आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है।

बिजली, बस महिला टिकट पर सब्सिडी बढ़ने से आइटी खर्च में कटौती

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली

▶ आइटी परियजनाओं के खर्च 2025-26 के लिए 690.5 करोड़ रुपये था, लेकिन मौजूदा खर्च के लिए संशोधित अनुमान सिर्फ 215 करोड़ रुपये है

महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा स्कीम और बिजली के लिए दिल्ली सरकार का सब्सिडी बजट बढ़ गया है, जबकि इस साल के रिवाइज्ड बजट अनुमान के अनुसार इसके बड़ी आइटी परियजनाओं लिए फंड में कटौती की गई है। वित्त विभाग द्वारा हाल ही में जारी किए गए रिवाइज्ड एस्टीमेट (आरई) के आंकड़ों से पता चला है कि बिजली सब्सिडी के लिए खर्च बढ़ाकर लगभग 4,200 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि इस साल के लिए बजट एस्टीमेट (बीई) 3,849 करोड़ रुपये था। यह बदलाव उपभोक्ताओं के नंबर बढ़ने के कारण बिजली सब्सिडी स्कीम के तहत बकाया चुकाने और ज्यादा मांग को पूरा करने के लिए उठाया गया है।

बता दें कि दिल्ली सरकार बिजलीको लेकर सब्सिडी देती है। परिवहन विभाग के आरई से पता चला है कि डीटीसी बसों में महिला यात्रियों के लिए डीटीसी को सब्सिडी 240 करोड़ के बजट अनुमान (बीई) के मुकाबले बढ़कर 328 करोड़ रुपये हो गई है। फ्री यात्रा के लिए क्लस्टर सेवा की सब्सिडी को भी 2026-27 में 200 करोड़ रुपये के बीई अनुमान से बढ़ाकर 342 करोड़ कर दिया गया है। महिला यात्रियों को दी जाने वाली सब्सिडी की कुल रकम 440 करोड़ रुपये के बीई अनुमान के मुकाबले बढ़कर 670 करोड़ रुपये हो गई है।

बजट आरई दस्तावेजों के मुताबिक आइटी विभाग का 2025-26 के लिए 690.5 करोड़ रुपये का खर्च था, लेकिन मौजूदा खर्च के लिए संशोधित अनुमान सिर्फ 215 करोड़ रुपये है, जो लगभग 69 प्रतिशत की भारी कमी है। अधिकारियों ने कहा कि आरई अनुमान यूनिफाइड डेटा हब प्रोजेक्ट सहित कई आइटी पहलों में कटौती दिखाते हैं, जिसके लिए 250 करोड़ दिए गए थे। परियोजना के लिए आरई को घटाकर छह करोड़ रुपये कर दिया गया है।

अस्पताल से एक महीने बाद घर लौटे सलीम वास्तिक

संस, जागरण, गाजियाबाद : इस्लामिक कुरीतियों के खिलाफ बोलने वाले सलीम वास्तिक एक महीने बाद रविवार को अस्पताल से उपचार कराने के बाद घर लौटे हैं। गले में गहरे घाव होने से वह अभी बोलने में असमर्थ हैं। घर पहुंचने के बाद पुलिस ने उनकी सुरक्षा में दो सुरक्षाकर्मी तैनात किए हैं। उन पर हमले के आरोपित सगे भाई पुलिस मुठभेड़ में पहले ही ढेर हो चुके हैं।

लोनी थाना क्षेत्र की निठौरा रोड की अली गार्डन कालोनी स्थित पूर्व मुस्लिम सलीम वास्तिक के कार्यालय में घुसकर हेलमेट पहने दो सगे भाई जीशान और गुलफाम ने 27 फरवरी को सर्जिकल ब्लेड से गला रेतकर कांच के टुकड़ों कमर और पेट पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। हमले के बाद करीब एक माह तक अस्पताल में रहे। एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि गले में हुए गहरे घाव से वह अभी भी बोल नहीं पा रहे हैं। स्वजन उनकी देखभाल में जुटे हैं। सलीम की सुरक्षा में दो गनर तैनात किए गए हैं।

स्कूटी चार्जिंग के दौरान मकान में लगी आग, दूसरी मंजिल से कूदने से बची चार की जान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

50 गज के मकान के भू-तल पर बनी पार्किंग में चार्जिंग पर लगी थी स्कूटी, बाहर जाने के रास्ते पर थी आग की लपटे

चांद बाग इलाके में मकान की पार्किंग में आग लगने उपर से कूदती महिला। वीडियो ग्रैब

चांदबाग क्षेत्र में शनिवार देर रात 50 गज के मकान की पार्किंग में स्कूटी चार्जिंग से मकान में आग लग गई। चार परिवार के आठ सदस्य ऊपरी मंजिल पर ही फंस गए। सीढ़ियों के जरिये धुआं ऊपरी मंजिल तक पहुंच गया। चार लोगों ने दूसरी मंजिल से गली में कूदकर जान बचाई। एक महिला दो साल के बच्चे को लेकर कूदी थी। गिरने से उन्हें मामूली चोट भी आई है।

घायल हालत में राशिदा (50), सोनी (25), निखत (22) व आसिफ (2) को स्थानीय लोगों ने जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती करवाया। दमकल ने मौके पर पहुंचकर घर में फंसे बाकी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। दमकल की 11 गाड़ियों ने डेढ़ घंटे में आग पर काबू पा लिया। दयालपुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। दमकल ने बताया कि शनिवार रात करीब डेढ़ बजे चांदबाग की गली नंबर-15 में 50 गज के मकान में बनी पार्किंग में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही दमकल की 11 गाड़ियां व एक स्काई लिफ्ट मौके पर पहुंची। दमकल के पहुंचने से पहले मकान में फंसी तीन महिलाएं एक बच्चे के साथ पहली मंजिल से नीचे कूद गई थी। बाकी चार लोग फंसे थे। उन्हें लिफ्ट से दमकल ने बाहर निकाला। किसी की जान नहीं गई। तीन बजे आग पर काबू पाया गया। पार्किंग में एक बाइक व स्कूटी जली हालत में मिली है।

बाहर भागने का रास्ता हो गया था बंद, पड़ोसियों ने चादर को बनाया जाल : इस मकान में चार फ्लैट बने हुए हैं। सभी फ्लैट में अलग-अलग परिवार रहते हैं। फ्लैट पर जाने का रास्ता पार्किंग से है। सीढ़ियों के पास स्कूटी चार्जिंग पर लगी हुई थी। पीड़ितों ने बताया कि शनिवार रात वह फ्लैट में सो रहे थे। धुएं से दम घुटने से आंख खुली।

धुआं ज्यादा होने पर आठ लोग फंस गए। शोर होने पर आसपास के लोग उठ गए और मदद के लिए आए। पड़ोसियों ने चादर को जाल बनाया। तीन महिलाओं ने दूसरी मंजिल से छलांग लगाई। एक महिला की गोद में छोटा बच्चा था। तीन लोग चादर पर गिरे।

रालेट एक्ट मामला

आज के ही दिन वर्ष 1919 को अंग्रेज सैनिकों की गोलियों से 50 लोग हुए थे बलिदान, बलिदानियों की याद में बनेगा बलिदान स्मारक, राष्ट्रपति से आज मिलेंगे स्पीकर विजेंद्र गुप्ता

जलियांवाला बाग से पहले दिल्ली में हुआ था नरसंहार

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा के इतिहास पर तैयार शताब्दी यात्रा —वीर विट्ठलभाई पटेल काफी टेबल बुक में गांधी जी की पुस्तक सत्य के प्रयोग से 30 मार्च 1919 के दिल्ली नरसंहार को लेकर लिए गए भाग को दिखाते विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता। जागरण

रालेट एक्ट के विरोध को लेकर जलियांवाला बाग से पहले दिल्ली में नरसंहार हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसके पहले 30 मार्च 1919 को दिल्ली में इस एक्ट के विरोध में आंदोलन कर रहे लोगों पर अंग्रेजों ने गोलियां चला दी थीं, इसमें 50 से अधिक लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हुए थे। इस आंदोलन का नेतृत्व स्वामी श्रद्धानंद कर रहे थे।

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता 30 मार्च 1919 के नरसंहार में बलिदान देने वालों को याद करने के लिए बलिदान स्मारक बनाए जाने का प्रयास कर रहे हैं। गुप्ता सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मिलेंगे और उन्हें दिल्ली विधानसभा के 100 साल के इतिहास पर उन्हें काफी टेबल बुक सौंपेंगे। इस बुक के पेज नंबर 167 पर महात्मा गांधी की पुस्तक 'सत्य के प्रयोग' के अंश प्रकाशित हैं, जिसमें गांधीजी ने 30 मार्च के दिल्ली नरसंहार का जिक्र किया है। 18 मार्च, 1919 में अंग्रेजों द्वारा दिल्ली विधानसभा यानी उस समय की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में लाए गए रालेट एक्ट के विरोध में बड़ा सत्याग्रह हुआ था, इसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। रालेट एक्ट में प्रविधान था कि अंग्रेजी हुकूमत किसी को भी बगैर किसी कारण दो साल तक जेल में रख सकती थी। गुप्ता राष्ट्रपति को 30 मार्च के ऐतिहासिक महत्व से अवगत कराएंगे। यह जानकारी भी एकत्रित कराई जा रही है कि इस नरसंहार में मबलिदानियों के नाम बलिदान स्मारक पर लिखे जा सकें। इससे पहले 1970 में 30 मार्च 1919 की 51वीं वर्षगांठ के अवसर पर डाक टिकट जारी हुआ था।

दिल्ली में उस दिन (30 मार्च, 1919) जैसी हड़ताल हुई, वैसी पहले कभी नहीं हुई थी। जान पड़ा हिंदू और मुसलमान एक दिल हो गए। स्वामी श्रद्धानंद को जामा मस्जिद में आने का निमंत्रण दिया गया और वहां उन्होंने भाषण दिया था। यह सब अधिकारियों के बर्दाश्त के बाहर था। रेलवे स्टेशन की ओर जाते जुलूस को पुलिस ने रोका और गोलियां चलाईं। कितने ही लोग जख्मी हुए, अनेक जान से मारे गए। जो कुछ बाद अमृतसर (13 अप्रैल, 1919) में भी यही हुआ।

- महात्मा गांधी की पुस्तक सत्य के प्रयोग से

नशे के लिए करने लगे दवाओं का धंधा, पांच गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक संगठित ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़ कर एक नाबालिग समेत चार आरोपितों को पकड़ा है। इनमें से एक पहले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था और अन्य आरोपित दवा के अलग-अलग धंधे से जुड़े हुए थे। सभी ने अधिक पैसे कमाने के लिए नशे में इस्तेमाल होने वाली दवाओं का अवैध कारोबार शुरू कर दिया। इनकी निशानदेही पर 3.5 करोड़ की 3.539 किग्रा अल्प्राजोलम टैबलेट व एक करोड़ की 1.709 किग्रा ट्रामाडोल टैबलेट व कैप्सूल बरामद की गई है।

डीसीपी राहुल अलवाल ने बताया कि खुफिया जानकारी पर क्राइम ब्रांच की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने दिल्ली समेत एनसीआर में सक्रिय इस कार्टेल का भंडाफोड़ किया है।

दिल्ली शहर नही कहानियों का एक अनंत समंदर है: शेखर कपूर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

शेखर कपूर। फिल्म निर्माता

दिल्ली केवल एक शहर नहीं बल्कि कहानियों का एक अनंत समंदर है। यहां की हर दीवार और हर झरोखा एक नई पटकथा लिखने का हौसला देता है। ये भावुक शब्द प्रसिद्ध फिल्मकार शेखर कपूर ने रविवार को अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली में आयोजित एक विशेष सत्र में कही। उन्होंने दिल्ली के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि यहां की सांस्कृतिक विरासत और यहां के दर्शकों की सिनेमाई समझ वैश्विक स्तर की है, जो किसी भी फिल्म निर्माता के लिए एक प्रेरक ऊर्जा का काम करती है।

निर्देशक का दृष्टिकोण ही फिल्म की पहचान : उन्होंने फिल्म निर्माण की प्रकृति पर भी अनुभव साझा किया। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि हर फिल्म की अपनी एक अलग रूह और विशेषताएं होती हैं, लेकिन निर्देशक का दृष्टिकोण ही फिल्म की दृश्य, पहचान और उसके कथात्मक स्वरूप को आकार देता है। उनके अनुसार तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो जाए, एक फिल्म की सफलता उसकी मूल संवेदना और निर्देशक की स्पष्ट सोच पर ही आधारित होती है।

पूरी तरह से पटरी पर आएंगे भारत और बांग्लादेश के आपसी संबंध

संकेत ▶ अप्रैल में विदेश मंत्री का भारत दौरा संभावित, भावी संबंधों का तय होगा रोडमैप

पूर्व हसीना सरकार व भारत के बीच हुए समझौते को भी आगे बढ़ाने पर होगी बात

जयप्रकाश रंजन • जागरण

- सात से नौ अप्रैल के बीच हो सकती है यात्रा

भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त एम. रियाज हमीदुल्ला केंद्रीय पीयूष गोयल से मुलाकात करते हुए। फाइल >>

नई दिल्ली : बीएनपी नेता तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद से ही भारत और बांग्लादेश के संबंधों में तनाव खत्म होने लगे थे और अब संकेत हैं कि दोनों तरफ की सरकारें आपसी संबंधों को पूरी तरह से सामान्य बनाने को तैयार हैं। ढाका की नई सरकार को इस बात से भी कोई गुरेज नहीं है कि वर्ष 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे के दौरान किए गए दोनों देशों के बीच कुछ प्रमुख समझौतों को अब नए सिरे से आगे बढ़ाया जाए। खासतौर पर मुक्त व्यापार समझौते यानी कांप्रीहेंसिव इकोनामिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (सीपा) पर चर्चा शुरू की जाए। इस बारे में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने ढाका में नई सरकार के प्रतिनिधियों से बात की है जबकि बांग्लादेश के उच्चायुक्त एम.रियाज हमीदुल्लाह ने नई दिल्ली में वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक में इस मुद्दे को उठाया है।

भारत और बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान के अगले महीने के शुरुआत में नई दिल्ली आने की तैयारी कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान के भारत आने की संभावना है लेकिन इसका बारे में उचित समय पर घोषणा की जाएगी। जानकारों का कहना है कि यह यात्रा 7-9 अप्रैल के बीच होने की संभावना है। यह नई बांग्लादेशी सरकार के गठन के बाद विदेश मंत्री रहमान का भी पहला उच्चस्तरीय दौरा होगा। इस दौरान गंगा जल संधि के नवीनीकरण, ऊर्जा संकट और व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की होने वाली बैठक में आपसी सहयोग से जुड़े मुद्दे ही प्राथमिकता में होंगे। मोदी और हसीना के बीच हुई बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में दोनों पक्षों ने सीपा की वार्ता जितनी जल्दी हो सके शुरू करने की इच्छा व्यक्त की थी। कूटनीतिक सूत्रों का कहना है कि बांग्लादेश के साथ कारोबारी समझौते को लेकर भारत की सोच में कोई बदलाव नहीं आया है। वैश्विक अस्थिरता को देखते हुए बांग्लादेश ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने को लेकर ज्यादा उत्सुक है। पश्चिम एशिया विवाद शुरू होने के बाद भारत ने बांग्लादेश को 5,000 टन डीजल की आपूर्ति की है।

कूटनीतिक सूत्र इस बात की तरफ ध्यान दिलाते हैं कि किस तरह से तारिक रहमान सरकार ने सत्ता संभालने के बाद भारत के खिलाफ कोई चुभने वाला बयान नहीं दिया है जैसा की अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में हो रहा था। यह दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास का संकेत है। वहीं, भारत में शरण लिए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की ओर से किसी भारतीय मीडिया को कोई नया साक्षात्कार नहीं दिया गया है। तारिक रहमान की सरकार की एक प्रमुख चिंता यह है कि शेख हसीना मीडिया के जरिये बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर सकती हैं। पूर्व में शेख हसीना के बयानों को लेकर बांग्लादेश में काफी प्रतिक्रिया हो रही थी।

आज बिहार विधानमंडल से त्यागपत्र देंगे नीतीश और नितिन नवीन

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना

नीतीश कुमार। फाइल

- फिलहाल विधानपरिषद के सदस्य हैं मुख्यमंत्री व विधानसभा सदस्य हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष
- इसी महीने की 16 तारीख को राज्यसभा के लिए चुने गए हैं दोनों

नितिन नवीन। फाइल

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सोमवार को क्रमशः विधान परिषद और विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देंगे। मुख्यमंत्री विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह से मिलकर स्वयं उन्हें अपना इस्तीफा सौंपेंगे। वहीं, अभी यह तय नहीं हुआ है कि नितिन नवीन सदेह उपस्थित होकर त्यागपत्र देंगे या उनका हस्ताक्षरित त्यागपत्र भाजपा के कोई वरिष्ठ नेता विधानसभा अध्यक्ष डा. प्रेम कुमार को सौंपेंगे। दोनों ही बीते 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार संसद के किसी सदन के लिए निर्वाचित होने के 14 दिनों के अंदर उन्हें राज्य विधानमंडल के उस सदन से इस्तीफा देना होता है, जहां के वे सदस्य हैं। इसलिए, वैधानिक प्रविधान के तहत नीतीश कुमार को विधान परिषद से इस्तीफा देना है। नीतीश 10 अप्रैल को राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले सकते हैं।

विदित हो कि बिहार विधान परिषद में नीतीश कुमार का यह चौथा कार्यकाल है। उनका वर्तमान कार्यकाल 2030 में खत्म होने वाला था। इस बीच मोकामा (पटना) के विधायक अनंत सिंह भी मुख्यमंत्री से मिले। बाद में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि कई लोगों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वह इस्तीफा नहीं दें, पर वह नहीं माने।

रविवार की सुबह नितिन की प्रतीक्षा करते रहे विधानसभा अध्यक्ष : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2025 के विधानसभा चुनाव में पटना जिले के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुने गए थे। संवैधानिक प्रविधान के अनुसार अगर वे 30 मार्च को त्याग पत्र नहीं देते हैं तो राज्यसभा के लिए हुआ उनका निर्वाचन वैध नहीं रह जाएगा। वैसे, नितिन नवीन के विधानसभा से त्यागपत्र को लेकर रविवार को दिनभर चर्चा होती रही। विधानसभा अध्यक्ष भी रविवार की सुबह साढ़े आठ बजे अपने कक्ष में पहुंच गए थे। उनके मुताबिक शनिवार को वे नई दिल्ली में थे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने सूचित किया था कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविवार की सुबह विस की सदस्यता से त्यागपत्र देंगे। बाद में सूचना मिली कि नितिन नवीन अपरिहार्य कारणों से बाहर चले गए हैं। अब वे सोमवार को त्यागपत्र देंगे। नितिन नवीन की प्रतीक्षा के बाद विधानसभा अध्यक्ष रविवार को फिर नई दिल्ली के लिए निकल गए। बाद में वे पटना लौट आए। इधर, भाजपा सूत्रों ने बताया कि भाजपा के कोई वरिष्ठ नेता उनका त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेंगे। विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली में यह प्रविधान नहीं है कि त्यागपत्र देने के लिए सदस्य का उपस्थित होना जरूरी है। विधानसभा अध्यक्ष यदि सहमत होते हैं कि संबंधित सदस्य का त्यागपत्र सही है और इसे बिना किसी भय का दबाव के दिया जा रहा है, प्रतिनिधि से प्राप्त त्यागपत्र को वे स्वीकार कर सकते हैं।

उड़ानों में 20 अप्रैल से बिना अतिरिक्त शुल्क के मिलेंगी 60 प्रतिशत सीटें

- एयरलाइन कंपनियों को पारदर्शी सीट आवंटन नीति भी बनानी होगी
- इस संबंध में डीजीसीए ने 20 मार्च को जारी किया है एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर

नई दिल्ली, प्रेट्र : एयरलाइन कंपनियां 20 अप्रैल से किसी भी उड़ान में कम से कम 60 प्रतिशत सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराना शुरू कर देंगी। इसके साथ ही एयरलाइन कंपनियां पारदर्शी सीट आवंटन नीति भी बनाएंगी। मौजूदा व्यवस्था में केवल करीब 20 प्रतिशत सीटें ही बिना शुल्क के उपलब्ध होती हैं, जबकि बाकी सीटों के चयन के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है।

नागर विमानन मंत्रालय ने 18 मार्च को बताया था कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के माध्यम से एयरलाइनों को यात्री सुविधाएं बढ़ाने के लिए कई अहम निर्देश जारी किए गए हैं। डीजीसीए को निर्देश दिए गए हैं कि वह एयरलाइंस को किसी भी उड़ान में कम से कम 60 प्रतिशत सीटें मुफ्त चयन के लिए आवंटित करने का निर्देश दे। इस संबंध में डीजीसीए ने 20 मार्च को संशोधित एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर जारी किया। डीजीसीए के अधिकारी ने बताया कि यह सर्कुलर 20 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा।

सर्कुलर के अनुसार एयरलाइंस को अपने बुकिंग इंटरफेस पर खाली सीटों की उपलब्धता और शर्तों के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही एक ही पीएनआर पर यात्रा करने वाले यात्रियों, खासकर परिवार के सदस्यों को साथ बैठाने के लिए भी कहा गया है। एयरलाइंस नए निर्देश को लागू करने की तैयारी कर रही हैं।

सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि खेल उपकरण या संगीत वाद्ययंत्रों से संबंधित वैकल्पिक सेवाओं के लिए सभी प्रासंगिक शुल्क, क्षति की स्थिति में किसी भी दायित्व की शर्तों सहित, एयरलाइन वेबसाइटों और बुकिंग प्लेटफार्मों पर पारदर्शी और स्पष्ट तरीके से प्रदर्शित किए जाने चाहिए। डीजीसीए ने कहा है कि यह सर्कुलर जारी होने की तारीख से 30 दिनों के बाद प्रभावी होगा। इस तरह के नए प्रविधानों से यात्रियों की यात्रा और सुखद और आरामदेह हो सकेगी।

केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार बोले, नशा मुक्त भारत अभियान का हो विस्तार

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने रविवार को नशा रोकने के प्रयासों को तेज करने, नशा मुक्ति सेवाओं का विस्तार करने और नशा मुक्त भारत अभियान को व्यापक बनाने का आह्वान किया।

वीरेंद्र कुमार ने यहां डा. आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में आयोजित 'नशा मुक्ति और पुनर्वास पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति' की पांचवीं बैठक की अध्यक्षता की। इसमें राज्यमंत्री बीएल वर्मा, सामाजिक न्याय सचिव सुधांश पंत, वरिष्ठ अधिकारियों, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों, एनजीओ और अन्य हितधारकों ने भाग लिया। उप-महानिदेशक प्रतिमा गुप्ता ने एजेंडे के खास बिंदुओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। वीरेंद्र कुमार ने सदस्यों से आग्रह किया कि वे ड्रग्स की मांग में कमी लाने जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर अपने विचार, सुझाव और प्रतिक्रिया सक्रिय रूप से एवं नियमित तौर पर साझा करें। चर्चा का मुख्य केंद्र नशा रोकने के उपायों को तेज करना था।

'भारत-अमेरिका सुरक्षा सहयोग भविष्य की रणनीतिक साझेदारी का मुख्य स्तंभ'

नई दिल्ली, प्रेट्र : अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भारत और अमेरिका के बीच 'दोनों पक्षों के लिए लाभकारी' आर्थिक विकास और सुरक्षा सहयोग को भविष्य की रणनीतिक साझेदारी का मुख्य स्तंभ बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और विशाल बुनियादी ढांचे की जरूरतें, ऊर्जा और डिजिटल क्षेत्र में अमेरिकी विशेषज्ञता के साथ पूरी तरह मेल खाती हैं।

आर्थिक एकीकरण और सप्लाई चेन : एक प्रतिष्ठित पत्रिका को दिए साक्षात्कार में राजदूत गोर ने कहा, दोनों देश सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए लचीली सप्लाई चेन बनाने को प्राथमिकता दे रहे हैं।

उन्होंने चीन से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच सुरक्षित नेटवर्क के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली 'पैक्स सिलिका' पहल में भारत के शामिल होने का स्वागत किया। गोर ने जोर देकर कहा कि अमेरिका, दक्षिण और मध्य एशिया में आर्थिक विकास के "मुख्य सूत्रधार" के रूप में कार्य करने की स्थिति में है और प्रस्तावित व्यापार समझौता क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए एक शक्तिशाली आधार बनेगा।

सहयोग क नई दिशा

- अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने 'पारस्परिक लाभ' वाले आर्थिक विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की
- दोनों देश सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिजों के लिए लचीली सप्लाई चेन बनाने को तरजीह दे रहे

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर। फाइल

रक्षा सहयोग : रणनीतिक साझेदारी की धुरी

रक्षा और सुरक्षा सहयोग को इस साझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बताते हुए राजदूत ने कहा कि 'क्वाड' के माध्यम से दोनों देशों के सुरक्षा हित मजबूती से जुड़े हुए हैं। उन्होंने मालाबार, टाइगर ट्रायम्फ और कोप इंडिया जैसे सैन्य अभ्यासों का जिक्र करते हुए सैन्य इंटर-आपरेबिलिटी बढ़ाने पर बल दिया। उनके अनुसार, भारत अमेरिका का एक प्रमुख रक्षा भागीदार है, और सैन्य बिक्री व कूटनीति इस रिश्ते के चमकते हुए बिंदु हैं। सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि एक-दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए दोनों देश आतंकवाद, कट्टरवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राजदूत ने अपने विजन को साझा करते हुए कहा कि वे भारत-अमेरिका संबंधों को 21वीं सदी की ऐसी परिभाषित रणनीतिक साझेदारी में बदलना चाहते हैं, जो दोनों देशों के लिए वास्तविक और ठोस लाभ सुनिश्चित करे।

विदित हो कि विगत कुछ महीनों में अमेरिका का साथ कारोबारी समझौते की बात आगे बढ़ी है।

हिमाचल में 15 मई के बाद तीन चरण में हो सकता है पंचायत चुनाव

राज्य ब्यूरो, जागरण • शिमला : हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग 15 मई के बाद स्थानीय शहरी निकायों के चुनाव करवाने की तैयारी में है। इसके लिए शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। सूत्रों की मानें तो पंचायत चुनाव तीन, जबकि शहरी निकायों के चुनाव एक ही चरण में करवाने पर विचार हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने समय पर चुनाव करवाने के लिए पंचायती राज विभाग को 31 मार्च से पहले आरक्षण रोस्टर जारी करने के निर्देश दिए हैं।

शहरी निकायों के आरक्षण रोस्टर को लेकर भी पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं। आरक्षण रोस्टर के जारी होने के बाद चुनाव करवाने का रास्ता साफ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को 31 मई से पहले स्थानीय निकाय चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 3,773 पंचायतें बन गई हैं। हालांकि सात पंचायतों से संबंधित मामले प्रदेश हाई कोर्ट में पहुंचे हैं। इसके अलावा और मामलों के कोर्ट में आने की सूचना है। प्रदेश हाई कोर्ट में सोमवार को पंचायतों के गठन को लेकर सुनवाई होनी है।

जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से लड़ने के लिए भारत ने शुरू किया नया योग प्रोटोकाल

- योग को सरल और सुलभ तरीके से दैनिक जीवन से जोड़ने की कवायद
- देश में गैर-संक्रामक बीमारियों में चिंताजनक रूप से देखी जा रही वृद्धि

भुवनेश्वर के एक पार्क में शुक्रवार सुबह योग करते लोग। फाइल/प्रेट्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : आयुष मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गैर-संक्रामक बीमारियों और जोखिम वाले समूहों के लिए एक व्यापक 'योग प्रोटोकाल' शुरू किया है। इस महीने की शुरुआत में योग महोत्सव 2026 के दौरान आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव द्वारा शुरू की गई इस पहल को जीवनशैली से जुड़ी विभिन्न बीमारियों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में देखा जा रहा है।

यह पहल आयुष मंत्रालय के अधीन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन के पारंपरिक चिकित्सा सहयोगी केंद्र द्वारा विकसित की गई है। यह प्रोटोकाल साक्ष्य-आधारित माड्यूल के रूप में तैयार किया गया है, जो यौगिक अभ्यासों को सरल और सुलभ तरीके से दैनिक जीवन में एकीकृत करता है।

संस्थान के एक अधिकारी ने बताया कि भारत में आज मधुमेह, हाइपरटेंशन, हृदय रोग, श्वसन संबंधी बीमारियां और मानसिक स्वास्थ्य विकार जैसी गैर-संक्रामक बीमारियों में चिंताजनक वृद्धि देखी जा रही है। हाल के अनुमानों के अनुसार, देश में होने वाली लगभग दो-तिहाई मौतें इन्हीं बीमारियों के कारण होती हैं। यह जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों की ओर एक स्पष्ट बदलाव का संकेत देती है।

अधिकारी ने बताया कि गैर-संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु दर में प्रतिवर्ष हो रही वृद्धि को देखते हुए निवारक उपायों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। इसी संदर्भ में नए योग प्रोटोकाल का महत्व बढ़ गया है।

वैज्ञानिक प्रमाणों और नैदानिक दृष्टिकोण पर आधारित यह माड्यूल 30 से 60 मिनट के दैनिक सत्र की सिफारिश करता है, जिसमें आसन, प्राणायाम, ध्यान और विश्राम तकनीकें शामिल हैं। इसे विभिन्न फिटनेस स्तरों और स्वास्थ्य स्थितियों के अनुरूप बनाया गया है।

एक अन्य आधिकारी ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य योग को स्वास्थ्य और कल्याण के लिए जीवनभर का साथी बनाना है। इसमें छोटे बच्चों के लिए मनोरंजक योग माड्यूल से लेकर किशोरों के लिए मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित दिनचर्या, बुजुर्गों के लिए गतिशीलता बढ़ाने वाले अभ्यास और महिलाओं और गर्भवती माताओं के लिए विशेष दिशानिर्देश शामिल हैं।

एनजीटी ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव से मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, देहरादून : पर्यावरणीय और भौगोलिक रूप से संवेदनशील पहाड़ों की रानी मसूरी में बढ़ते दबाव और सरकारी स्तर पर कथित निष्क्रियता को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सख्त रुख अपनाया है। ट्रिब्यूनल ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर विस्तृत शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें मसूरी में दबाव कम करने के लिए अब तक उठाए गए कदमों की पूरी जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिवक्ता से भी जवाब मांगा गया है।

मसूरी की स्थिति की तुलना वर्ष 2023 में चमोली जिले के जोशीमठ में आए भू-धंसाव के गंभीर संकट से की गई है। जोशीमठ में अनियंत्रित निर्माण और अत्यधिक पर्यटन दबाव के कारण जमीन धंसने की समस्या उत्पन्न हुई थी। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो मसूरी में भी जोशीमठ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

दिव्यांगजनों की तर्ज पर बुजुर्गों के लिए भी एक नया विभाग बनाने की सिफारिश

अरविंद पांडेय • जागरण

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति ने की है यह सिफारिश
- देश में दिव्यांगजनों की आबादी 2.5 करोड़, जबकि बुजुर्गों की संख्या करीब 15 करोड़

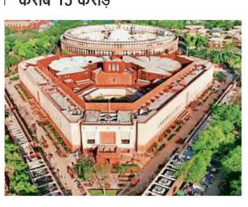

नई दिल्ली : देश में बुजुर्गों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से जुड़ी एक संसदीय समिति ने भी अब दिव्यांगजनों की तर्ज पर बुजुर्गों के लिए एक नया विभाग बनाने की सिफारिश की है। समिति का मानना है कि मौजूदा समय में मंत्रालय के पास बुजुर्गों के जुड़े मामलों को देखने के लिए जो तंत्र है, वह उनसे जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बुजुर्गों से जुड़े संगठन पहले से ही सरकार से बुजुर्गों के लिए नया विभाग बनाने की मांग कर रहे हैं।

भाजपा सांसद पीसी मोहन की अध्यक्षता वाली सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के मुताबिक, दिव्यांगजनों से जुड़ी समस्याओं से बेहतर ढंग से निपटने के लिए जैसे सरकार ने नए विभाग का गठन किया था, वैसे ही बुजुर्गों के लिए भी नया विभाग बनाने की जरूरत है। वैसे भी देश में दिव्यांगजनों की मौजूदा आबादी 2.5 करोड़ ही है, जबकि बुजुर्गों की आबादी करीब 15 करोड़ है। माता-पिता व वरिष्ठजनों के भरण-पोषण एवं देखभाल से जुड़ा प्रस्तावित विधेयक पारित होने के बाद बुजुर्गों से जुड़ी गतिविधियां और बढ़ेंगी। ऐसे में उनके लिए एक अलग विभाग जरूरी है।

वृद्धाश्रमों के संचालन में राज्य भी बंटाएंगे हाथ : वृद्धाश्रमों के संचालन पर संसदीय समिति की ओर से खड़े गए सवालों पर मंत्रालय ने कहा है कि करीब आठ सौ वृद्धाश्रमों को केंद्र के जरिये गैरसरकारी संगठनों के साथ मिलकर संचालित करने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में वह राज्य सरकारों से इसमें शामिल होने पर चर्चा कर रहे हैं। अधिकांश राज्य सहमत हैं। जल्द ही राज्यों के साथ मिलकर वृद्धाश्रमों के बेहतर संचालन पर एक मानक प्रक्रिया तय की जाएगी।

2050 तक देश में बुजुर्गों की आबादी हो जाएगी 35 करोड़ : एक रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा समय में देश में बुजुर्गों की आबादी लगभग 15 करोड़ है, जो 2050 तक लगभग 35 करोड़ होने की संभावना है। यानी 2050 तक उनकी आबादी देश की कुल आबादी में 20 प्रतिशत तक हो जाएगी। इतना ही नहीं, 2046 तक देश में बुजुर्गों की संख्या 15 वर्ष तक के बच्चों की आबादी से अधिक होने का अनुमान है।

बदलाव

बिल सी-12 लागू, एक साल और 14 दिन की समय-सीमा में किया बदलाव, एक साल में 32 हजार भारतीयों ने मांगी राजनीतिक शरण

कनाडा ने सख्त किए शरण नियम, भारतीयों के दावों पर पड़ेगा बड़ा असर

रोहित कुमार • जागरण

चंडीगढ़: कनाडा में 2025 के पहले छह महीनों में भारत के करीब 9,770 लोगों ने शरण मांगी है। इनमें बड़ी संख्या पंजाब से जुड़े मामलों की बताई जा रही है। इसी बीच कनाडा सरकार ने शरण नियमों को सख्त करते हुए नया कानून बिल सी-12 लागू कर दिया है, जिसके तहत एक साल से अधिक देरी से किए गए दावों और अनियमित तरीके से सीमा पार कर 14 दिन के भीतर आवेदन न करने वालों को पूरी सुनवाई का मौका नहीं मिलेगा।

कनाडा सरकार की ओर से लागू 'स्ट्रेंथनिंग कनाडा इमिग्रेशन सिस्टम एंड बार्डर्स एक्ट' को 26 मार्च को शाही मंजूरी (रायल असेंट) मिलने के बाद प्रभावी कर दिया गया है।

सरकार का कहना है कि नया कानून सीमा सुरक्षा को मजबूत करेगा, संगठित अपराध पर अंकुश लगाएगा और इमिग्रेशन सिस्टम को निष्पक्ष व प्रभावी बनाएगा। हालांकि, इसके कई प्रविधानों को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है।

प्रतीकात्मक

समय-सीमा में बड़ा बदलाव

नए कानून का सबसे बड़ा असर समय-सीमा से जुड़े नियमों पर पड़ेगा। ये नियम तीन जून 2025 या उसके बाद किए गए दावों पर लागू होंगे। यदि कोई व्यक्ति कनाडा में प्रवेश के एक साल से अधिक समय बाद शरण का दावा करता है, तो उसका मामला इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड (आइआरबी) में सुनवाई के लिए नहीं भेजा जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक साल की अवधि दोबारा प्रवेश करने पर भी रीसेट नहीं होगी। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति अमेरिका से कनाडा में आधिकारिक सीमा चौकियों के बजाय अनियमित तरीके से प्रवेश करता है और 14 दिनों के भीतर शरण का दावा नहीं करता तो उसे भी पूर्ण सुनवाई का अवसर नहीं मिलेगा।

पंजाब मूल के लोगों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर, वर्क परमिट खत्म होने पर मांगते हैं राजनीतिक शरण

एसोसिएशन आफ कंसलटेंट आफ ओवरसीज स्टडीज के अनुमान के मुताबिक, वर्ष जनवरी 2024 से एक जनवरी 2025 तक 32 हजार भारतीयों ने कनाडा में राजनीतिक शरण मांगी। वर्ष 2025 जनवरी से जून तक 9,770 भारतीयों ने राजनीतिक शरण मांगी। इनमें भी 80 प्रतिशत पंजाबी थे। एसोसिएशन के सचिव सुखविंदर नंदरा ने बताया कि राजनीतिक शरण मांगने वालों में स्टूडेंट वीजा पर कनाडा गए वे छात्र होते हैं, जिनका वर्क परमिट खत्म हो गया होता है। ऐसे में कनाडा में ही रहने के लिए वे राजनीतिक शरण के आवेदन करते हैं। इसी तरह विजिटर वीजा वाले लोग भी वहां रहने के लिए राजनीतिक शरण मांगते हैं। नंदरा ने कहा कि नए नियम का असर भी सबसे ज्यादा पंजाब मूल के लोगों पर पड़ेगा।

कनाडियन काउंसिल फार रिफ्यूजीज का कहना है कि यह कानून शरणार्थियों की सुरक्षा को कमजोर करता है और अंतरराष्ट्रीय नियमों व कनाडा के चार्टर के तहत किए गए वादों का उल्लंघन कर सकता है।

कह कर रहेंगे माधव जोशी

42 लाख विचाराधीन मतदाताओं का मामले बंगाल में निपटाए गए। 18 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर किए गए हैं।

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार, 30 मार्च, 2026
www.jagran.com

एलडीएफ और यूडीएफ लुटेरे, केरलम में राजग बनाएगा अगली सरकार : मोदी

चुनावी रैली ▶ कहा-राज्य में एक अलग ही माहौल है, जो बदलाव का संदेश दे रहा है

पलक्कड़, प्रेट्र : केरलम विधानसभा चुनाव से पहले रविवार को एक हाई वोल्टेज रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने माकपा के नेतृत्व वाले एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ पर राज्य को लूटने का आरोप लगाया। भाजपा के गठन के बाद से चुनावी सूखे का सामना कर रहे पार्टी कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास जगाते हुए मोदी ने कहा कि केरलम में अगली सरकार राजग बनाएगा। केरलम की जनता के आशीर्वाद और आप सभी के समर्थन से हम यहां सरकार बनाएंगे और सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

पीएम ने आरोप लगाया कि एलडीएफ और यूडीएफ बारी-बारी से सत्ता में आकर राज्य को लूटते रहे हैं। इन दोनों के बीच एक व्यावहारिक समझौता रहा है। कुछ वर्षों तक एलडीएफ सरकार चलाता है और अपनी जेबें भरता है। इसके बाद यूडीएफ आता है और लूट जारी रखता है। इस व्यवस्था में केरलम फंसा हुआ है। एएनआइ के अनुसार, प्रधानमंत्री ने कहा कि एलडीएफ और यूडीएफ की सभी नीतियां सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए हैं। एक तरफ एलडीएफ, दूसरी तरफ यूडीएफ, एक तरफ कम्युनिस्ट, दूसरी तरफ कांग्रेस, एक भ्रष्ट, दूसरा अत्यधिक भ्रष्ट, एक सांप्रदायिक, दूसरा अत्यधिक सांप्रदायिक। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें राज्य में बदलते राजनीतिक माहौल का आभास हो रहा है। यह भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के लिए बढ़ते समर्थन का संकेत है। राज्य में एक अलग ही माहौल है, जो बदलाव का संदेश दे रहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केरलम के पलक्कड़ में एक जनसभा के दौरान 'चेंडा' बजा रहे हैं। 'चेंडा' केरलम का एक पारंपरिक बेलनाकार वाद्य यंत्र है। प्रेट्र

कांग्रेस नेताओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला उठाया : पीएम मोदी ने कांग्रेस के पूर्व नेताओं से जुड़े यौन उत्पीड़न का मुद्दा भी उठाया। 2024 में कांग्रेस के टिकट पर उपचुनाव जीतने वाले पलक्कड़ सीट से मौजूदा विधायक राहुल ममकुटाथिल और पार्टी के नगर पार्षद प्रशोब सी वालसन से जुड़े यौन उत्पीड़न के मामलों का संदर्भ देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि केरलम की महिलाओं को इससे सावधान रहने की जरूरत है।

एएनआइ के अनुसार, प्रधानमंत्री ने सकेरलम की पारंपरिक शैली को अपनाया, जिसमें सफेद मुंडू (धोती) के साथ कुर्ता पहना। उन्होंने केरलम की सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव सुनिश्चित करते हुए चेंडा (पारंपरिक ढोल) बजाया।

केरलम में आइयूएमएल नेता पर यूएई की यात्रा का लालच देने पर केस

मलप्पुरम, प्रेट्र : केरलम में आसन्न विधानसभा चुनाव के बीच थवनूर निर्वाचन क्षेत्र में यूडीएफ उम्मीदवार को सबसे अधिक मत दिलाने वाले बूथ समिति के सदस्यों को विदेशी यात्रा का लालच देने पर आइयूएमएल के एक नेता के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि यह मामला आइयूएमएल के प्रदेश उपाध्यक्ष बावा हाजी के खिलाफ दर्ज किया गया है, जो मलप्पुरम के मंगलम से हैं। 22 मार्च को आयोजित एक सम्मेलन के दौरान हाजी ने कांग्रेस नेता वीएस जाय के लिए प्रचार करते हुए यूडीएफ बूथ समिति के सदस्यों के लिए 15 दिन की यूएई यात्रा की घोषणा की, जो अधिकतम मत प्राप्त करती है। इस मामले की पहली सूचना एलडीएफ प्रतिनिधियों द्वारा चुनाव आयोग को दी गई थी। जांच के बाद आयोग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन पाया। आयोग के निर्देश के आधार पर तिरुर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और प्रतिनिधित्व अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। हाजी को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि सम्मेलन का वीडियो फुटेज भी बरामद किया गया है, जिसमें आइयूएमएल नेता ने यह पेशकश की थी।

केरलम में सतर्क कांग्रेस हाईकमान ने पूरी तरह थामी गुटबाजी

- शीर्ष नेतृत्व ने के.सुधाकरण की नाराजगी दूर की, जिले के नेताओं को साध रहे वेणुगोपाल
- शशि थरूर, सतीशन, चेन्निथेला, सुधाकरण से मुरलीधरन के एकजुट होने के पीछे राहुल गांधी की रणनीति

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पार्टी नेता राहुल गांधी तथा केसी वेणुगोपाल से शुक्रवार को नई दिल्ली में के. सुधाकरण ने अपने परिवारजनों के साथ मुलाकात की। फाइल/प्रेट्र

संजय मिश्र • जागरण

नई दिल्ली: केरलम के विधानसभा चुनाव में 2021 में हुई चूक से सबक लेते हुए कांग्रेस हाईकमान ने इस बार सूबे के शीर्ष नेताओं के बीच गुटबाजी को लगभग पूरी तरह थाम लिया है। इस कड़ी में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात के बाद सूबे के वरिष्ठ लोकसभा सांसद के.सुधाकरण का पार्टी के चुनाव अभियान में पूरी शिद्दत से शामिल होने का एलान कांग्रेस नेतृत्व के लिए राहत भरा है। वाम दलों के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार के आक्रामक चुनावी अभियान को देखते हुए चुनाव के दौरान केरलम कांग्रेस की एकजुटता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए अहम चुनौती थी। इसमें संदेह नहीं कि चाहे के सुधाकरण हों या तेजतर्रार सांसद शशि थरूर, वीडी सतीशन, रमेश चेन्निथेला से लेकर के मुरलीधरन जैसे नेताओं को एकजुट करने की इस पहल में राहुल गांधी ने सबसे अहम सक्रिय भूमिका निभाई है।

विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं देने से नाराज सुधाकरण को साधने की पहल इसका ताजा प्रमाण है। कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन के सत्ता में आने की संभावनाओं को देखते हुए स्वाभाविक रूप से केरलम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्य के नेतृत्व के लिए अपनी दावेदारी ठोकने का मौका गंवाना नहीं चाहते। इसके मद्देनजर सुधाकरण समेत कुछ अन्य लोकसभा सांसद विधानसभा चुनाव लड़ने का दबाव बना रहे थे, मगर हाईकमान ने सांसदों को विधानसभा टिकट नहीं देने का सैद्धांतिक फैसला कर इन सबकी राह रोक दी। इससे नाराज सुधाकरण कांग्रेस के चुनाव कार्यक्रमों में शरीक नहीं हो रहे थे। कभी वामपंथी दलों का गढ़ रहे कन्नूर और आसपास के जिले में कांग्रेस को ताकतवर बनाने में सुधाकरण की बड़ी भूमिका रही है और उनका प्रभाव भी है। इसलिए कोई जोखिम नहीं लेते हुए राहुल गांधी ने सीधे सुधाकरण को फोन कर शनिवार को दिल्ली बुलाया। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के अस्पताल में भर्ती होने के कारण राहुल केरलम के चुनावी दौरे अभी नहीं कर पा रहे। मल्लिकार्जुन खरगे के साथ उनके आवास पर सुधाकरण की बैठक हुई जिसमें राहुल गांधी व कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी शामिल हुए और उन्हें चुनाव में सक्रिय रूप से जुटने के लिए राजी कर लिया गया। राहुल गांधी ने सुधाकरण और उनके परिवार संग हुई मुलाकात की तस्वीरें एक्स पर साझा कर उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि के.सुधाकरण ने केरलम की जनता के लिए संघर्ष करते हुए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। केरलम कांग्रेस की इस एकजुटता से उत्साहित राहुल गांधी ने इसी पोस्ट में यूडीएफ के केरलम में 100 सीटों के साथ एक जबर्दस्त जीत की ओर बढ़ने का दावा करने से गुरेज नहीं किया।

केरलम का चुनावी मिजाज बीते कई दशकों से हर पांच साल में सत्ता बदलने का रहा था, मगर 2021 में एलडीएफ ने लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल कर सबको हैरान कर दिया था और यूडीएफ की पराजय की सबसे बड़ी वजह कांग्रेस की गुटबाजी को माना गया था। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कई राज्यों के चुनाव में मिली मात को देखते हुए पार्टी हाईकमान केरलम को लेकर इसीलिए सतर्क है और तभी कुछ महीने पहले राहुल गांधी और खरगे ने कांग्रेस की लाइन-लेंथ से इतर चल रहे शशि थरूर को बुलाकर दो घंटे बातचीत कर उनकी नाराजगी दूर की। इसी तरह केरलम में नेता विपक्ष वीडी सतीशन हों या वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथेला दोनों मुख्यमंत्री पद के लिए उछाले जाने पर कह रहे थे कि कांग्रेस नेतृत्व चुनाव बाद इसका फैसला करेगा। हाईकमान ने जहां सूबे के शीर्ष नेताओं को साध लिया है, वहीं केसी वेणुगोपाल जिला स्तर पर टिकट बंटवारे के बाद स्थानीय नेताओं के असंतोष को थामने में जुटे हैं।

तमिलनाडु में टीवीके सभी सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव

चेन्नई, प्रेट्र : अभिनेता से राजनेता बने विजय ने तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए रविवार को सभी 234 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। वह खुद दो सीटों से चुनाव लड़ेंगे। इनमें पेरंबूर और तिरुचिरापल्ली (पूर्वी) शामिल हैं।

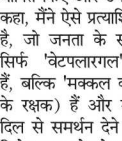

विजय ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में दोनों सीटों से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। साथ ही शेष सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित किए और उनका परिचय कराया। कहा, मैंने ऐसे प्रत्याशियों का चयन किया है, जो जनता के साथ खड़े रहेंगे। वे सिर्फ 'वेटपलारगल' (उम्मीदवार) नहीं हैं, बल्कि 'मक्कल कप्पलार्गल' (जनता के रक्षक) हैं और मतदाताओं से उन्हें दिल से समर्थन देने का आग्रह किया। विशेष रूप से जेन जी मतदाताओं से पार्टी के पक्ष में मतदान करने और अपने परिवारों को टीवीके उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया।

असम में भाजपा सरकार लागू करेगी यूसीसी : शाह

- भरी हुंकार - प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कोई 'माई का लाल' देश की एक भी इंच जमीन नहीं छीन सकता
- मतदाता सूचियों के संशोधन का विरोध सिर्फ घुसपैठियों को संरक्षण देने के लिए कर रहे राहुल और कांग्रेस

गुवाहाटी, प्रेट्र : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को असम के ढेकियाजुली और तिहु में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए राज्य की सुरक्षा और जनसांख्यिकीय बदलाव को लेकर बड़े एलान किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा की सरकार आने वाले दिनों में असम में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करेगी। कहा कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य एक विशेष समुदाय में प्रचलित 'चार शादियों' की प्रथा पर रोक लगाना है।

घुसपैठियों की विदाई और भूमि मुक्ति का संकल्प : शाह ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि दशकों तक वोट बैंक के लालच में कांग्रेस ने सीमाओं को खुला रखा, जिससे राज्य की जनसांख्यिकी बदल गई। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार ने अब तक 1.25 लाख एकड़ भूमि को घुसपैठियों के कब्जे से मुक्त कराया है। उन्होंने कहा, 'पिछले 10 वर्षों में हमने घुसपैठ रोकी है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। अगले पांच वर्षों में हम सुनिश्चित करेंगे कि एक-एक अवैध घुसपैठिये को देश से बाहर भेजा जाए और उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएं।' उन्होंने असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई को घेरते हुए सवाल किया कि क्या वे घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं? शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और राहुल गांधी मतदाता सूचियों के संशोधन का विरोध सिर्फ घुसपैठियों को संरक्षण देने के लिए कर रहे हैं।

देश की सुरक्षा और मोदी का नेतृत्व : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से असम विरोधी रही है। उन्होंने कहा, भारत-चीन युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने असम को उसके भाग्य पर छोड़ दिया था। अतीत की तुलना वर्तमान से करते हुए उन्होंने हुंकार भरी कि मोदी सरकार के दौरान देश की सीमाओं के साथ खिलवाड़ असंभव है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कोई 'माई का लाल' देश की एक भी इंच जमीन नहीं छीन सकता।

असमिया संस्कृति और विकास का सम्मान : गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कभी असमिया विभूतियों का सम्मान नहीं किया। राज्य के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई को कांग्रेस ने भारत रत्न नहीं दिया क्योंकि उन्होंने नेहरू की उस योजना का विरोध किया था जिसमें राज्य को उस क्षेत्र के साथ पाकिस्तान को देने की बात कही गई थी जो अब बांग्लादेश है। यह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जिसने उन्हें यह सम्मान दिया। इसी तरह भूपेन हजारिका को भी मोदी सरकार ने ही भारत रत्न से नवाजा।

सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली में असम विधानसभा चुनाव से पहले राजग उम्मीदवारों के समर्थन में रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह, असम भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया व अन्य के साथ। प्रेट्र

पिछले 10 वर्षों में हमने घुसपैठ रोकी है, लेकिन यह अभी पर्याप्त नहीं है। अगले पांच वर्षों में हम सुनिश्चित करेंगे कि एक-एक अवैध घुसपैठिये को देश से बाहर भेजा जाए और उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएं।
- अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

असम में कांग्रेस ने किया पांच गारंटियों का वादा

- मल्लिकार्जुन खरगे ने की घोषणा, सरकार बनने में महिलाओं के खातों में बिना शर्त हर माह ट्रांसफर करेंगे रकम
- 25 लाख का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा, भूमि अधिकार और जुबीन गर्ग मौत मामले में न्याय का भी किया वादा

नाओबोइचा, प्रेट्र : कांग्रेस ने असम के मतदाताओं से पांच गारंटियों का वादा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार को असम के लिए अपनी पार्टी की 'पांच गारंटियों' की घोषणा की। इसमें महिला कल्याण, सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा, भूमि अधिकार और जुबीन गर्ग की मौत मामले में न्याय पर जोर दिया गया है। खरगे ने राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया।

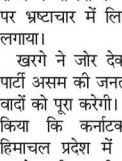

खरगे ने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी असम की जनता से किए गए सभी वादों को पूरा करेगी। उन्होंने यह दावा भी किया कि कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकारों ने अपने सभी चुनावी वादों को पूरा किया है।

लखीमपुर जिले के नाओबोइचा में रैली में खरगे ने पार्टी की 'पांच गारंटियों' के बारे में बताया। इसमें प्रत्येक महिला के बैंक खाते में बिना शर्त हर महीने रकम ट्रांसफर करने के साथ ही कारोबार करने या उसका विस्तार करने की इच्छुक महिलाओं को 50 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता शामिल है।

कांग्रेस ने सभी परिवारों के लिए 25 लाख रुपये की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना, 10 लाख आदिवासियों के लिए स्थायी भूमि पट्टे और राज्य के बुजुर्गों को 1,250 रुपये प्रति माह देने का भी वादा किया है। बुजुर्गों से संबंधित मामलों की देखरेख के लिए विशेष विभाग भी बनाया जाएगा।

खरगे ने कहा, हम कांग्रेस के सत्ता में आने के 100 दिनों के भीतर जुबीन गर्ग मृत्यु मामले में न्याय सुनिश्चित करने का भी वादा करते हैं।

खरगे ने जातीय संघर्ष से प्रभावित मणिपुर की यात्रा देर से करने को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को नकली मुख्यमंत्री करार दिया और कहा कि भाजपा ने 2021 के चुनावों में सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनावों के बाद, हिमंत ने आदिवासी नेता सोनोवाल को हटा दिया ताकि असम के सीएम की कुर्सी पर कब्जा कर सकें। खरगे ने हिमंत की सरकार पर लोगों को डराने और भय का माहौल बनाने का भी आरोप लगाया।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे रविवार को असम के नाओबोइचा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए। एएनआइ

भाजपा असम में लगातार तीसरी बार सत्ता में आएगी : नितिन नबीन

तिनसुकिया, प्रेट्र : भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने दावा किया कि पार्टी असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर हैट-ट्रिक मारेगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार केवल देश के लोगों के लिए काम करती है, न कि घुसपैठियों के लिए। नबीन ने पूर्व कांग्रेस सरकारों पर आरोप लगाया कि वे असम के विकास के बजाय वोट-बैंक की राजनीति में लिप्त थीं।

नबीन ने रविवार को मार्गेरिटा के उम्मीदवार और वर्तमान भाजपा विधायक भास्कर शर्मा के समर्थन में एक चुनावी रैली में कहा, भाजपा विधानसभा चुनावों के बाद हैट-ट्रिक बनाने जा रही है। हमने पहले सरबानंद सोनोवाल के नेतृत्व में सरकार बनाई, उसके बाद हिमंत बिस्व सरमा का कार्यकाल आया। इस बार हम सरमा के नेतृत्व में अपनी तीसरी सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि 2014 में भाजपा के नेतृत्व वाले राजग के सत्ता में आने के बाद पूरी स्थिति बदल गई और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में असम अवसरों का राज्य बन गया है।

भाजपा सत्ता में आई तो मांस-मछली नहीं खा पाएंगे बंगाली : ममता बनर्जी

- चुनावी सभा में बंगाल की सीएम ने कहा, मुझे जान से मारने की हो सकती है साजिश
- बोलीं, भाजपा और चुनाव आयोग में मिलीभगत, हटा दिए 1.20 करोड़ लोगों के नाम

जासं, पुरुलिया

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को पुरुलिया में चुनावी रैली के दौरान भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो वह खानपान की आदतों पर भी रोक लगा देगी। बंगाली मांस और मछली भी नहीं खा पाएंगे। ममता ने कहा कि मुझे जान से मारने की साजिश रची जा सकती है।

बनर्जी ने कहा, भाजपा कहती है कि मछली, मांस, अंडे नहीं खा सकते। वह धर्म की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में वे किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखते। वे दंगे भड़काते हैं। उन्होंने कहा, भाजपा शासित राज्यों में आदिवासियों का शोषण और महिलाओं पर हमले होते हैं। दरअसल, ममता बनर्जी की ये टिप्पणियां टीएमसी के चुनावी अभियान की रणनीति के अनुरूप हैं, जिसमें भाजपा को बंगाल की सांस्कृतिक परंपराओं से कटा हुआ दिखाए जाने पर जोर है।

चुनाव आयोग की ओर से लगातार अधिकारियों को हटाने की कार्रवाई पर ममता ने कहा कि साजिश के तहत मेरे अधिकार छीन लिए गए हैं।

मतदाताओं को लेकर ममता ने आरोप लगाया कि बंगाल में करीब 1 करोड़ 20 लाख मतदाताओं के नाम चुपचाप हटा दिए गए हैं। ममता ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग के बीच मिलीभगत है, जिससे अल्पसंख्यक और कुछ खास समुदायों के वोटरों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनकी मदद के लिए उनकी पार्टी कैंप लगाएगी।

पुरुलिया के मानबाजार में चुनावी सभा को संबोधित करतीं ममता बनर्जी। जागरण

लोगों को जंजीरों में बांधकर भारत भेजा गया तब कहां थे शाह : ममता ने बिना नाम लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि एक बड़े नेता ने चार्जशीट तो जारी कर दी, लेकिन जब विदेश से लोगों को जंजीरों में बांधकर भारत भेजा गया था तब वह कहां थे। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है।

इसके साथ ही अमित शाह के पट्टी वाले बयान पर उन्होंने कहा कि मैं पट्टी बांधकर घूमती हूं। पहले जाकर मेरे डाक्टर की रिपोर्ट देख लीजिए। पिछली बार चुनाव के दौरान आप लोगों ने जान-बूझकर मेरे पैर में चोट पहुंचाई थी। क्या फिर से मुझे मारने की योजना बना रहे हैं।

चुनावी समीकरण

वामपंथियों के लिए और चुनौतीपूर्ण हुआ खोया मुस्लिम वोट बैंक वापस पाना, मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर और बीरभूम में मुस्लिम आबादी निर्णायक

वामो-आइएसएफ के लिए सिरदर्द बने हुमायूं-ओवैसी

विशाल श्रेष्ठ • जागरण

कोलकाता : मुश्किलें पहले ही क्या कम थीं, जो आप भी आ धमके...। बंगाल में हुमायूं कबीर व असदुद्दीन ओवैसी की नई जुगलबंदी देख वाममोर्चा (वामो) व इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आइएसएफ) के नेता इन दिनों यही सोच रहे होंगे। इस नए गठजोड़ ने उनकी चुनौतियां और बढ़ा दी हैं। इसने बंगाल के मुस्लिम वोट बैंक को भी बेहद 'नाजुक' बना दिया है। राज्य के मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम व दक्षिण 24 परगना जिलों में मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका निभाती है। बंगाल में लगातार 34 साल एकछत्र राज करने वाला वामो 2011 में सत्ता से हटने के बाद से मुस्लिम वोट बैंक खोता चला आया है। 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस-आइएसएफ से गठजोड़ करने के बावजूद उसे कुल 4.73% वोट मिले थे, जो 2016 के विस चुनाव में 19.75% था। यही वामो जब सत्ता में था, तब उसका मुस्लिम वोट 70% से ऊपर रहा करता था। उसका ऐसा ही हश्र लोकसभा चुनावों में भी होता आया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में वामो का वोट छह से सात प्रतिशत रहा। उससे पहले 2019 में भी यह सात प्रतिशत के आसपास ही था।

कोलकाता में बुधवार को एआइएमआइएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और एजेयूपी प्रमुख हुमायूं कबीर। फाइल/प्रेट्र

ओवैसी ने पिछली बार वामो-कांग्रेस को पहुंचाया था नुकसान

2021 के विस चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने सात सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें से तीन पर कांग्रेस, तीन पर तृणमूल और एक पर वामो का कब्जा था। वे सभी सीटें तृणमूल को मिली थीं यानी कांग्रेस व वामो का वोट काटने में सफल रहे थे।

सरकते मुस्लिम वोट को संभालने के लिए वामो ने गत विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अलावा फुरफुरा शरीफ के पीरजादा नौशाद सिद्दीकी की पार्टी आइएसएफ से भी हाथ मिलाया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चुनाव में इस गठजोड़ को मात्र एक सीट मिली, वह भी नई नवेली आइएसएफ की झोली में गई थी। वामो व कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया था। हालांकि उसके बाद बंगाल में हुए पंचायत चुनाव व पिछले कुछ विधानसभा उपचुनावों में वामपंथी दलों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा है, जिससे उसकी उम्मीद थोड़ी बढ़ी है। वामो ने इस बार कांग्रेस को दरकिनार कर सिर्फ आइएसएफ से हाथ मिलाया है, लेकिन इसी बीच हुमायूं-ओवैसी के गठजोड़ ने उसकी चुनौतियां बढ़ा दी हैं।

विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल के मुस्लिम वोट बैंक के अब मुख्य रूप से चार दावेदार हो गए हैं-तृणमूल, वामो-आइएसएफ गठजोड़, कांग्रेस व हुमायूं-ओवैसी। ओवैसी के आने से मुस्लिम वोटों का 8-12% तक का नया वोट बैंक बढ़ सकता है, जिसका असर वामो-आइएसएफ पर पड़ने की आशंका है। यह 'वोट-कटवा' की चुनौती से ज्यादा 'अस्तित्व का संकट' बन सकता है।

बंगाल में कांग्रेस ने जारी की 284 प्रत्याशियों की पहली सूची

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा के दो सप्ताह बाद रविवार शाम कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। इनमें 284 प्रत्याशियों के नाम हैं। सबसे प्रमुख नाम बहरमपुर से पांच बार के सांसद रहे अधीर रंजन चौधरी का है। अधीर 30 साल बाद विस चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। अधीर ने पिछली बार 1996 में नवग्राम सीट से विस चुनाव लड़ा व जीता था।

1999 में कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें लोकसभा चुनाव में उतारते हुए बहरमपुर से टिकट दिया था, जहां से वह पांच बार सांसद निर्वाचित हुए। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने हरा दिया था। अभी भी 10 नामों की घोषणा होनी बाकी है। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार राज्य में अपनी खोई सियासी जमीन वापस पाने के लिए इस बार गठबंधन के बजाय अपने दम पर चुनाव लड़ेगी।

अधीर रंजन। फाइल

पांच बार के सांसद रहे अधीर रंजन चौधरीने 30 साल बाद विस चुनाव में ठोकी ताल

मौसम को भी मिला टिकट : सूची में दूसरा प्रमुख नाम मौसम बेनजीर नूर का है, जिन्होंने हाल में तृणमूल से वापसी की है। पार्टी ने भवानीपुर में प्रदीप प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है, जहां तृणमूल से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व भाजपा से सुवेंदु अधिकारी प्रत्याशी हैं।

21 राज्य-केंद्रशासित प्रदेश अब पीडीएस केरोसिन मुक्त हो चुके हैं। 2023-24 में पीडीएस के जरिये 10,60,524 किलोलीटर का केरोसिन आवंटन होता था।

केंद्र से मिले अतिरिक्त केरोसिन उठाने को लेकर राज्यों में उत्साह नहीं

सरकार ने आवंटित किया 48 हजार किलोलीटर अतिरिक्त केरोसिन, घरों में स्टोव नहीं, भविष्य में आपूर्ति को लेकर भी असमंजस

हिमाचल और लद्दाख ने लेने से मना किया, सिर्फ 17 राज्यों ने आवंटन आर्डर जारी किए

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण एलपीजी आपूर्ति पर दबाव बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को खाना पकाने के लिए वैकल्पिक ईंधन के रूप में 48,000 किलोलीटर अतिरिक्त केरोसिन आवंटित किया है। यह नियमित मासिक कोटे (करीब एक लाख किलोलीटर) से अतिरिक्त है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि वे जिलों में वितरण के लिए स्थानों की पहचान करें और इसे मुख्य रूप से राशन दुकानों या निर्दिष्ट स्थानों पर बांटें। हालांकि राज्यों की तरफ से योजना को लेकर खास उत्साह नहीं दिख रहा है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, अभी तक सिर्फ 17 राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों ने एसकेओ (सुपीरियर केरोसिन आयल) आवंटन के आदेश जारी किए हैं। वहीं, हिमाचल प्रदेश व लद्दाख ने बता दिया है कि उनके यहां केरोसिन की कोई जरूरत नहीं है। कई अन्य राज्य

केरोसिन। फाइल

अभी भी आदेश जारी करने में हिचकिचा रहे हैं। विशेषज्ञों व राज्य प्रशासन के सूत्रों के अनुसार, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अब बहुत कम लोगों के पास केरोसिन पर चलने वाले स्टोव या चूल्हे बचे हैं। राजस्थान, हरियाणा, उप्र आदि राज्यों में 2017 के आसपास ही पीडीएस के जरिए केरोसिन का वितरण बंद कर दिया गया था। नतीजतन, लोगों के पास केरोसिन इस्तेमाल का कोई साधन नहीं है। दूसरा, यह अतिरिक्त आवंटन काफी कम माना जा रहा है। तीसरा, केंद्र ने निर्देश दिया है कि हर जिले में सिर्फ दो स्थानों पर ही इसका वितरण हो। राज्यों का कहना है कि लोग बाजार से स्टोव खरीदकर केरोसिन का इस्तेमाल शुरू कर दें और बाद में नियमित सप्लाई न मिली तो स्थिति और खराब हो सकती है। यह लोकप्रिय फैसला नहीं होगा।

दरअसल, केंद्र सरकार पिछले एक दशक से केरोसिन को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की नीति पर चल रही थी। स्वच्छ ईंधन (एलपीजी) को बढ़ावा देने व प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटीके) योजना के तहत कई राज्यों को केरोसिन का कोटा सौंपने के बदले नकद प्रोत्साहन दिया गया। नतीजा यह है कि 21 राज्य-केंद्रशासित प्रदेश अब पीडीएस केरोसिन मुक्त हो चुके हैं। 2023-24 में पीडीएस के जरिए 10,60,524 किलोलीटर का केरोसिन आवंटन था। सबसे ज्यादा 66 प्रतिशत अकेले बंगाल को (7,04,016 किलोलीटर) मिला था। अब नियमित मासिक कोटा भी एक लाख किलोलीटर है, जो पहले के मुकाबले बहुत कम है।

पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि यह अतिरिक्त आवंटन पश्चिम एशिया संकट के चलते एलपीजी पर दबाव कम करने को किया गया है। राज्य स्तर पर वितरण व्यवस्था, स्टोव की उपलब्धता व भविष्य की आपूर्ति पर अनिश्चितता के कारण योजना पर अमल में देरी हो रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केरोसिन मुख्य रूप से राशन कार्डधारकों को खाना पकाने और रोशनी के लिए दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल कई राज्यों में तैयारियां पूरी नहीं हो पाई हैं।

दिल्ली में प्रवासी लोगों व छात्रों के लिए उपलब्ध होगा छोटा सिलिंडर, नोटिफिकेशन जल्द

नेमिष हेमंत • जागरण

5 किलो का सिलिंडर आधार कार्ड पर होगा उपलब्ध, 100 रुपये प्रति किलो मिलेगी एलपीजी

- एलपीजी की किल्लत से बढ़ी है प्रवासी और स्ट्रीट फूड संचालकों की परेशानियां, मिलेगी राहत

नई दिल्ली: एलपीजी सिलिंडर की किल्लत से सर्वाधिक परेशान प्रवासी लोगों व छात्रों की दिक्कतें दूर होने जा रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय उन्हें जल्द पांच किलो का छोटा सिलिंडर मुहैया कराएगी। इसे लेकर शीघ्र अधिसूचना जारी हो सकती है। मामले से जुड़े राष्ट्रीय स्तर के गैस वितरकों के एसोसिएशन के एक पदाधिकारी ने बताया कि पेट्रोलियम मंत्रालय और तेल कंपनियों संग शनिवार को वेबिनार में महानगरों में रह रहे प्रवासी लोगों व छात्रों को हो रही दिक्कत पर चर्चा हुई। तय हुआ कि उन्हें छोटे सिलिंडर की आपूर्ति की जाए। गली-मोहल्लों में अवैध रूप से छोटे सिलिंडरों की रीफिलिंग कर रहे दुकानदारों के विरुद्ध अभियान चलाया जाए।

पांच किलो वाला यह सिलिंडर आधार कार्ड पर मिलेगा। इसमें एलपीजी की कीमत प्रति किलो 100 रुपये रहेगी। नाम न छापने की शर्त पर उन्होंने बताया कि सोमवार या मंगलवार को इसे लेकर नोटिफिकेशन आ सकता है। यह उन लोगों के लिए राहत भरी खबर है, जो काम धंधे के लिए दूसरे शहर में रहते हैं और उनके पास अधिकृत गैस कनेक्शन नहीं है। दिल्ली में ही ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है। छोटे गैस सिलिंटर से बड़ी संख्या में छात्र भी लाभान्वित होंगे, जो हास्टल या किराये के कमरों में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। उनमें से अधिकतर मौजूदा समय में अवैध रूप से छोटे सिलिंडर भरवा रहे हैं। उन्हें खुले बाजार में एलपीजी 200 से 250 रुपये किलो तक मिल रही है। वैसे, छोट् सिलिंडर के लिए किसी कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है, यह आधार कार्ड पर ही उपलब्ध होगा। पहले भी यह गैस एजेंसियों पर उपलब्ध होता था, लेकिन तब उसमें लोगों की दिलचस्पी कम थी। वहीं, एलपीजी संकट के बीच उसकी आपूर्ति भी पूरी तरह से बंद कर दी गई है। अब व्यावसायिक सिलिंडरों की उपलब्धता बढ़ाने के साथ छोटे सिलिंडर भी उपलब्ध कराने को लेकर रणनीति बनी है। उनके अनुसार, यह एलपीजी कंपनियों से रीफिलिंग होती है। साथ ही इसकी टंकी मजबूत होती है। इसलिए यह सुरक्षित है।

स्ट्रीट फूड स्टाल के लिए उपलब्धता पर संशय: स्ट्रीट फूड के स्टालों पर छोटे सिलिंडरों का उपयोग होता है। इनकी अनुपलब्धता से उनका काम प्रभावित हो रहा है। वैसे, छोटू सिलिंडर व्यावसायिक कार्यों के लिए उपलब्ध होगा कि नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। मामले से जुड़े लोगों के अनुसार, एक-दो दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

मना करने पर भी पति करता रहा डांस, पत्नी ने दी जान

जागरण संवाददाता, दुमका: झारखंड के दुमका जिले के शहरों गांव में शनिवार रात विवाह समारोह के दौरान एक युवक अपने परिवार और रिश्ते की अन्य महिलाओं के साथ डांस कर रहा था। पत्नी के मना करने पर भी पति नहीं रुका तो पत्नी ने कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर ली।

ठाड़ीपाथर गांव की 19 वर्षीय सूर्या देवी और 22 वर्षीय मनोज राय ने एक साल पहले प्रेम विवाह किया था। मनोज रोजी-रोटी के लिए मुंबई काम करने चला गया। इसी बीच मनोज की चचेरी बहन की शादी तय हुई। तीन दिन पहले ही मनोज रविवार को बहन की शादी में शामिल होने के लिए मुंबई से गांव आया था। शनिवार को शादी की रस्मों के दौरान परिवार के सभी लोग डांस कर रहे थे। डीजे की धुन पर मनोज भी घर की महिलाओं के साथ डांस करने लगा। यह बात उसकी पत्नी सूर्या को पसंद नहीं आई। इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि आवेश में आकर सूर्या ने कीटनाशक खा लिया। जब मनोज कमरे में उसे देखने के लिए गया तो सूर्या के मुंह से झाग निकल रहा था। इसके बाद घर के लोग सूर्या को मेडिकल कालेज अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

एयरलाइंस को राहत के लिए विकल्प तलाश रहा उड्डयन मंत्रालय

- राज्य सरकारों के साथ मिलकर एटीएफ पर टैक्स कम करने के विकल्प पर चल रही चर्चा

के. राममोहन नायडू। फाइल

नई दिल्ली, प्रेट्र : पश्चिम एशिया संघर्ष के एयरलाइन कंपनियों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय कई विकल्प तलाश रहा है। इसमें एक है राज्य सरकारों के साथ मिलकर विमान ईंधन (एटीएफ) पर टैक्स को कम करना। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद तेल की बढ़ती कीमतों और हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंधों के कारण भारतीय एयरलाइंस की परिचालन लागत तेजी से बढ़ रही है।

सूत्र के अनुसार, नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू और मंत्रालय ने जेट ईंधन पर टैक्स कम करने की संभावना पर मुख्यमंत्रियों और राज्य सरकारों के साथ चर्चा शुरू कर दी है। एयरलाइन की कुल परिचालन लागत में एटीएफ का हिस्सा 40 प्रतिशत होता है। एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) पर वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) की दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग है।

पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते एयरलाइनों ने विशेष रूप से पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए अपनी सेवाओं में कटौती की है। एयरस्पेस प्रतिबंध के खपत बढ़ रही है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) अन्य देशों के समकक्ष नियामकों के साथ हालात को लेकर संपर्क में है।

समर शेड्यूल के तहत उड़ानों को मंजूरी देने में अपनाया सतर्क रुख : पिछले साल दिसंबर में इंडिगो में हुए पैमाने पर परिचालन व्यवधानों के मद्देनजर नागर विमानन अधिकारियों ने समर शेड्यूल (ग्रीष्मकालीन मौसम के लिए उड़ानों के संचालन) के लिए उड़ानों की संख्या को मंजूरी देने में सतर्क रुख अपनाया है। इस कारण इस बार ग्रीष्मकालीन मौसम में एयरलाइंस कम उड़ानें संचालित करेंगी। सूत्र ने बताया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) नहीं चाहते कि पिछले साल दिसंबर में इंडिगो के साथ जो हुआ, वैसी स्थिति दोबारा उत्पन्न हो। सूत्रों के अनुसार, विमानों, पायलटों और और अन्य जरूरी संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए एयरलाइन के समर शेड्यूल को मंजूरी दी गई है। घरेलू समर शेड्यूल में, एयरलाइंस पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान संचालित उड़ानों की संख्या की तुलना में कम से कम 10 प्रतिशत कम उड़ानें संचालित करने वाली हैं। इसके बाद डीजीसीए ने एयरलाइन के सर्दियों के कार्यक्रम में 10 प्रतिशत कटौती कर दी थी।

देहरादून के जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर शुरू हुई डिजी यात्रा सुविधा

नई दिल्ली, एएनआइ: देहरादून के जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर यात्रियों को डिजी यात्रा सुविधा मिलनी शुरू हो गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने रविवार को गुजरात के राजकोट से देहरादून के जौली ग्रांट हवाई अड्डे पर डिजी यात्रा सुविधा का वर्चुअली शुभारंभ किया। इस सेवा के शुरू होने से यात्री चेहरे की पहचान का उपयोग करके आसानी से हवाईअड्डे में प्रवेश कर सकेंगे। इससे चेक-इन, बोर्डिंग पास और अन्य प्रक्रियाओं में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। डिजी यात्रा सरकार की परिवर्तनकारी डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य चेहरे की पहचान तकनीक (एफआरटी) के जरिये हवाईअड्डों पर यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाना है। गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए यात्रियों की पहचान और यात्रा संबंधी दस्तावेज उनके स्मार्टफोन में ही सुरक्षित वालेट में संग्रहीत किए जाते हैं। अपलोड किया गया डाटा ब्लाकचेन तकनीक का उपयोग करता है और उपयोग के 24 घंटों के भीतर सर्वर से सारा डाटा हटा दिया जाता है।

94 हजार टन एलपीजी से लदे दो और भारतीय जहाज होर्मुज से सुरक्षित निकले

- बीडब्ल्यू टीवाईआर जहाज के 31 मार्च तक मुंबई, बीडब्ल्यू ईएलएम के एक अप्रैल को न्यू मंगलौर पहुंचने की उम्मीद
- होर्मुज स्ट्रेट में भारतीय झंडे वाले अभी 18 जहाज और, इन पर 485 भारतीय नाविक सवार

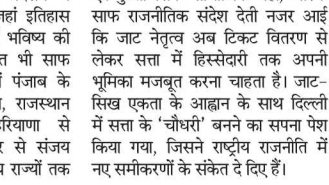
प्रतीकात्मक

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय झंडे वाले दो और एलपीजी टैंकर पश्चिम एशिया के युद्ध प्रभावित होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित निकल चुके हैं और अगले कुछ दिनों में इनके भारतीय तटों पर पहुंचने की उम्मीद है। इन जहाजों पर देश के लगभग एक दिन के इस्तेमाल की रसोई गैस लदी है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया 'दो एलपीजी जहाज बीडब्ल्यू टीवाईआर और बीडब्ल्यू ईएलएम सुरक्षित रूप से होर्मुज स्ट्रेट क्षेत्र से गुजर चुके हैं और भारतीय तटों की ओर बढ़ रहे हैं। बीडब्ल्यू टीवाईआर मुंबई की ओर बढ़ रहा है और इसके 31 मार्च को पहुंचने की उम्मीद है जबकि बीडब्ल्यू ईएलएम न्यू मंगलौर बंदरगाह की ओर जा रहा है और इसके एक अप्रैल को आने की संभावना है। यह दोनों जहाज लगभग 94,000 टन एलपीजी लेकर आ रहे हैं। अमेरिका और इजरायल के हमलों तथा ईरान की जवाबी कार्रवाई के कारण होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही लगभग रुक गई है। यह संकीर्ण समुद्री मार्ग खाड़ी देशों से दुनिया में तेल और गैस के निर्यात का मुख्य रास्ता है। ईरान ने हाल ही में कहा है कि गैर शत्रु देशों के जहाज ईरानी अधिकारियों के समन्वय से इस मार्ग से निकल सकते हैं।' इससे पहले भारतीय झंडे वाले चार एलपीजी टैंकर सुरक्षित रूप से इस मार्ग से निकल चुके हैं।

भारत अपनी रसोई गैस की जरूरतों का लगभग 60 प्रतिशत खाड़ी देशों से आयात करता है। पिछले साल भारत ने 3.31 करोड़ टन एलपीजी का उपभोग किया, जिसमें 90 प्रतिशत आयात पश्चिम एशिया से आया था। होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने के बाद भारत अमेरिका और अर्जेंटीना जैसे देशों से एलपीजी प्राप्त कर रहा है। बयान में कहा गया- 'होर्मुज स्ट्रेट क्षेत्र में भारतीय झंडे वाले कुल 18 जहाज हैं जिन पर 485 भारतीय नाविक सवार हैं।' पोत परिवहन महानिदेशालय का नियंत्रण कक्ष चौबीसों घंटे काम कर रहा है और अब तक 4,523 काल और 8,985 ईमेल हेंडल कर चुका है।

बिहार की नई सरकार में भाजपा से अधिक होंगे जदयू कोटे के मंत्री

भुवनेश्वर वात्स्यायन • जागरण

- भाजपा कोटे से मुख्यमंत्री बनने पर सामने आएगी नई स्थिति, जदयू को मिल सकता है विस अध्यक्ष का पद

भाजपा और जदयू। फाइल

पटना : बिहार में बनने वाली नई सरकार में इस बार भाजपा से अधिक जदयू कोटे के मंत्री होंगे। यह तय माना जा रहा कि इस बार मुख्यमंत्री भाजपा से बनेगा। इस वजह से मंत्रिमंडल का गठन रिवर्स मोड में होना है। पिछले वर्ष नवंबर में बिहार में एनडीए सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शपथ ली थी। मंत्रिमंडल में नीतीश सहित 27 मंत्री थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद यह संख्या 26 हो गई है।

वर्तमान में नीतीश कुमार सहित जदयू के नौ मंत्री हैं। कहा जा रहा कि इस बार यह संख्या 13-14 तक जा सकती है। वहीं भाजपा के 13 विधायक मंत्री हैं। इनमें दो उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व विजय कुमार सिन्हा भी शामिल हैं। भाजपा कोटे के मंत्रियों की संख्या कम होकर 10 तक हो सकती है। मंत्रिमंडल का गठन रिवर्स मोड में होने की स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष पद जदयू को मिल सकता है। वर्तमान में यह पद भाजपा के पास है। 91 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के अनुसार, किसी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्य हैं। इस आधार पर अधिकतम 36 मंत्री ही हो सकते हैं।

इस हिसाब से इनका बंटवारा एनडीए के अलग-अलग घटक दलों में उनकी संख्या के आधार पर होगा। वर्तमान सरकार में भाजपा कोटे से 13, जदयू से नौ, लोजपा (रा) से दो, रालोमो व हम से एक-एक मंत्री हैं।

राजौरी में मिले दो संदिग्ध गुब्बारे, जांच एजेंसियां सतर्क

जागरण संवाददाता, राजौरी : जम्मू-कश्मीर में राजौरी जिले की नौशहरा तहसील के दो गांव में रविवार को संदिग्ध हवाई जहाज आकार नुमा दो गुब्बारे मिले। हंजना गांव में सुबह पहला गुब्बारा मिला जिस पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की मार्किंग थी, जबकि शाम को डीन गांव में दूसरा गुब्बारा बरामद हुआ। ग्रामीणों ने इसकी सूचना प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को दी, जिसके बाद पुलिस ने गुब्बारों को कब्जे में ले लिया। प्रारंभिक जांच में यह सामान्य गैस से भरे गुब्बारे प्रतीत होते हैं, पर विदेशी एयरलाइन की मार्किंगके कारण सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं।

अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि गुब्बारे सीमा पार से आए हैं या किसी अन्य स्रोत से यहां पहुंचे। गुब्बारे मिलने के बाद आसपास के क्षेत्रों में सतर्कता के साथ निगरानी बढ़ाई गई है। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि गुब्बारा सुबह खेतों के पास देखा गया। गुब्बारे मिलने से क्षेत्र में दहशत है। एजेंसियां जांच कर रही हैं कि यह किसी जासूसी गतिविधि या शरारती घटना से जुड़ा मामला तो नहीं है।

पेट की अतिरिक्त चर्बी समग्र मोटापे की तुलना में अधिक खतरनाक

- केंद्रीय मंत्री ने जीवनशैली में बदलाव करने और जागरूक रहने की दी सलाह

जितेंद्र सिंह। फाइल

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने समग्र मोटापे की तुलना में पेट पर अतिरिक्त चर्बी के जमा होने को अधिक खतरनाक करार दिया। खासकर भारतीय परिपेक्ष्य में, जहां दुबले-पतले दिखने वाले व्यक्तियों में भी पेट पर अक्सर काफी मात्रा में वसा पाई जाती है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह सामान्य मोटापे से अधिक खतरनाक है और हृदय रोगों व मधुमेह का मुख्य कारण है। उन्होंने इसके लिए जीवनशैली में बदलाव करने और जागरूक रहने की सलाह दी।

मंत्री ने कहा कि हालांकि पुरुषों और महिलाओं दोनों में समग्र मोटापा बढ़ रहा है, लेकिन पेट पर चर्बी जमने का मामला असमान रूप से अधिक बना हुआ है और यह हृदय रोग के जोखिम के एक बड़े कारक के रूप में काम करता है। मंत्री ने 'एडवांसेज इन ओबेसिटी एंड लिपिड मैनेजमेंट इन सीवीडी' नामक पुस्तक के विमोचन के दौरान कहा-'पेट के आसपास आंतरिक वसा की उपस्थिति, सामान्य मोटापे के बिना भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या का कारण बनती है और इसका जल्द पता लगाने के साथ-साथ सही तरीके से निदान करने की जरूरत होती है।'

मंत्री ने यह भी बताया कि युवा जनसंख्या में मेटाबोलिक विकारों जैसे कि टाइप-2 डायबिटीज और हृदय संबंधी विकारों की बढ़ती घटनाएं बदलती जीवनशैली, आहार की आदतों और शारीरिक गतिविधि में कमी को दर्शाती हैं। बता दें कि भारत दुनिया में मोटापे की राजधानी के रूप में भी उभर रहा है और बाल मोटापे में विश्व में तीसरे स्थान पर है।

तेलंगाना में बीआरएस के 24 विधायक दो दिन के लिए निलंबित

- राजस्व मंत्री के खिलाफ जांच के लिए सदन में कर रहे थे हंगामा
- रेड्डी पर हैं भ्रष्टाचार और अवैध खनन कराने के आरोप

भारत राष्ट्र समिति। फाइल

हैदराबाद, आइएएनएस: तेलंगाना विधानसभा में हंगामा करते हुए कार्यवाही में बाधा डाल रहे भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के 24 विधायकों को दो दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया है। इस आशय का प्रस्ताव सदन में विधायी मामलों के मंत्री डी श्रीधर बाबू ने पेश किया जिसे ध्वनि मत से स्वीकार किया गया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष गड्डम प्रसाद कुमार ने 24 बीआरएस विधायकों को सदन से दो दिन के लिए निलंबित कर दिया।

बीआरएस तेलंगाना विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल है। बीआरएस के सदस्य राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी पर लगे भ्रष्टाचार और अवैध खनन के मामलों की जांच विधानसभा की समिति से कराए जाने की मांग कर रहे थे। इसी मांग को लेकर उन्होंने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही जांच के लिए समिति गठित किए जाने की मांग शुरू कर दी। समय के साथ बीआरएस सदस्यों का हंगामा बढ़ता गया। इस दौरान वे काम रोको प्रस्ताव भी लाए लेकिन स्पीकर ने उनकी मांग अस्वीकार कर दी। इसके बाद सदन में हंगामा और बढ़ गया और बीआरएस सदस्य विधानसभा अध्यक्ष के आसन के समक्ष आकर नारेबाजी और हंगामा करने लगे। इससे चलते सदन की कार्यवाही ठप हो गई।

राज्य सरकार ने भारत राष्ट्र समिति की मांग को खारिज करते हुए कहा कि 2014 से हो रहे अवैध खनन के मामले की जांच पहले ही सीबी सीआइडी को दी जा चुकी है। इसलिए मामले में किसी अन्य जांच की जरूरत नहीं है।

प्रतिमा अनावरण पर राजनीति

शासनादेश का हवाला दे प्रशासन ने पट्टिका से जाट शब्द हटवाया, बालियान व एसडीएम में नोकझोंक, मंच से सांसद हनुमान बेनीवाल ने दी चेतावनी, जाट शब्द वापस लगवा दें नहीं तो योगी को हटवा देंगे

प्रतिमा से जाट शब्द हटाने पर हंगामा, बिना अनावरण किए लौटे मान

जागरण संवाददाता, मेरठ

महाराजा सूरजमल की प्रतिमा अनावरण के बाद जाट शब्द लिखी पट्टिका हटाने के विरोध में आक्रोशित लोग। जागरण

देर शाम बनी सहमति, खत्म हुआ धरना

शाम करीब साढ़े सात बजे प्रशासन व नेताओं के बीच सहमति बनी। विवादित पट्टिका को पुलिस लाइन से संजीव बालियान के आवास पर पहुंचाया गया, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ। बालियान का तर्क था कि पट्टिका किसी जाति का प्रचार नहीं है। अंतरराष्ट्रीय जाट संसद संगठन का नाम है, जिसकी अनुमति लेकर इसे पुन: लगवाया जाएगा। जहां आयोजक अनावरण संपन्न होने का दावा कर रहे हैं, वहीं प्रशासन का कहना है कि अनुमति केवल सम्मान समारोह की थी, अनावरण की नहीं।

मेरठ के सरधना क्षेत्र में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गया। प्रतिमा की पट्टिका से जाट शब्द हटाने को लेकर जिला प्रशासन, भाजपा नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री डा. संजीव बालियान व नागौर (राजस्थान) के सांसद हनुमान बेनीवाल के बीच नोकझोंक हुई। विवाद इतना बढ़ा कि मुख्य अतिथि और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बिना अनावरण किए ही कार्यक्रम से वापस लौट गए।

विवाद की शुरुआत तब हुई जब जिला प्रशासन ने महापुरुषों की प्रतिमाओं पर जाति विशेष का नाम न लिखने के शासनादेश का हवाला देते हुए पट्टिका से जाट शब्द हटवा दिया। आयोजकों ने अंतरराष्ट्रीय जाट संसद के नाम की पट्टिका लगवाई थी, जिसे पुलिस ने शनिवार रात ही हटा दिया था। मंच से इस कार्रवाई का विरोध शुरू हुआ। सांसद हनुमान बेनीवाल ने मंच पर मौजूद संजीव बालियान की ओर इशारा कर कहा, "जाट शब्द वापस लगवा दें, नहीं तो सीएम योगी को हटवा देंगे।" शाम को माहौल तब और गरमा गया जब बालियान, बेनीवाल व अंतरराष्ट्रीय जाट संसद के अध्यक्ष मनु चौधरी प्रतिमा स्थल पर पहुंच गए। इन नेताओं की एसडीएम उदित नारायण सेंगर व सीओ प्रकाश चंद अग्रवाल से तीखी बहस हुई। धक्का-मुक्की में किसी नुकीली चीज से सीओ चोटिल हो गए। प्रशासन के अड़ियल रुख के विरोध में मनु चौधरी समर्थकों के साथ प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए। इंटरनेट मीडिया के जरिए युवाओं को मौके पर जुटने का आह्वान किया जाने लगा, जिससे तनाव बढ़ गया।

इससे पूर्व कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, भाजपा सरकार देश को विश्व गुरु बनाने का दावा करती थी, पर विश्व चेला बना दिया है। महंगाई व किसानों की दुर्दशा का आलम यह है कि पहले गोरे अंग्रेज लूटते थे, अब काले अंग्रेज लूट रहे हैं। हालांकि, पट्टिका विवाद न सुलझने पर वे बिना प्रतिमा का अनावरण किए ही दिल्ली लौट गए। जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला ने समाज को एकजुट रहने की सलाह देते हुए कहा,हमारा डीएनए सनातनी से पहले किसानी है। उन्होंने राजस्थान के मीणा समाज का उदाहरण देते हुए जाट समाज के सेवानिवृत्त अधिकारियों को समाज के कार्यों में सक्रिय होने का आह्वान किया।

पश्चिम यूपी के मंच से पांच राज्यों तक गूंजा जाट राजनीति का संदेश

राज्य ब्यूरो, जागरण • लखनऊ

- सूरजमल प्रतिमा अनावरण बना शक्ति प्रदर्शन, कई दलों के नेताओं की मौजूदगी से बढ़ी सियासी हलचल

उप्र में भले ही विधान सभा चुनाव अभी दूर है, पर जमीनी स्तर पर राजनीतिक तापमान तेज होने लगा है। पश्चिमी उप्र में इस बार केंद्र में जाट राजनीति है, जिसकी धुरी पहचान, प्रतीक,एकजुटता के इर्द-गिर्द घूमती नजर आ रही है। राजा सूरजमल की प्रतिमा ने इस उभार को ठोस रूप दे दिया। अंतरराष्ट्रीय जाट संसद के बैनर तले आयोजित यह कार्यक्रम राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन में तब्दील हो गया। मंच से जहां इतिहास के गौरव की बात हुई, वहीं भविष्य की सत्ता में हिस्सेदारी के संकेत भी साफ तौर पर उभरे। कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, राजस्थान से हनुमान बेनीवाल, हरियाणा से दिग्विजय चौटाला व बिहार से संजय सिंह की मौजूदगी ने इसे पांच राज्यों तक फैले जाट नेटवर्क का रूप दे दिया। स्थानीय स्तर पर भी इसके सियासी मायने गहरे रहे। भाजपा नेता व मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद संजीव बालियान, कैराना के पूर्व सांसद हरपाल सिंह पंवार, रामावतार पलसानिया जैसे जाट चेहरे एक मंच पर दिखे। यह एकजुटता सिर्फ सामाजिक नहीं, बल्कि साफ राजनीतिक संदेश देती नजर आई कि जाट नेतृत्व अब टिकट वितरण से लेकर सत्ता में हिस्सेदारी तक अपनी भूमिका मजबूत करना चाहता है। जाट-सिख एकता के आह्वान के साथ दिल्ली में सत्ता के 'चौधरी' बनने का सपना पेश किया गया, जिसने राष्ट्रीय राजनीति में नए समीकरणों के संकेत दे दिए हैं।

15 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया गया है माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में। इसमें से 12,250 किलोमीटर सड़क का निर्माण पिछले 10 वर्षों में किया गया है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार, 30 मार्च, 2026

दस हजार से अधिक माओवादियों का एक दशक में आत्मसमर्पण

2025 में 2300 का समर्पण, 2026 में 630 ने सशस्त्र विद्रोह है छोड़ा

देश से माओवाद समाप्त करने की समयसीमा 31 मार्च तक निर्धारित

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुरक्षा दबाव और पुनर्वास प्रयासों के संयोजन ने देश के सबसे लंबे समय तक चलने वाले विद्रोहों में से एक माओवाद को घातक झटका दिया है। इसमें पिछले दशक में 10 हजार से अधिक माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश से माओवाद को समाप्त करने की समयसीमा 31 मार्च निर्धारित की है। 2025 में 2,300 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया और 2026 के पहले तीन महीनों में 630 से अधिक कैडरों ने सशस्त्र विद्रोह के बजाय मुख्यधारा का जीवन चुना।

2014 से 2026 की शुरुआत तक के वामपंथी माओवाद (एलडब्ल्यूई) आत्मसमर्पण के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं सरकार ने माओवाद के खिलाफ पिछले सरकारों के बिखरे हुए दृष्टिकोण को बदलती है। "रेड कारिडोर" में सड़क निर्माण इसका एक उदाहरण है, जो एक आर्क है जो कभी "पशुपति से तिरुपति" तक फैला हुआ था, जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे, जहां ठेकेदार काम करने से इन्कार कर देते थे। केंद्र ने पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी (पीएलजीए) के मुख्य क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए बार्डर रोड्स आर्गनाइजेशन (बीआरओ) को जिम्मेदारी दी, जिसमें इन विद्रोह के गढ़ों में पांच प्रमुख सड़कों और छह महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण शामिल है।

माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में 15 हजार किमी से अधिक सड़कों का निर्माण किया गया है। इसमें से पिछले 10 वर्षों में 12,250 किलोमीटर का निर्माण पूरा किया गया है। सुरक्षित पुलिस स्टेशनों की संख्या 2014 में 66 से बढ़कर पिछले 10 वर्षों में 586 हो गई है। छह वर्षों में 361 नए सुरक्षा शिविर स्थापित किए गए हैं और 68 रात में उतरने वाले हेलीपैड बनाए गए हैं।

माओवादी घटनाओं की रिपोर्ट करने वाले पुलिस स्टेशनों की संख्या 2013 में 76 जिलों में 330 से घटकर जून 2025 तक केवल 22 जिलों में 52 रह गई है। सरकार के सुरक्षा दबाव व पुनर्वास प्रयासों के संयोजन पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति ने आंदोलन के मूल को कमजोर कर दिया।

इससे माओवाद नेतृत्वविहीन हो गया है और सरकारी योजनाओं के लाभ आम लोगों तक पहुंचने लगे। सरकार ने शिक्षा और बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया। इसका उद्देश्य विद्रोह की सामाजिक-आर्थिक जड़ों को कमजोर करना है।

आत्मसमर्पण करते माओवादी। फाइल

माओवाद के खात्मे पर आज चर्चा करेगी लोस

नई दिल्ली, प्रेट्र : लोकसभा सोमवार को वामपंथी माओवाद से देश को मुक्त करने के प्रयासों पर चर्चा करेगी, जो कि माओवाद समाप्त करने के लिए सरकार की 31 मार्च की समयसीमा से एक दिन पहले है। लोकसभा सचिवालय ने "वामपंथी माओवाद (एलडब्ल्यूई) से देश को मुक्त करने के प्रयास" पर चर्चा को नियम 193 के तहत सूचीबद्ध किया है, जिसमें मतदान की जरूरत नहीं है। इस नियम के तहत संक्षिप्त अवधि की चर्चा में सरकार का उत्तर आवश्यक है। इस चर्चा की शुरुआत तेदेपा सांसद बायरड्डी शबरी और शिवसेना के सदस्य श्रीकांत शिंदे करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी कि माओवादी समस्या को 31 मार्च, 2026 तक पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा।

सुकमा में मुठभेड़ के दौरान पांच लाख का इनामी माओवादी ढेर

नईदुनिया, सुकमा: छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले के पोलमपल्ली थाना क्षेत्र के जंगल-पहाड़ी इलाके में मुठभेड़ में पांच लाख का इनामी माओवादी मूचाकी कैलाश मारा गया। एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर डीआरजी टीम ने सर्च आपरेशन शुरू किया था। रविवार सुबह से ही माओवादियों और पुलिस के बीच रुक-रुक कर फायरिंग होती रही। मुठभेड़ स्थल की तलाशी लेने पर एक पुरुष माओवादी का शव हथियार सहित बरामद किया गया। उसकी पहचान मूचाकी कैलाश के रूप में हुई है। वह नागरिकों की हत्या, हमलों और आईईडी ब्लास्ट की साजिशों में शामिल रहा है। बस्तर रेंज के आइजी सुंदरराज पी ने माओवादियों से आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने की अपील की है। इस वर्ष प्रदेश में अब तक 27 माओवादियों को अलग-अलग मुठभेड़ों में मार गिराया गया है। गत वर्ष सुरक्षाबलों ने राज्य में मुठभेड़ों में कुल 285 माओवादियों को मार गिराया था।

'स्कूल, बोर्ड, पंचायत के प्रमाणपत्र मौजूद तो मेडिकल परीक्षण विधि विरुद्ध'

विधि संवाददाता, जागरण ● लखनऊ

नाबालिग की उम्र निर्धारण में नियमों की अनदेखी पर हाई कोर्ट का अहम निर्णय

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि जब स्कूल, बोर्ड, नगर निगम, नगरपालिका या पंचायत के प्रमाणपत्र उपलब्ध हों तब किसी नाबालिग की उम्र निर्धारण के लिए मेडिकल परीक्षण (आसिफिकेशन टेस्ट) कराना कानून के विरुद्ध है। यह कहते हुए कोर्ट ने इस मामले में किशोर न्याय बोर्ड और विशेष पाक्सो अदालत के आदेशों को निरस्त करते हुए नाबालिग को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह आदेश एक नाबालिग की ओर से दाखिल रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है।

मामला प्रतापगढ़ जिले का है, जहां 11 मार्च, 2025 को लीलापुर थाने में दर्ज एफआइआर में एक नाबालिग पर पाक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। आरोप था कि उसने 15 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़छाड़ की और उसे धमकी दी। याचिका में नाबालिग की ओर से दलील दी गई कि घटना के समय उसकी उम्र 16 वर्ष से कम थी। हाईस्कूल प्रमाणपत्र में जन्मतिथि 1 जनवरी, 2010 दर्ज है जबकि प्राथमिक विद्यालय के अभिलेख में 13 मई 2009 अंकित है। इसके बावजूद किशोर न्याय बोर्ड ने उम्र तय करने के लिए मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश दे दिया जिसे विशेष जज पाक्सो एक्ट ने भी बरकरार रखा। इन्हीं आदेशों को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

हाई कोर्ट ने कहा, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 के अनुसार उम्र निर्धारण के लिए सबसे पहले स्कूल या बोर्ड के प्रमाणपत्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उसके बाद नगर निगम, नगरपालिका या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र को देखना चाहिए।। दोनों उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार भी आरोपी याची नाबालिग ही है। ऐसे में मेडिकल परीक्षण का आदेश देना कानून के विपरीत था।

10 हजार में बिक रहे म्यूल खाते, टेलीग्राम एप पर सौदा

ग्वालियर से संचालित हो रहा म्यूल खातों (किराये के खाते) का बड़ा नेटवर्क

शातिर बिचौलिये जरूरतमंद लोगों को जल्द रुपया कमाने का दे रहे हैं झांसा

अमित मिश्रा ● नईदुनिया

मनीष यादव

ईशू रजक

ग्वालियर: साइबर ठगी के मामलों में अब तक मध्य प्रदेश पुलिस दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार से म्यूल खाते (किराये के खाते) खुलवाने वाले बिचौलियों और खाताधारकों को पकड़कर लाती रही है। हाल में दो लोगों की गिरफ्तारी से सामने आया है कि ग्वालियर से ही म्यूल खातों का बड़ा नेटवर्क चलाया जा रहा है। इनके माध्यम से करोड़ों रुपये की साइबर ठगी हो रही है। शातिर बिचौलिये प्रदेश भर से जरूरतमंद लोगों को जल्द रुपया कमाने का लालच देकर फंसा रहे हैं। महज 10 हजार रुपये में इनके बैंक खाते बेचे जा रहे हैं।

ग्वालियर पुलिस ने दो बिचौलियों मनीष यादव और ईशू रजक को पकड़ा है। इनके मोबाइल में जो डाटा पुलिस को मिला है, उससे पता चला है कि बिचौलिये टेलीग्राम एप के जरिये चीन और कंबोडिया में बैठे शातिर ठगों से जुड़े हैं। खाते में ठगी का पैसा आने के बाद क्रिप्टो ट्रेडिंग के जरिये विदेश भेजा जाता है। पुलिस को इन दोनों के मोबाइल से मिले डाटा के अनुसार, ये 220 टेलीग्राम ग्रुप और वाट्सएप ग्रुप से बिचौलियों जुड़े हैं। चीन, कंबोडिया, दुबई में बैठे ठग इन खातों की डिमांड करते हैं। इसके बाद ये खाता उपलब्ध करवाते हैं। इन खातों में विदेश में बैठे ठग डिजिटल अरेस्ट सहित अन्य तरीके से साइबर ठगी का पैसा डलवाते हैं। जिसे ठगा जाता है, उससे इन्हीं खातों में पैसा ट्रांसफर कराया जाता है। फिर दूसरी और तीसरी लेयर के लिए भी यही बिचौलिये खाते उपलब्ध कराते हैं।

90 प्रतिशत खाते निजी बैंकों के

पैसे ट्रांसफर करने के लिए ठग निजी बैंक खातों का प्रयोग करते हैं। इन बैंकों में आनलाइन खाता खुलवाने की प्रक्रिया आसान है। जितना ठगी का पैसा म्यूल खातों में आता है। उसमें से 20 प्रतिशत कमीशन के रूप में काटकर बिचौलिये बाकी पैसे को क्रिप्टो करेंसी में बदलकर ठगों तक पहुंचा देते हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपितों ने बताया कि बैंक के निकट ये लोग जरूरतमंद लोगों को चिह्नित करते हैं। झांसा देते हैं कि अगर वह खाता किराये पर देंगे या नया खाता खुलवाकर सारा एक्सेस दे देंगे तो रुपये मिलेंगे। नया खाता खुलवाने पर 10 हजार रुपये और पहले से जो खाता खुला है उसमें हर ट्रांजेक्शन पर कमीशन फिक्स कर देते हैं। बिचौलियों के पास से ग्वालियर सहित अन्य जिलों के रहने वाले लोगों के अलग-अलग बैंक के 122 खातों को बेचने का रिकार्ड मिला है।

कुपवाड़ा में सेना की यूनिट में गोलीबारी, तीन जवान घायल

राज्य ब्यूरो, जागरण ● श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एक सैन्य यूनिट में शनिवार आधी रात को गोलीबारी की घटना में तीन सैनिक घायल हो गए। सभी को सैन्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोप है कि एक सैन्य कर्मी ने बैरक में घुसकर कथित तौर पर साथियों पर अपनी निजी इसांस राइफल से गोलियां चला दीं। पुलिस और सेना ने जांच शुरू कर दी है। आरोपित की पहचान नाइक ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट पवन कुमार (36) के रूप में हुई है। पवन कुमार 17 वर्षों से सेना में कार्यरत हैं और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के निवासी बताए जा रहे हैं।

प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार गोलीबारी में तीन जवान घायल हुए हैं। एक जवान को पेट और पैर में गोली लगी है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। एक अन्य जवान एवी राठौर दयाल को जांघ और फीमर (जांघ की हड्डी) में गोली लगी है। सिपाही मनीष को बाएं कूल्हे में मामूली छर्रे की चोट आई है। घायल जवानों को तुरंत निकट के 168 मिलिट्री अस्पताल, ड्रगमुला (कुपवाड़ा) में भर्ती कराया।

सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपित से हथियार छीनकर हिरासत में ले लिया है। स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा, पुलिस के साथ ही सेना के अधिकारी भी मामले की जांच कर रहे हैं।

बहू पर सास-ससुर के भरण पोषण का कानूनी दायित्व नहीं: हाई कोर्ट

विधि संवाददाता, जागरण ● प्रयागराज

बेटे की मृत्यु के बाद पुलिस कांस्टेबल बहू से गुजारा भत्ता की मांग की याचिका खारिज

इलाहाबाद हाई कोर्ट। फाइल

'नैतिक दायित्व की अवधारणा भले ही कितनी मजबूत हो, वह किसी वैधानिक आदेश के अभाव में कानूनी दायित्व के रूप में लागू नहीं की जा सकती।' यह टिप्पणी करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने बहू से भरण-पोषण की मांग में दायर बुजुर्ग दंपती की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। पीठ ने कहा, बहू दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत सास-ससुर को भरण पोषण भत्ता देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। विधायिका ने अपने विवेक से उक्त प्रविधान के दायरे में सास-ससुर को शामिल नहीं किया है। दूसरे शब्दों में विधायिका की यह मंशा नहीं है कि उक्त प्रविधान के तहत बहू पर सास-ससुर के भरण-पोषण का दायित्व डाला जाए।

अगस्त 2025 में आगरा स्थित पारिवारिक न्यायालय द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद बुजुर्ग दंपती ने हाई कोर्ट में अपील की थी। सुनवाई के दौरान बुजुर्ग दंपती के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता वृद्ध व अशिक्षित हैं, और वे अपने बेटे पर निर्भर थे, जो उप्र पुलिस में कांस्टेबल थे। बेटे का विवाह 2016 में हुआ था और 2021 में मृत्यु हो गई। उनकी बहू भी उप्र पुलिस में कांस्टेबल है। बेटे की मृत्यु के बाद उसके पक्ष में देय सारे लाभों का भुगतान बहू को हुआ। कोर्ट ने कहा, पक्षों की दलीलों पर विचार करने और रिकार्ड की जांच करने पर यह स्वीकृत स्थिति है कि याचीगण प्रतिवादी बहू के ससुर व सास हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत संबंधित प्रविधानों) के अंतर्गत भरण-पोषण का दावा करने का वैधानिक अधिकार है। यह सिर्फ उन व्यक्तियों की श्रेणियों तक ही सीमित है जिनका उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है। प्रश्नगत मामले में रिकार्ड पर ऐसा कुछ नहीं है जो यह इंगित करता हो कि बहू को मिली नौकरी अनुकंपा के आधार पर थी। मृतक की संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में दी गई दलील भी धारा 125 के तहत विचारणीय नहीं है, क्योंकि ऐसे मुद्दे भरण-पोषण कार्यवाही के दायरे से बाहर हैं। पारिवारिक न्यायालय, आगरा के 21 अगस्त 2025 को पारित आदेश में कोई अवैधता, विकृति या त्रुटि नहीं है।

मणिपुर में प्रतिबंधित संगठन के चार सदस्यों की प्रतिद्वंद्वी गुट ने की हत्या

इंफाल, प्रेट्र : मणिपुर के कामजोंग जिले में एक प्रतिबंधित संगठन के चार सदस्यों की प्रतिद्वंद्वी गुट के सदस्यों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अधिकारी ने बताया कि यह घटना शनिवार रात नौ बजे होंगबेई गांव में हुई। पुलिस ने रविवार सुबह घटनास्थल पर जांच कर एनएससीएन ईस्टर्न फ्लैंक के चार सदस्यों के शव बरामद किए।

एनएससीएन ईस्टर्न द्वारा जारी बयान के अनुसार, प्रतिद्वंद्वी समूह के सदस्यों ने छह कार्यकर्ताओं को ले जा रही गाड़ी को रोककर उन पर गोलियां बरसाईं। चार सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य जान बचाने में सफल रहे।

इस बीच एएनआइ के अनुसार मणिपुर में प्रतिबंधित संगठन पीएलए और यूपीपीए के उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। मणिपुर पुलिस के अनुसार सुरक्षा बलों ने वसूली करने वाले पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी आफ कांगलेइपाक (यूपीपीके) के एक-एक कैडर को शनिवार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए पीएलए कैडर की पहचान थोकचोम खेलजीत मैतेयी उर्फ कैनी के रूप में हुई है। उसके पास से मोबाइल फोन भी मिला है। यूपीपीके कैडर की पहचान इंफाल पूर्वी जिले के खारीबाम बोयनाओ मैतेयी के रूप में हुई है। ज्ञात हो, मणिपुर में हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं।

गोवा यौन शोषण में दो बहनें भी पीड़ित: पुलिस

पणजी, प्रेट्र : गोवा के एक पार्षद के बेटे से जुड़े यौन शोषण की जांच में यह सामने आया है कि उसने कई पीड़ितों का शोषण किया। इनमें दो बहनें भी हैं, जिनमें से एक नाबालिग है। अब तक 20 वर्षीय आरोपित सोहम नाइक की प्रेमिका सहित चार महिलाओं ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। क्राइम ब्रांच ने इस संबंध में चार लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, जिनमें दो नाबालिग हैं। पीड़ितों का दावा किया है कि उन्हें गोवा के कुशवाटी जिले के कचोरेम नगरपालिका परिषद के पार्षद के बेटे नाइक ने यौन शोषण का शिकार बनाया। पुलिस ने 22 मार्च को नाइक को कई लड़कियों से दुष्कर्म करने और उनके अश्लील वीडियो प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपित के खिलाफ बच्चों के पाक्सो अधिनियम, गोवा चिल्ड्रन एक्ट, बीएनएस व सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

संघ का लक्ष्य भारत को समरस, समर्थ और सशक्त बनाना: होसबाले

जागरण संवाददाता, धर्मशाला

दत्तात्रेय होसबाले।

हिमाचल में आरएसएस सरकार्यवाह बोले, देश के विकास के लिए सभी का योगदान जरूरी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने रविवार को धर्मशाल में प्रबुद्धजन संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा, संघ का लक्ष्य भारत को समरस, समर्थ व समर्थ बनाना है। संघ ने अपने कार्य की 100 वर्षों की यात्रा पूर्ण की है। इस अवधि में संघ ने सेवा एवं समर्पण भाव से देश सेवा एवं राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है।

होसबाले ने कहा, स्वतंत्रता सेनानी एवं संघ संस्थापक डा. केशव बलिराम हेडगेवार ने भारत को स्वतंत्र एवं शक्तिशाली बनाने के लिए 1925 को विजयादशमी के दिन संघ का कार्य प्रारंभ किया था। संघ राष्ट्र हित में व्यक्तिगत चरित्र और राष्ट्रीय चरित्र दोनों को ठीक करने की दृष्टि से काम कर रहा है। कहा, समाज की उन्नति के लिए समाज को संगठित करना, सामूहिक प्रयास करना व सबको साथ लेकर चलना अति आवश्यक है। देश के सर्वांगीण विकास में सभी का योगदान होना चाहिए।

होसबाले ने कहा, संघ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त कर समाज के लिए कार्य करता है। संघ सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन है। संघ कार्यकर्ताओं के लिए जीवन शैली है। आज देश में एक लाख से अधिक सेवा कार्य चल रहे हैं। एक लाख से अधिक स्थानों पर शाखा मिलन संघ मंडली चल रही हैं।

पंजाब में पाकिस्तान निर्मित दो सब मशीनगन बरामद, दो बदमाश फरार

जागरण संवाददाता, अमृतसर: पंजाब पुलिस ने रविवार सुबह कोट खालसा इलाके में नाकाबंदी के दौरान पाकिस्तान निर्मित दो सब मशीन गन बरामद कीं। हालांकि, हथियार लेकर जा रहे बाइक सवार दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए।

पुलिस ने बताया कि कोट खालसा इलाके में पुलिस टीम ने बाइक सवार दो युवकों को रुकने का इशारा किया। आरोपितों ने बाइक को भगाने का प्रयास किया। इस दौरान उनकी बाइक पर रखा बैग गिर गया। टीम ने जब बैग की तलाशी ली तो उसमें पाकिस्तान निर्मित एमपी-फाइव सब मशीन गन बरामद की गई। बरामद दोनों हथियारों की मारक क्षमता काफी है। एक बार में वह कई राउंड फायर कर सकती है। दावा किया कि ये हथियार यूरोप से गैंग चला रहे पटियाला के राजपुरा निवासी कुख्यात गैंगस्टर गुरप्रीत सिंह उर्फ गोल्डी ढिल्लों ने ड्रोन से भारतीय सीमा में गिरवाए थे।

बाघ व तेंदुओं की पहचान अब माइक्रो चिप से होगी

जागरण संवाददाता, लखीमपुर

प्रयोग के तौर पर लखीमपुर के मझगई रेंज में पकड़ी गई मादा तेंदुए से शुरुआत

पलिया के मझगई रेंज में पकड़ी गई मादा तेंदुए का फाइल फोटो जागरण >>

पलियाकलां के मझगई रेंज के लोहरा वीरान से पकड़ी गई मादा तेंदुआ की पहचान अब उसके कान के पास लगे माइक्रो चिप से की जाएगी। यह प्रदेश में पहली बार है जब किसी वन्यजीव को जंगल में छोड़ने के पहले चिप लगाई गई है। प्रयोग सफल रहा तो अन्य वन्यजीवों को भी इसी तरह चिप लगाई जाएगी। यह चिप ट्रैकिंग डिवाइस नहीं है। यह सिर्फ वन्यजीवों की पहचान बताने का कार्य करेगी।

दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर डा. एच राजामोहन ने बताया कि ग्रामीणों पर हमला करने वाले बाघ और तेंदुओं को दूरदराज के जंगलों में इसलिए छोड़ा जाता है ताकि वे पुनः उसी इलाके में लौटकर उत्पात न मचाएं। पहले इन वन्यजीवों के गले में कालर आइडी लगाई जाती थी,जो महंगी व वन्यजीवों के लिए असुविधाजनक होती थी। एक कालर आइडी की लागत करीब पांच लाख रुपये होती थी। इसलिए, माइक्रो चिप लगाने का निर्णय लिया गया है, जो सस्ती और अधिक सुविधाजनक है। मझगई रेंज से पकड़ी गई मादा तेंदुआ में पहली बार चिप लगाई गई है।इसका परिणाम सकारात्मक रहा, तो भविष्य में सभी बाघ और तेंदुओं में चिप लगाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि माइक्रो चिप ट्रैकिंग डिवाइस नहीं है, इसलिए वन्यजीव की लोकेशन ट्रेस नहीं की जा सकती। लेकिन, यदि वन्यजीव कहीं पकड़ा जाता है या मृत पाया जाता है, तो इसकी पहचान की जा सकती है। जंगल से पकड़ कर जंगल में छोड़े जाने वाले वन्यजीवों के शरीर में ही चिप लगाई जाएगी। यह ध्यान देने योग्य है कि चिड़ियाघर या सफारी में भेजे जाने वाले वन्यजीवों को चिप नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि उनकी पहचान पहले से ही रखी जाती है।

लीची के वर्षों पुराने पेड़ों को दिया नया जीवन, बढ़ी किसानों की आय

जागरण विशेष पद्म विभूति

अमरेंद्र तिवारी ● जागरण

पद्मश्री डा. गोपालजी त्रिवेदी की 'कैनोपी मैनेजमेंट' तकनीक बनी किसानों के लिए वरदान

जलजमाव वाले क्षेत्र को मत्स्य आधारित खेती में बदला, सुधरा भूजल स्तर

कैनोपी मैनेजमेंट तकनीक से लीची के पुराने पेड़ में कटाई छंटाई करते श्रमिक ● सौ. बिहार लीची उत्पादक संघ

मुजफ्फरपुर: विज्ञान और इंजीनियरिंग श्रेणी में पद्मश्री से सम्मानित कृषि विज्ञानी डा. गोपालजी त्रिवेदी की उम्र भले ही 95 वर्ष है, लेकिन खेती में कुछ नया करने और इसे लाभकारी बनाने का जज्बा युवाओं जैसा है। वह आज भी किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने, उत्पादन बढ़ाने और आय में वृद्धि के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी 'कैनोपी मैनेजमेंट' तकनीक लीची उत्पादकों के लिए वरदान साबित हुई है।

डा. गोपालजी ने लीची उत्पादन के लिए मशहूर मुजफ्फरपुर के पुराने बागों को नया जीवन देने में अहम भूमिका निभाई। उनकी 'कैनोपी मैनेजमेंट' तकनीक के इस्तेमाल से वर्षों पुराने पेड़ों को हटाए बिना ही नए पेड़ की तरह उपज प्राप्त होने लगती है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक डा. विकास दास का कहना है कि इस तकनीक से बिहार में करीब पांच हजार हेक्टेयर में बागों को पुनर्जीवन मिला है। इससे गुणवत्ता बेहतर होने के साथ उपज भी बढ़ी है। मुजफ्फरपुर में करीब 12 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में लीची की खेती होती है। समय के साथ बहुत से बाग काफी पुराने हो गए। इस कारण लीची का उत्पादन कम हो गया। नए बाग लगाने के लिए जगह की जरूरत पड़ती। उन्हें लगाने के कई वर्षों बाद लीची की उपज आती। इन समस्याओं को देखते हुए कृषि विज्ञानी डा. गोपालजी त्रिवेदी ने वर्ष 2003 में कैनोपी मैनेजमेंट तकनीक की शुरुआत की। उन्होंने प्रारंभिक चरण में अपने बाग के 10 पेड़ों पर इसका प्रयोग किया तो उपज सवा क्विंटल तक बढ़ गई। बिहार लीची उत्पादक संघ के अध्यक्ष व किसान बच्चा प्रसाद सिंह का कहना है कि उन्हें जिस पुराने पेड़ से 100 किलो फल मिलता था, इस तकनीक को अपनाने से 110 से 115 किलो तक फल मिल रहा है।

पुराने पेड़ों के लिए बेहद फायदेमंद

'कैनोपी मैनेजमेंट' एक उन्नत कृषि तकनीक है, जो 40-50 साल से अधिक पुराने व अनुत्पादक पेड़ों के लिए बेहद फायदेमंद है। इसमें बहुत घने पेड़ों को काट-छांट कर छोटा (1.5 मीटर की ऊंचाई तक) किया जाता है। बाद में पेड़ को गोबर की खाद के अलावा अन्य पोषक तत्व दिए जाते हैं। इससे स्वस्थ व फल देने वाली नई शाखाएं तेजी से निकलती हैं। घनी टहनियां हटाने से कीड़ों व बीमारियों का प्रकोप कम हो जाता है। सूरज की रोशनी पेड़ के अन्य हिस्सों तक पहुंचती है।

डा. गोपालजी त्रिवेदी

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

रायपुर एम्स में दो एमबीबीएस छात्र एआइ से नकल करते पकड़े गए

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया ● रायपुर

चप्पलों में मोबाइल छिपाकर परीक्षा कक्ष में पहुंचे थे दोनों आरोपित

नकल करते दो छात्रों को पकड़ा गया है। जांच कमेटी बनाई गई है। रिपोर्ट आने पर एम्स के नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
-डा. मृत्युंजय राठौर, पीआरओ, एम्स

रायपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में एमबीबीएस परीक्षा के दौरान नकल का मामला सामने आया है। करीब एक सप्ताह पहले परीक्षा में शामिल दो अभ्यर्थी आधुनिक तरीके से नकल करते पकड़े गए। दोनों चप्पलों (सैंडल) में मोबाइल छिपाकर परीक्षा कक्ष पहुंचे थे लेकिन परीक्षक की सतर्कता से उनके नकल करने की योजना फेल हो गई। एम्स प्रबंधन ने मामले में जांच कमेटी गठित की है।

एम्स परिसर स्थित मेडिकल कालेज में एमबीबीएस की परीक्षा चल रही थी। परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर सख्त तलाशी के बावजूद आरोपित दोनों छात्र मोबाइल अंदर ले जाने में सफल रहे। परीक्षा शुरू होते ही प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) से हल किया और उत्तर लिखने लगे। परीक्षक को उनकी गतिविधियों पर संदेह हुआ। जांच करने उनके पास से मोबाइल बरामद हुए। परीक्षक ने इसकी जानकारी प्रबंधन को दी। दोनों परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र से बाहर कर दिया गया। बताया गया कि अभ्यर्थियों ने चप्पल के निचले हिस्से को काटकर उसमें मोबाइल रखने की जगह बनाई थी।

पश्चिम एशिया की जंग बनेंगे नए समीकरण

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच पिछले करीब एक महीने से जारी जंग कुछ हफ्तों में खत्म हो जाए या महीनों के बाद बंद हो। इसने दुनिया के भू-राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव की बुनियाद रख दी है। साफ है कि दुनिया अब उस तरह से नहीं रहेगी, जैसी युद्ध शुरू होने से पहले थी। ऐसा पहली बार हुआ है जब यूरोप के देशों ने जंग में अमेरिका का साथ देने से साफ मना कर दिया है। यह तब है जब अमेरिका और यूरोप के देश सैन्य संगठन नाटो के सदस्य हैं और यूरोप अपनी सुरक्षा की जरूरतों के लिए काफी हद तक अमेरिका पर निर्भर है। जंग में अमेरिका के सहयोगी खाड़ी देशों के ऊर्जा ढांचे को गंभीर नुकसान हुआ है और इससे उबरने में उनको एक दशक तक का समय लग सकता है। ये देश लंबे समय से अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर भरोसा करते थे और अमेरिका के सैन्य अड्डे भी इन देशों में हैं। यह युद्ध पश्चिम एशिया में अमेरिका के करीब पांच दशक के प्रभुत्व के अंत की शुरुआत भी हो सकता है। जंग वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य में किस तरह के बदलाव ला सकती है और भारत की इसमें क्या भूमिका होगी, इसकी पड़ताल अहम मुद्दा है...

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसे बदल गई थी दुनिया

द्वितीय विश्व युद्ध (1939-1945) ने पिछली सदियों से चले आ रहे वैश्विक ढांचे को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया और एक नया वर्ल्ड आर्डर स्थापित किया। इस युद्ध के बाद दुनिया राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से वैसी नहीं रही, जैसी पहले थी।

दो महाशक्तियों का उदय

युद्ध से पहले दुनिया 'बहुध्रुवीय' थी, जहां ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान मुख्य शक्तियां थीं।

यूरोप का पतन: युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश आर्थिक और सैन्य रूप से इतने कमजोर हो गए कि वे दुनिया पर अपना दबदबा खो बैठे।

महाशक्तियों का उदय: विश्व मंच पर केवल दो महाशक्तियां बचीं। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। इसने दुनिया को 'द्विध्रुवीय' बना दिया।

शीत युद्ध की शुरुआत

फासीवाद को हराने के बाद, पूर्व मित्र राष्ट्र (अमेरिका और सोवियत संघ) आपस में ही भिड़ गए। यह शीतयुद्ध 1990 में सोवियत संघ के विघटन के बाद ही खत्म हुआ।

वैचारिक संघर्ष: यह लोकतंत्र/पूंजीवाद (अमेरिका) बनाम साम्यवाद (सोवियत संघ) की लड़ाई थी।

सैन्य गुट: दुनिया दो खेमों में बंट गई। पश्चिमी देशों का नाटो और वारसा पैक्ट (पूर्वी ब्लाक)। अगले 45 वर्षों तक पूरी दुनिया की राजनीति इसी संघर्ष के इर्द-गिर्द घूमती रही।

उपनिवेशीकरण का खात्मा और नए देशों का जन्म

- युद्ध ने साम्राज्यवादी शक्तियों की कमर तोड़ दी थी। वे अब अपने उपनिवेशों पर नियंत्रण रखने में असमर्थ थे।
- इसके परिणामस्वरूप एशिया और अफ्रीका में स्वतंत्रता की लहर दौड़ी।
- भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और बाद में दर्जनों अफ्रीकी देश आजाद हुए। इसने वैश्विक मानचित्र को पूरी तरह बदल दिया और 'तीसरी दुनिया' के देशों का उदय हुआ।

संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना

युद्ध की तबाही को देखते हुए दुनिया के नेताओं ने महसूस किया कि भविष्य में ऐसे युद्धों को रोकने के लिए एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय संस्था की जरूरत है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। सुरक्षा परिषद के माध्यम से दुनिया के पांच बड़े देशों अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस को विशेष शक्तियां (वीटो) दी गईं, जो आज भी वैश्विक व्यवस्था का आधार है।

नई वैश्विक आर्थिक व्यवस्था

युद्ध के बाद विश्व अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने के लिए 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ।

आइएमएफ और विश्व बैंक

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुई ताकि देशों को पुनर्निर्माण के लिए कर्ज मिल सके।

अमेरिकी डालर का दबदबा

अमेरिकी डालर दुनिया की प्रमुख आरक्षित मुद्रा बन गई। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अमेरिका का नियंत्रण स्थापित हो गया।

परमाणु युग और सुरक्षा की नई परिभाषा

अगस्त 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराने के साथ ही युद्ध का स्वरूप बदल गया।

परमाणु प्रतिरोध

अब शक्ति का पैमाना यह नहीं था कि किसके पास कितनी बड़ी सेना है, बल्कि यह था कि किसके पास परमाणु हथियार हैं। इसने बड़ी शक्तियों के बीच सीधे युद्ध को रोक दिया, क्योंकि दोनों को पता था कि युद्ध का मतलब पूर्ण विनाश होगा।

मानवाधिकार और अंतरराष्ट्रीय कानून

- होलोकास्ट (यहूदियों का नरसंहार) जैसी घटनाओं ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया।
- 1948 में 'मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा' को अपनाया गया।
- युद्ध अपराधों के लिए नूर्नबर्ग ट्रायल हुए, जिसने यह स्थापित किया कि युद्ध के दौरान भी मानवता के विरुद्ध अपराध करने वालों को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सजा दी जा सकती है।

सामने आए वैश्विक प्रभुत्व के नए खिलाड़ी

जागरण रिसर्च

क्षेत्र	युद्ध से पहले (पुराना क्रम)	युद्ध के बाद (नया क्रम)
सत्ता का केंद्र	पश्चिमी यूरोप (लंदन, पेरिस, बर्लिन)	अमेरिका और सोवियत संघ
राजनीति	साम्राज्यवाद (उपनिवेशवाद)	स्वतंत्र राष्ट्र और शीत युद्ध
अर्थव्यवस्था	सोने पर आधारित व्यापार	डालर पर आधारित 'ब्रेटन वुड्स' सिस्टम
सुरक्षा	गुप्त संधियां	संयुक्त राष्ट्र और सामूहिक सुरक्षा

आकार लेगी नई वैश्विक व्यवस्था

डा. अभिषेक श्रीवास्तव
असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल आफ इंटरनेशनल स्टडीज, जेएनयू

पश्चिम एशिया की जंग के बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रह जाएगी। क्षेत्र में अमेरिका का प्रभुत्व कमजोर होगा और यहां कई देशों का प्रभाव बढ़ सकता है। वैश्विक स्तर पर भी नए व्यवस्था आकार ले सकती है जिसमें भारत जैसी उभरती वैश्विक ताकतें अहम भूमिका निभा सकती हैं।

पश्चिम एशिया में चल रहा ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच का संघर्ष अब केवल एक सामान्य युद्ध नहीं रह गया है, बल्कि यह पूरे क्षेत्र की राजनीति, सुरक्षा व्यवस्था और वैश्विक संतुलन को बदलने वाला निर्णायक मोड़ बन चुका है। यह युद्ध आने वाले समय में नई भू-राजनीतिक व्यवस्था की नींव रख रहा है। इसके प्रभाव केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि भारत सहित पूरी दुनिया इसकी चपेट में आएगी।

पिछले कई दशकों से पश्चिम एशिया में सीधे युद्ध कम होते थे। देश अपने-अपने समर्थित संगठनों के जरिये लड़ते थे। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। ईरान और अमेरिका-इजरायल सीधे आमने-सामने हैं। ईरान ने हिज्बुल्ला और हाउती जैसे संगठनों के माध्यम से इस युद्ध को कई मोर्चों पर फैला दिया है। अब तक पश्चिम एशिया की स्थिरता तीन चीजों पर टिकी थी, पहली अमेरिका की ताकत और दबदबा, जो अब पहले जैसा नहीं रहा। इतनी बड़ी सैन्य शक्ति होने के बावजूद अमेरिका ईरान को पूरी तरह रोक नहीं पा रहा है। इससे उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी, ऊर्जा सुरक्षा, जो अब खतरे में है। होर्मुज जलडमरूमध्य, जहां से दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है, अब तनाव का केंद्र बन गया है। यदि यहां की रुकावट को जल्द समाप्त नहीं किया गया तो पूरी दुनिया में तेल को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। तीसरा, क्षेत्रीय गठबंधन। गठबंधन अब टूट रहे हैं। कई देश अब अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर रहने से हिचक रहे हैं और विकल्प तलाश रहे हैं। इसका परिणाम यह होगा कि पश्चिम एशिया अब बहुध्रुवीय शक्तियों का केंद्र बनेगा, जहां कोई एक देश इस क्षेत्र को पूरी तरह नियंत्रण में नहीं रख पाएगा। यह युद्ध अमेरिका के लिए एक बड़ी रणनीतिक परीक्षा बन गया है। एक ओर उसे पश्चिम एशिया में ईरान और इजरायल से जुड़े संघर्ष में सक्रिय रहना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना भी उसकी प्राथमिकता है।

इस दोहरे दबाव के कारण अमेरिका पर अधिक बोझ की स्थिति बनती जा रही है। उसके प्रमुख सहयोगी देश जैसे जापान और दक्षिण कोरिया भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं अमेरिका का ध्यान उनके क्षेत्र से हट न जाए। यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। अमेरिका की वैश्विक छवि कमजोर पड़ सकती है, चीन को अपने प्रभाव को विस्तार देने का अवसर मिल सकता है, और दुनिया का शक्ति संतुलन धीरे-धीरे बदल सकता है। इस पूरे संघर्ष का भारत पर भी गहरा प्रभाव पड़ना तय है। सबसे पहले ऊर्जा सुरक्षा की बात करें, तो भारत अपनी लगभग 85 प्रतिशत तेल की जरूरत आयात के माध्यम से पूरी करता है। इसका बड़ा बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है। यदि युद्ध के कारण तेल आपूर्ति में बाधा आती है, तो भारत में महंगाई और आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। इसलिए भारत को अब ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण करना होगा, रणनीतिक भंडारण क्षमता बढ़ानी होगी और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ना होगा। कूटनीतिक स्तर पर भी भारत के सामने संतुलन बनाए रखने की चुनौती है। भारत के अमेरिका, इजरायल और ईरान—तीनों के साथ अच्छे संबंध हैं, इसलिए उसे किसी एक पक्ष में खुलकर जाने के बजाय अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखनी होगी। भारत को एक संतुलित और व्यावहारिक नीति अपनानी होगी, जिससे वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए शांति स्थापित करने में भी सकारात्मक भूमिका निभा सके। व्यापार और संपर्क के संदर्भ में भी यह युद्ध नई संभावनाएं और चुनौतियां लेकर आया है। चाबहार बंदरगाह, इंटरनेशनल नार्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कारिडोर जैसे प्रोजेक्ट भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये वैकल्पिक व्यापार मार्ग प्रदान करते हैं। ऐसे समय में जब पारंपरिक समुद्री मार्ग असुरक्षित हो सकते हैं, ये परियोजनाएं भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत कर सकती हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी भारत को सतर्क रहना होगा। इस युद्ध के कारण समुद्री सुरक्षा, साइबर हमलों और कट्टरपंथी संगठनों की गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है। इसलिए भारत को अपनी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना होगा तथा आधुनिक खतरों के अनुरूप अपनी रणनीति का पुनर्निर्धारण करना होगा।

ईरान और अमेरिका-इजरायल संघर्ष ने पश्चिम एशिया की पूरी राजनीतिक और सुरक्षा संरचना को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह युद्ध केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, बल्कि एक नए वैश्विक दौर की शुरुआत का संकेत है। इसमें अमेरिका का एकाधिकार धीरे-धीरे कमजोर हो रहा है। क्षेत्रीय शक्तियां अधिक प्रभावशाली हो रही हैं और ऊर्जा व व्यापार मार्गों का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। अब पश्चिम एशिया में स्थिरता बाहरी शक्तियों द्वारा थोपी नहीं जा सकती, बल्कि यह क्षेत्रीय संतुलन और आपसी समझ के माध्यम से ही संभव होगी। भारत को दूरदर्शिता और संतुलित रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए तभी वह राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के साथ वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को और सशक्त बना सकता है।

आपकी आवाज

पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने से पहले ही वैश्विक व्यवस्था में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इस युद्ध ने इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। जंग थमने के बाद भी इसके नतीजे बहुआयामी होंगे। यह दुनिया में अमेरिकी दबदबे को खत्म करने वाला निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है और पश्चिम एशिया में भी नए समीकरण आकार ले सकते हैं। **प्रभात वर्मा**

पश्चिम एशिया का युद्ध ईरान को बरबाद करने के साथ पूरी दुनिया को खतरनाक मंदी की चपेट में लाने की क्षमता रखता है। अगर यह युद्ध लंबा चला तो पूरी दुनिया आर्थिक संकट में फंस जाएगी। भू राजनीतिक मोर्चे पर भी बड़े बदलाव हो सकते हैं क्योंकि ऐसा पहली बार है जब अमेरिका के सहयोगी नाटो देशों ने इस युद्ध में अमेरिका का साथ देने से मना कर दिया है। जाहिर है कि अब इन देशों को अमेरिका पर भरोसा नहीं रह गया है। वैश्विक रक्षा गठजोड़ के लिहाज से इसके मायने बहुत बड़े हैं। **सरोज तिवारी**

ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका अगर ईरान से लंबे संघर्ष में फंस जाता है तो इससे रूस और चीन दोनों को फायदा होगा। तेल की कीमतें बढ़ने से रूस आर्थिक रूप से मजबूत होगा और अमेरिका के संसाधन बरबाद होने से चीन को फायदा होगा क्योंकि वह चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। जंग थमने के बाद पश्चिम एशिया में चीन अपना प्रभाव और बढ़ा सकता है क्योंकि यहां के देश अब अपनी सुरक्षा के लिए नए क्षेत्रीय गठजोड़ की संभावनाएं तलाशने को मजबूर होंगे। **रामलाल मौर्य**

इस युद्ध का व्यापक असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। ट्रंप की टैरिफ नीति से दुनिया के देश पहले से ही नाराज हैं। ऐसे में व्यापार के और सप्लाई चेन के मोर्चे पर भी देश नए सिरे से अपनी रणनीति बनाने के लिए काम कर सकते हैं। भारत के लिए भी यह बदलाव अहम होंगे क्योंकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और निर्यात बढ़ाने के लिए वैश्विक बाजार की स्थिरता बेहद अहम है। **हाशिम**

वैश्विक अर्थव्यवस्था की टूटेगी कमर

ईरान युद्ध 28 फरवरी को ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या के साथ शुरू हुआ। किसी को भी खासकर अमेरिका को यह उम्मीद नहीं थी कि यह एक महीने तक चलेगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक टेलीफोन पर मुश्किल बातचीत की। जाहिर तौर पर उन्होंने इस बात की शिकायत की कि इजरायल ने ईरानी प्रतिरोध को गलत समझा और वहां कोई जन-विद्रोह नहीं हुआ। यह युद्ध अब एक निर्णायक मोड़ पर है।

अमेरिका और इजरायल दोनों को यह एहसास हो गया है कि ईरान पर लगातार हवाई हमले करने के बावजूद वे ड्रोन और मिसाइलों से जवाबी हमला करने की ईरान की क्षमता को खत्म करने में नाकाम रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में युद्ध के बढ़ते विरोध और युद्धविराम स्वीकार करने से पहले ईरान से रियायतें हासिल करने की कोशिश के बीच फंस गए हैं। इस बीच, मिस्र, पाकिस्तान और तुर्की मध्यस्थता कर रहे हैं और युद्धविराम के प्रस्तावों के आदान-प्रदान में मदद कर रहे हैं। अमेरिका का 15-सूत्रीय प्रस्ताव उसके पुराने एजेंडे को दर्शाता है। इसमें मांग की गई है कि ईरान अपना परमाणु संवर्धन कार्यक्रम छोड़ दे, यह वादा करे कि वह कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा, इस क्षेत्र में अपने प्राक्सी (समर्थक गुटों) को समर्थन देना बंद कर दे और होर्मुज जलडमरूमध्य से मुक्त आवागमन बहाल करे। इसमें ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने का सुझाव भी दिया गया है, ताकि मांगों को नरम बनाने के लिए एक संभावित प्रलोभन दिया जा सके।

खबरों के मुताबिक, ईरान अभी-अभी मध्यस्थों को अमेरिका के प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। वैसे भी, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने हाल ही में एक साक्षात्कार में ईरान का पक्ष स्पष्ट किया। ईरान परमाणु हथियार हासिल न करने का वादा करने और अपने अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आइएईए) को सौंपने के लिए तैयार है।

केसी सिंह
पूर्व राजदूत

पश्चिम एशिया के युद्ध की वजह से पहले ही दुनिया ऊर्जा संकट का सामना कर रही है। अगर यह युद्ध और लंबा खिंचता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था बहुत बड़े संकट में फंस जाएगी। भू राजनीतिक परिदृश्य के लिहाज से इसके दूरगामी परिणाम होंगे और देशों के बीच नए गठबंधन और समीकरण उभर सकते हैं।

हालांकि, वह आइएईए की देखरेख में अपना नागरिक परमाणु कार्यक्रम जारी रखना चाहता है। वह हवाई हमलों से हुई तबाही के लिए हर्जाना भी चाहता है। सबसे बढ़कर, वह होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। अंत में, ईरान यह वादा चाहता है कि उस पर फिर कभी कोई हमला नहीं होगा। अमेरिका और ईरान की मांगों के बीच कुछ अंतर हैं। युद्ध शुरू होने से पहले ओमान की मेजबानी में हुई बातचीत में इनमें से कई मुद्दे लगभग सुलझ गए थे। हालांकि, कुछ मुद्दे युद्ध के कारण पैदा हुए हैं। सबसे पहले, ईरान ने युद्ध के नकारात्मक प्रभाव को फैलाने के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य से समुद्री यातायात को बाधित कर दिया। ऊर्जा की कीमतें तुरंत बढ़ गईं और वैश्विक शेयर बाजार धड़ाम से गिर गए। अकेले अमेरिकी शेयर बाजार में लगभग 5 ट्रिलियन डालर का नुकसान हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान में नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमले पर लगी रोक को 6 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। दुर्भाग्य से, इजरायल इस रोक का उल्लंघन कर रहा है। इजरायल ने ईरान के दो बड़े स्टील उत्पादन केंद्रों पर हमला किया, जिससे ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। अमेरिका ने भी इस इलाके में अपने मरीन सैनिक भेज दिए हैं, जिससे ईरान के अहम द्वीपों और तटों पर ज़मीनी हमले का खतरा बना हुआ है। ऐसी अपुष्ट खबरें भी हैं कि ईरान ने कुवैत के एक द्वीप पर उन पर हमला किया है। अमेरिकियों की 'कैरेट और स्टिक' वाली नीति शायद काम कर जाए, लेकिन इजरायल ईरान के आम नागरिकों के बुनियादी ढांचे पर बड़े हमले करके इस कोशिश को नाकाम कर रहा है।

सबसे अच्छा नतीजा यह होगा कि अमेरिका और ईरान जल्द से जल्द युद्धविराम पर सहमत हो जाएं और इजरायल को भी इसे मानने के लिए मजबूर होना पड़े। अगर युद्ध और लंबा खिंचता है तो दुनिया भर में ऊर्जा और आर्थिक संकट और भी गहरा जाएगा। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था बहुत बड़े संकट में फंस जाएगी। भारत के लिए खाड़ी क्षेत्र में शांति का मतलब सिर्फ तेल और गैस की आपूर्ति से कहीं ज़्यादा है। सबसे पहले खाड़ी देशों में रहने वाले एक करोड़ भारतीयों की सुरक्षा आती है। इस क्षेत्र लगातार अस्थिरता से लोगों की नौकरियां जाएंगी, और इसके चलते यहां से आने वाली विदेशी मुद्रा में भी कमी आएगी। इसका असर भारत के निर्यात पर भी पड़ेगा, क्योंकि खाड़ी देश भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से हैं।

आजादी के बाद गुटनिरपेक्षता की नीति से भारत को ईरान-इराक युद्ध जैसे कई क्षेत्रीय संकटों से निकलने में मदद मिली। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत की छवि निष्पक्ष देश की रही। मौजूदा हालात में खतरा यह है कि अगर भारत को किसी एक पक्ष का समर्थक माना गया, तो इसके दूरगामी नुकसान हो सकते हैं। भारत के ईरान के साथ बहुत पुराने भाषाई और सांस्कृतिक संबंध हैं। वहीं, इजरायल मजबूत रक्षा साझेदार है। अटल बिहारी वाजपेयी ने ईरान और इजरायल के साथ भारत के संबंधों में बेहतरीन संतुलन बनाए रखा था। भारत की कूटनीति को उसी छवि को फिर से बहाल करने की जरूरत है।

राष्ट्रीय फलक

मुस्लिमों पर भी लागू होता है संरक्षक व प्रतिपाल्य अधिनियम : हाई कोर्ट

विधि संवाददाता, जागरण • प्रयागराज

- कहा, नाबालिग की अभिरक्षा को मुस्लिम भी इसके जरिये न्याय के हकदार

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम कानून से शासित होने वाले पक्षकार भी अपने नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा प्राप्त करने के लिए संरक्षक व प्रतिपाल्य अधिनियम का सहारा ले सकते हैं। न्यायमूर्ति अनिल कुमार ने कहा,यह अधिनियम धर्म पर ध्यान दिए बिना सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। मुस्लिम पर्सनल ला के तहत आने वाले लोग भी इसके माध्यम से राहत पाने के हकदार हैं।

याची रिजवाना ने अपने दो नाबालिग बच्चों 10 वर्षीय अबू हसन और पांच वर्षीय कनीज फातिमा की अभिरक्षा के लिए हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। उसका तर्क था कि मुस्लिम कानून के अनुसार, सात वर्ष से कम आयु के बालक और नाबालिग लड़की की अभिरक्षा का अधिकार मां के पास होता है। अधिनियम की धारा-6 के प्रविधानों के चलते मुस्लिम पक्षकारों पर 'संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम' प्रभावी नहीं होता, इसलिए अभिरक्षा का विवाद केवल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के जरिये तय किया जा सकता है।

न्यायमूर्ति अनिल कुमार ने कहा कि 'संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम' की धारा-6 किसी भी वर्ग, धर्म के व्यक्ति को अदालत जाने से नहीं रोकती, बल्कि यह विभिन्न श्रेणियों के अभिभावकों को मान्यता देने का काम करती है।उन्होंने स्पष्ट किया कि 'अभिभावक' शब्द की परिभाषा काफी व्यापक है। इसमें बच्चे की 'अभिरक्षा का अधिकार भी शामिल है। कहा कि व्यक्तिगत कानून केवल अदालत का मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन अभिरक्षा तय करने का सबसे प्रमुख आधार बच्चे का कल्याण ही होता है।

रोटी पर थूकने वाले शाहबाज पर एक लाख का जुर्माना

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी : उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गत वर्ष अक्टूबर में जायका रेस्टोरेंट में रोटी बनाते समय उस पर थूकने के मामले में अपर जिलाधिकारी मुक्ता मिश्र की कोर्ट ने आरोपित दुकानदार शाहबाज खान पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा से जुड़े चार अन्य मामलों का भी निस्तारण किया। खाद्य निर्माता कंपनी और विक्रेता पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मार्च 2022 में बड़थी बाईपास पर मिले पारस पनीर में फैट की मात्रा कम पाई गई थी, जिसके लिए गाजियाबाद स्थित कंपनी वीआरएस फूड्स लिमिटेड पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मार्च 2021 में नौगांव से किंग्स रिफाइंड तेल अधोमानक घोषित किया गया था, जिसके लिए अदानी विल्मर कंपनी पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। मार्च 2023 में डे-लाइट सरसों का तेल अधोमानक घोषित होने पर तपन एग्रो इंडस्ट्रियल कंपनी पर भी तीन लाख का जुर्माना लगाया गया है।

उप्र में प्रीपेड मीटर का 'करंट', निगेटिव बैलेंस ने छीनी उपभोक्ताओं की नींद

जागरण टीम, लखनऊ

- बिना चेतावनी और पुराने बिल की जानकारी के बिजली काटने की हो रही शिकायत
- वाराणसी में बिजली निगम के टोल फ्री नंबर 1912 पर आसानी से नहीं होती सुनवाई

प्री पेड मीटर। फाइल

यह है प्रमुख समस्या

- बिल जमा करने पर भी बिजली जुड़ने में 24 से 72 घंटे तक का समय लग रहा है
- स्मार्ट मीटर को प्रीपेड में बदलने की जानकारी उपभोक्ताओं को पहले नहीं दी जा रही है
- टोल-फ्री नंबर 1912 अक्सर काम नहीं करता, जिससे उपभोक्ताओं की सुनवाई नहीं हो पा रही है
- बिल जमा करने पर भी बकाया बताकर बिजली काटी जा रही है। अधिकारी नहीं दे रहे संतोषजनक जवाब
- बिना किसी मैसेज या चेतावनी के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। भुगतान के बाद भी अतिरिक्त बकाया दिख रहा है

उत्तर प्रदेश में बिजली के स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया कई उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का कारण बन रही है। कहीं बिना सूचना के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, तो कहीं भुगतान के 36 घंटे बाद भी आपूर्ति बहाल नहीं हो पा रही है। हजारों लोग अंधेरे में रहने को बाध्य हो रहे हैं। लखनऊ में तीन लाख मीटर प्रीपेड किए जा चुके हैं। हरदोई, बाराबंकी और लखीमपुर के उपभोक्ताओं का आरोप है कि बिना पूर्व सूचना के मीटर प्रीपेड कर दिए गए, जिससे अचानक बिजली गुल हो रही है। जब तक यूपीपीसीएल के खाते में पैसा नहीं दिखता, तब तक घंटों बिजली नहीं आती। ऐसी ही शिकायत पर अलीगढ़ में चीफ इंजीनियर पंकज अग्रवाल को 25 मार्च को निलंबित किया जा चुका है।

गोरखपुर में दो लाख 20 हजार उपभोक्ताओं का मीटर प्रीपेड मोड पर संचालित किया जा रहा है। ज्यादातर उपभोक्ताओं के मोबाइल फोन पर निगेटिव बैलेंस होने और बिजली कटने के पहले चेतावनी का संदेश नहीं आ रहा है। वाराणसी में टोल फ्री नंबर 1912 कनेक्ट न होने की शिकायत आ रही है। यहां लगभग साढ़े आठ लाख उपभोक्ताओं में 1.10 लाख उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर को प्रीपेड में बदला जा चुका है। अचानक बैलेंस जीरो दिखाकर किसी पूर्व सूचना के बिना आपूर्ति बंद कर दी जा रही है। प्रीपेड सिस्टम में बार-बार तकनीकी खराबी एवं रिचार्ज अपडेट न होने की शिकायतें आ रही हैं। छोटे बकायादारों का 500 रुपये के बकाये पर भी कनेक्शन काट दिया दिया रहा है। बिजली विभाग का टोल फ्री नंबर 1912 यहां मुश्किल से लगता है। मनाही के बाद भी पुराना रामनगर के वार्ड निवासी शमीम अख्तर की बिजली रात में काट दी गई। कानपुर में डेढ़ लाख प्रीपेड मीटर काम कर रहे हैं। बिल जमा करने के बाद भी दोबारा बिजली शुरू करने में 24 से 72 घंटे तक का समय लग जा रहा है। ऐसी समस्या कानपुर व फतेहपुर ही नहीं, बल्कि बुंदेलखंड समेत आसपास के सभी जिलों में है। बरेली के एक उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन 17 मार्च की सुबह काट दिया गया। उनके बिल पर 2400 रुपये का बकाया दर्शाया गया। इसे तुरंत जमा किया तो दूसरा संदेश आया कि 1200 रुपये और जमा करने हैं। उन्होंने यह रकम भी जमा कर दी, मगर आपूर्ति बहाल नहीं हुई। आनलाइन भुगतान के बावजूद सर्वर की देरी के कारण अयोध्या के उपभोक्ता भी बिजली कटने से परेशान हैं।

दैनिक जागरण

व्यक्ति के स्वभाव पर उसका भविष्य निर्भर करता है

माओवाद से मुक्ति की घड़ी

माओवाद से मुक्ति की समयसीमा निकट आ जाने के पूर्व बस्तर में 25 लाख के इनामी माओवादी सरगना पापा राव ने अपने 17 साथियों के साथ जिस तरह हथियार डाले, उसे माओवादियों के इस सबसे बड़े गढ़ में माओवादी हिंसा के अंत का एक निर्णायक क्षण मानना स्वाभाविक है, क्योंकि यह इस क्षेत्र का आखिरी बड़ा माओवादी सरगना माना जाता था। देश का माओवाद से मुक्ति की कगार पर पहुंचना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि के लिए पूरा श्रेय मोदी सरकार और विशेष रूप से गृहमंत्री अमित शाह को जाता है, जिन्होंने यह संकल्प लिया कि एक निश्चित अवधि में माओवादियों को घुटने टेकने के लिए विवश किया जाएगा। यह संकल्प पूरा होता इसलिए दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुरक्षा बलों ने एक व्यापक और कहीं अधिक प्रभावी रणनीति के तहत माओवाद के खात्मे का अभियान छेड़ा। अच्छी बात यह रही कि इस अभियान में माओवाद ग्रस्त सभी राज्यों और वहां के सुरक्षा बलों ने पूरा सहयोग दिया। यदि माओवाद दशकों से देश के लिए सिरदर्द और आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बना रहा तो इसीलिए कि पहले की सरकारों ने उससे निपटने के मामले में वैसी प्रतिबद्धता का परिचय नहीं दिया, जैसी आवश्यक थी।

अब जब माओवाद अंतिम सांसें गिनता दिख रहा है तो यह ध्यान रहे कि ग्रामीण क्षेत्रों में हथियारबंद माओवादी भले ही असहाय-निरुपाय दिख रहे हों, लेकिन अर्बन नक्सल कहे जाने वाले उनके उन समर्थकों को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए, जो माओवादी संगठनों को वैचारिक खुराक देते रहे हैं। स्पष्ट है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों को हताश-निराश माओवादियों को फिर से सिर उठाने का अवसर नहीं देना चाहिए। यह हिंसक विचारधारा किसी भी सूरत में दोबारा नहीं पनपनी चाहिए। माओवाद घोर अतिवादी एवं सभ्य समाज को चुनौती देने वाली एक विषैली और विजातीय विचारधारा है। स्पष्ट है कि इस विचारधारा का सामना विचार के स्तर पर भी करना होगा। ऐसा करते समय यह भी स्मरण रखना होगा कि निर्धन-वंचित ग्रामीणों और विशेष रूप से वनवासियों के हितों की रक्षा की फर्जी आड़ लेकर पनपी इस विचारधारा को समय-समय पर राजनीतिक संरक्षण भी मिला। चूंकि माओवादी भोले-भाले ग्रामीण लोगों के हितों के बहाने कमीशनखोरी और उगाही करने वाले गिरोह में तब्दील हो गए थे, इसलिए वे अपने को सशक्त करते चले गए। सबसे आश्चर्यजनक बात यह रही कि वे विभिन्न स्रोतों से आधुनिक हथियार एवं विस्फोटक भी हासिल करने में समर्थ रहे। यह सबको और विशेष रूप से माओवादियों के दबे-छिपे समर्थकों और उनसे हमदर्दी रखने वालों को समझने की आवश्यकता है कि माओवाद सरीखी विनाशकारी विचारधारा के लिए इस देश में कोई स्थान नहीं हो सकता।

अवसर भी जिम्मेदारी भी

झारखंड में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए जेटेट-2026 की अधिसूचना नई उम्मीद लेकर आई है। जैक द्वारा जारी विज्ञापन केवल परीक्षा की औपचारिक घोषणा भर नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में लंबित सुधारों को गति देने का संकेत भी है। पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को नए सिरे से पद के लिए आवेदन देने को कहा गया है। यह प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक है। जैक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पोर्टल सरल, त्रुटिरहित और पारदर्शी हो, ताकि किसी तकनीकी वजह से योग्य अभ्यर्थी वंचित न रह जाएं। नई नियमावली-2026 के तहत भाषा चयन में भूमिज को शामिल करना एक सकारात्मक पहल है। यह कदम जनजातीय पहचान और भाषाई विविधता को सम्मान देने की दिशा में महत्वपूर्ण है। लेकिन, इसे केवल प्रतीकात्मक न रखते हुए शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण में भी समान संवेदनशीलता दिखानी होगी। पारा शिक्षकों को दी गई आयु सीमा में छूट सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से उचित है, क्योंकि वे वर्षों से शिक्षा व्यवस्था का आधार रहे हैं। परंतु, यह भी जरूरी है कि मेरिट और गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। राज्य को प्रशिक्षण और मूल्यांकन की मजबूत व्यवस्था विकसित करनी होगी, ताकि चयनित शिक्षक वास्तव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें। सबसे अहम पहलू यह है कि जेटेट सिर्फ एक परीक्षा न बनकर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी बनाए।

यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पोर्टल सरल, त्रुटिरहित और पारदर्शी हो

ट्रंप के लिए वियतनाम बना ईरान

शिवकांत शर्मा

ईरान को लेकर अगर ट्रंप के लक्ष्य पूरे नहीं होते तो उन्हें मागा राष्ट्रपति के रूप में नहीं, वियतनाम से हारे निक्सन और इराक से पस्त बुश की तरह देखा जाएगा

अवधेश राजपूत

जिस ईरान युद्ध को छेड़ने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा होगा कि महज चार दिनों में ही जंग का फैसला हो जाएगा, वह टकराव महीने भर से ज्यादा लंबा खिंच गया है और उस पर जल्द विराम के भी कोई आसार नहीं दिख रहे। इस दौरान अमेरिका के लगभग 40 अरब डालर खर्च हो चुके हैं। रणभूमि पर सैनिक नहीं उतारने की बारंबार दुहाई देने के बावजूद ट्रंप को लगभग सात हजार मरीन और पैराशूट सैनिक भेजने पड़ रहे हैं, लेकिन ईरान न किसी तरह की हार मानने को तैयार है और न सीधी बातचीत को। अमेरिकी कांग्रेस और संयुक्त राष्ट्र से अनुमति लिए बिना ईरान के परमाणु और मिसाइल खतरे से रक्षा के बहाने छेड़े इस युद्ध ने पूरी दुनिया को गंभीर आर्थिक संकट में झोंक दिया है। ऐसा इसलिए, क्योंकि अपने व्यापक विनाश से तिलमिलाया ईरान अब अपने 454 किलो संवर्धित यूरेनियम को सौंपना और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को सीमित करना तो दूर, होर्मुज जलमार्ग पर कब्जा करने पर तुल गया है।

ईरान की निगरानी में गुजरे कुछ जहाजों के अलावा यह जलमार्ग पिछले महीने भर से बंद है। इसकी वजह से तेल, गैस, उर्वरक, हीलियम और प्लास्टिक के कच्चे माल की तंगी हो गई है। भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया समेत एशिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं की निर्भरता खाड़ी पर सर्वाधिक है। इसलिए वहां तो महंगाई और मंदी का खतरा है ही यूरोप और अमेरिका में भी महंगाई पर काबू पाने के लिए ब्याज दरें बढ़ाने की बातें होने लगी हैं। इसे 1970 के दशक में इजरायल-मिस्र-सीरिया युद्ध और इस्लामी क्रांति के तेल संकटों से भी बड़ा ऊर्जा संकट माना जा रहा है।

होर्मुज बंद रहने से उपजे आर्थिक संकट की तपिश एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ-साथ अमेरिका भी पहुंच चुकी है। अमेरिका में डीजल की कीमतें 25 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं। डीजल और उर्वरक की महंगाई का सीधा असर किसानों की आमदनी पर पड़ रहा है। रोजमर्रा का सामान महंगा होने से ट्रंप के मागा समर्थकों में भी नाराजगी है। युद्ध का विरोध करने वालों का आंकड़ा 61 प्रतिशत से ऊपर चला गया है। ट्रंप का अपना जनसमर्थन इतिहास के न्यूनतम बिंदु पर है। सीनेट में विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर युद्धमंत्री हेगसेथ और विदेशमंत्री रूबियो को समितियों में तलब करने पर अड़े हैं। नवंबर में होने जा रहे संसदीय चुनाव में यदि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने कांग्रेस में अपना बहुमत खो दिया तो ट्रंप पर महाभियोग की तलवार भी लटकने लगेगी। इसलिए वे अब इस युद्ध को किसी ऐसे समझौते के साथ समाप्त करने के लिए छटपटा रहे हैं, जिसमें उनकी जीत का ढोल पीटने की गुंजाइश हो। इसलिए वे किसी भी मध्यस्थ के जरिये संदेश भेज कर बातचीत की हवा बांधने की कोशिश कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि मध्यस्थता के लिए उन्हें चीन या रूस जैसा कोई देश नहीं मिला जिसके ईरान के साथ सामरिक रिश्ते हों। ओमान और कतर जैसे पुराने मध्यस्थ भी तैयार नहीं हुए। बस एक पाकिस्तान मिला।

फारस और ओमान की खाड़ियों को मिलाने वाले होर्मुज जलमार्ग की चौड़ाई उसके मोड़ पर मात्र 21 समुद्री मील है जिसमें से 12 समुद्री मील तक ईरान की जलसीमा है और 12 समुद्री मील ओमान की। दोनों की जलसीमाएं एक-दूसरे से सटी हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के जलमार्ग कानून के अनुसार ये दोनों देश अपनी जलसीमाओं से होकर गुजरने वाले जहाजों को रोक नहीं सकते। जैसे विमानों को दूसरे देशों की वायुसीमा से होकर उड़ान भरने का अधिकार है, वैसे ही जहाजों को जलसीमा से होकर गुजरने का। यहां समस्या अधिकारों की न होकर अंतरराष्ट्रीय नियमों के पालन की है। ईरान पर हमले के समय तो अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र के नियमों का ध्यान नहीं रखा। न ही ईरान के चीन और रूस जैसे मित्रों ने या दूसरे देशों ने हमले रोकने के लिए कोई आवाज उठाई। अब ईरान से उसके होर्मुज जलमार्ग से होकर गुजरने के अधिकार की मांग किस मुंह से करेंगे। इसे खुलवाने के लिए ट्रंप ने नाटो और दूसरे मित्र देशों को दुत्कारा और फटकारा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। पिछले सप्ताह नाटो के महासचिव मार्क रूटर ने होर्मुज खुलवाने के लिए नाटो देशों समेत तीस देशों का संगठन खड़ा करने की बात जरूर की, मगर ईरान का कहना है कि होर्मुज जलमार्ग बंद कहां है? मित्र देशों के जहाजों के लिए तो खुला है। बस अमेरिका, इजरायल और उनके समर्थक देशों के जहाजों के लिए बंद है। उन्हें जाने के लिए भारी चुंगी अदा करनी होगी।

कहां तो अमेरिका ने ईरान की मुल्लाशाही को गिराने के लिए उसके तेल पर प्रतिबंध लगा रखे थे। कहां अब ईरान ने अमेरिका और उसके मित्र देशों के जहाजों के होर्मुज से गुजरने पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। उसे खुलवाने के लिए ट्रंप एक तरफ ईरान के बिजलीघर उड़ाने और कहर बरपाने की धमकी दे रहे हैं और त्वरित हमलों में दक्ष मरीन और पैराशूट सैनिकों को खाड़ी में तैनात कर रहे हैं। दूसरी तरफ धमकी की समयसीमा बढ़ाते जा रहे हैं। जहां ट्रंप ईरान की लड़ाई को होर्मुज खुला रखने की लड़ाई में बदल कर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का खोया साथ हासिल करने की चाल चल रहे हैं, वहीं ईरान यमन के हूती संगठन को भी लड़ाई में उतार कर उस बाब-अल-मंदाब जलमार्ग को रोकने की तैयारी कर रहा है जो लाल सागर से होते हुए स्वेज नहर तक ले जाता है।

ट्रंप सारे पत्ते अपने हाथ में होने के चाहे जितने दावे करें, पर लगता यही है कि वे फंस चुके हैं। यदि वे ईरान के बिजलीघरों को उड़ाते हैं तो ईरान के जवाबी हमलों की आशंका से तेल और शेयर बाजारों में और हड़कंप मचेगा। यदि सेना को ईरान के खार्ग या किसी और द्वीप पर उतारते हैं तो बाजारों में हड़कंप के साथ-साथ अमेरिका में भी उनका मुखर विरोध होगा। यदि होर्मुज खुलवाए बिना लौट जाते हैं तो उन्हें मागा राष्ट्रपति के रूप में नहीं, बल्कि वियतनाम से हारकर लौटे निक्सन और इराक से हारकर लौटे बुश की तरह ईरान से हार कर लौटे राष्ट्रपति के रूप में याद किया जाएगा।

(लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं)

response@jagran.com

समान संहिता पर राह दिखाते राज्य

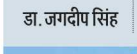

डा. जगदीप सिंह

उत्तराखंड एवं गुजरात का यूसीसी की दिशा में बढ़ना अन्य राज्यों के साथ केंद्र को भी कानून बनाने के लिए प्रेरित करेगा

गुजरात विधानसभा ने पारित किया यूसीसी बिल। फाइल

गत दिनों गुजरात विधानसभा में विस्तृत चर्चा के बाद 'गुजरात यूनिफार्म सिविल कोड बिल, 2026' को बहुमत से पारित कर दिया गया। इस कदम के साथ गुजरात, उत्तराखंड के बाद दूसरा ऐसा राज्य बन गया है, जहां व्यक्तिगत मामलों में धर्म-आधारित अलग-अलग कानूनों के स्थान पर एकसमान कानूनी ढांचा लागू किया गया है। विधेयक के अनुसार विवाह समारोह धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न किए जा सकते हैं, किंतु उनका पंजीकरण अनिवार्य होगा। पंजीकरण न कराने की स्थिति में दस हजार रुपये तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है। विवाह की न्यूनतम आयु पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष तय की गई है। बहुविवाह को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है तथा पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह अमान्य माना जाएगा। तलाक के आधारों को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिनमें क्रूरता, परित्याग, व्यभिचार, मतांतरण और मानसिक विकार शामिल हैं। साथ ही आपसी सहमति से तलाक का प्रविधान भी रखा गया है, किंतु विवाह के एक वर्ष के भीतर तलाक की अनुमति नहीं दी जाएगी। लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता देते हुए उसके पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है। यदि किसी पक्ष की आयु नाबालिग पाई जाती है, तो उसके माता-पिता को सूचित किया जाएगा। लिव-इन संबंध से जन्मे बच्चे को वैध संतान का दर्जा दिया जाएगा तथा महिला साथी को भरण-पोषण का अधिकार प्रदान किया गया है। बच्चों के पालन-पोषण में माता-पिता, दोनों की समान जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है। साथ ही उत्तराधिकार और संपत्ति के बंटवारे में पूर्ण लैंगिक समानता लागू की गई है, जिससे विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के कारण उपजी असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास किया गया है।

यह कानून पूरे गुजरात में लागू होगा और गुजरात के वे मूल निवासी, जो राज्य के बाहर रहते हैं, उन पर भी प्रभावी रहेगा। इसके अंतर्गत वे व्यक्ति भी शामिल किए गए हैं, जो पिछले दस वर्षों से लगातार गुजरात में निवास कर रहे हैं या राज्य अथवा केंद्र सरकार की सेवा में कार्यरत हैं। हालांकि अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को इस कानून से छूट प्रदान की गई है, ताकि उनकी पारंपरिक प्रथाओं और सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। इसमें जबरन विवाह पर दंड का प्रविधान किया गया है, साथ ही हलाला जैसी कुप्रथाओं को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है। इस कानून के लागू होने का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव लैंगिक न्याय के क्षेत्र में दिखाई देगा। महिलाओं को अब सभी समुदायों में संपत्ति, उत्तराधिकार और भरण-पोषण के मामलों में समान अधिकार प्राप्त होंगे। लिव-इन संबंधों में आर्थिक सुरक्षा मिलने से उनकी स्थिति अधिक सुदृढ़ होगी और बच्चों के अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। पंथ के आधार पर कानूनी भेदभाव समाप्त होने से सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलेगा। अंतर्धार्मिक विवाह अधिक सुगम होंगे और संपत्ति से जुड़े विवादों में जटिलताएं भी कम होने की संभावना है। कानूनी प्रक्रिया में भी उल्लेखनीय सरलीकरण आएगा। अदालतों पर बोझ कम होगा, क्योंकि अब विवादों का निपटारा एक ही कानूनी ढांचे के अंतर्गत किया जा सकेगा। इससे न्याय वितरण अधिक तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनेगा। पारिवारिक मामलों में मुकदमों की संख्या घटने से सामाजिक स्थिरता को भी बल मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो संपत्ति संबंधी विवादों में कमी आने से व्यापार और निवेश का परिवेश भी अधिक अनुकूल होगा।

अब इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार को कई ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे पहले, एक सुदृढ़ डिजिटल पंजीकरण प्रणाली विकसित करनी होगी। साथ ही ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाना होगा। प्रशिक्षित अधिकारियों की नियुक्ति और न्यायिक कर्मचारियों को नए प्रविधानों से अवगत कराना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसको चरणबद्ध तरीके से लागू करने से संभावित चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना किया जा सकेगा। जनता के बीच विश्वास निर्माण के लिए निरंतर संवाद और सहभागिता भी अनिवार्य होगी।

राजनीतिक दृष्टि से यह निर्णय अन्य राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है और केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय स्तर पर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने का दबाव भी बढ़ा सकता है। गुजरात विधानसभा का यह निर्णय भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता को दर्शाता है, जहां विविधता का सम्मान करते हुए समानता को प्राथमिकता दी गई है। यदि इस कानून का प्रभावी क्रियान्वयन होता है, तो एक प्रगतिशील राज्य के रूप में गुजरात की पहचान और पुख्ता होगी। यह कानून पंथ से ऊपर उठकर प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ होगी, सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा और राष्ट्रीय एकता को नई मजबूती प्राप्त होगी। निःसंदेह गुजरात का यह कदम इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में दर्ज होगा, क्योंकि यह लंबे समय से चल रही बहस को ठोस कार्रवाई में परिवर्तित करने का उदाहरण है। समानता अब केवल संवैधानिक आदर्श तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि वास्तविकता की दिशा में अग्रसर होती दिखाई दे रही है, जो पूरे देश के लिए प्रेरणास्रोत बन सकती है।

(लेखक राजनीति शास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सर्वव्यापी ईश्वरीय सत्ता

जब किसी भीषण दुर्घटना के बाद भी कोई व्यक्ति सही सलामत बच निकलता है तो हम मान लेते हैं, अवश्य कोई अदृश्य शक्ति है, जिसका निर्णय अंतिम होता है। अदम्य इच्छा, पर्याप्त संसाधन, अच्छी योजना और अथक प्रयास के बाद भी कुछ कार्य होते-होते फलीभूत नहीं होते। इसके विपरीत सहज बुद्धि और तर्क से जो कार्य असंभव था वह कदाचित संपन्न हो जाता है।

मनुष्य की कितनी भी इच्छाएं हों, समस्त लौकिक गतिविधियों के संचालन की ईश्वर की अपनी वृहत्तर व्यवस्था है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप निष्फल रहता है। सृष्टि में समस्त प्राणियों, वनस्पतियों तथा जल-थल सतहों से इतर अनेक अदृश्य, अबूझ अस्मिताएं विद्यमान रहती हैं। मानव जाति इस अनंत, विराट व्यवस्था की एक छोटी सी इकाई है। ईश्वर सृष्टि के प्रत्येक अंग के जीवन चक्र के संचालन और समस्त घटकों में परस्पर समन्वय का दायित्व निभाते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बहुआयामी प्रसार, उपयोग और इसमें शोध के बाद भी अभी तक मनुष्य को अनेक क्षेत्रों की जानकारी आधी अधूरी है। अपने अज्ञान को समझ लेंगे तो अपने ज्ञान पर अहंकार नहीं होगा। निहित स्वार्थों और लोभ से अभिप्रेरित मनुष्य की आकांक्षाएं भले ही महासागर जैसी अनंत हों, किंतु उसकी वास्तविक भूमिका एक बूंद से अधिक नहीं है। इस सत्य को जानने वाला ईश्वरीय शक्ति के समक्ष नतमस्तक रहेगा। ईश्वर सर्वव्यापी हैं। हम भले ही भ्रम में जीते रहें कि हमारा अनुचित कार्य कोई नहीं देख रहा, किंतु वे जानते हैं किस आशय से हम कब, क्या-क्या करते हैं और उसी अनुसार न्याय देते हैं। यह समझ लेंगे कि कण-कण में व्याप्त ईश्वरीय अंश सभी में निहित है और हम उसी की संतति हैं तो हम सद्गुणों को अपनाते हुए उसी सन्मार्ग पर प्रशस्त रहेंगे जैसा ईश्वर चाहते हैं। तब अवगुण छूट जाएंगे और धन्य हो जाएंगे।

हरीश बड़थ्वाल

खाद्य पदार्थों की बर्बादी

डा. मोनिका शर्मा

दुनिया के बहुत देशों में चल रहे ऊर्जा संकट के इस दौर में मितव्ययता और संचय की समझ का महत्व समझा जा रहा है। जबकि जीवन की सबसे अहम आवश्यकताओं में शामिल अन्न को सहेजने में आज भी दुनियाभर में कोताही की जाती है। एक ओर दिखावा संस्कृति ने भोजन की बर्बादी की मानसिकता को बढ़ाई है तो दूसरी ओर दुनिया के हर हिस्से में ही कुपोषण और भूख से जूझने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। यही वजह है कि खाद्य पदार्थों की बर्बादी रोकने के लिए सजगता और संवेदशीलता, दोनों आवश्यक हैं। ध्यातव्य है कि 30 मार्च को मनाया जाने वाले अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस के लिए वर्ष 2026 का विषय 'खाद्य अपशिष्ट' ही है। कचरा प्रबंधन, रिसाइकिलिंग और टिकाऊ उपभोग को बढ़ावा देने वाली संयुक्त राष्ट्र की यह पहल पर्यावरण सहेजने और कचरे को कम करने से जुड़ी है। 2024 की संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की ही फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में दुनियाभर में करीब 1.05 अरब टन भोजन बर्बाद हुआ। बदलती जीवनशैली में यह मात्रा हर वर्ष बढ़ ही रही है। इसीलिए इस वर्ष की थीम फूड वेस्ट कम से कम करने और अन्न का हर दाना सहेजने की सजगता का संदेश देने से जुड़ी है।

अन्न को ब्रह्म मानने की परंपरा वाले हमारे देश में 60 प्रतिशत भोजन की बर्बादी घरेलू स्तर पर ही होती है

विचारणीय है कि खाद्य अपशिष्ट की बढ़ती समस्या के पीछे कई कारण हैं। आम जीवन में व्यक्तिगत आदतें तो सामाजिक-पारिवारिक समारोहों में सामाजिक दबाव एवं दिखावे की प्रवृत्ति भोजन की बर्बादी की वजह हैं। व्यवस्थागत मोर्चे पर खराब भंडारण और जमाखोरी अन्न की बर्बादी का कारण बनते हैं। जबकि खाद्यान्नों के अपव्यय का व्यवहार एक नैतिक और पर्यावरणीय संकट है। चिंतनीय है कि भोजन की बर्बादी सीधे-सीधे पानी, श्रम, ऊर्जा और दूसरे संसाधनों का अपव्यय करना भी है। भोजन को पकाने और उगाने में किसी न किसी रूप में ऊर्जा, मानवीय श्रम और संसाधन लगते ही हैं। बावजूद इसके हमारे देश में ही हर वर्ष उत्पादित भोजन का लगभग 30-40 प्रतिशत हिस्सा बर्बाद होता है। जीवन सहेजने वाल अन्न अपशिष्ट बनकर जहरीली गैसों, किटाणुओं और ठोस एवं तरल कचरे के रूप में जीवन का जोखिम बन जाता है।

स्पष्ट है कि खाद्य पदार्थों की बर्बादी रोकने हेतु आमजन का दायित्वबोध सबसे अहम है। जूठन न छोड़ने और पुनः उपयोग का नियम बहुत सहजता से अपनाया जा सकता है। गौरतलब है कि अन्न को ब्रह्म मानने की परंपरा वाले हमारे देश में 60 प्रतिशत भोजन की बर्बादी घरेलू स्तर पर ही होती है। सामाजिक-पारिवारिक मोर्चे पर देखें तो आयोजनों में भी खाने की चीजों के सीमित विकल्प रखने का साझा दृष्टिकोण बेहद आवश्यक है। व्यवस्थागत मोर्चे पर बेहतर परिवहन और भंडारण बहुत जरूरी हैं।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

विकास के साथ संतुलन की जरूरत

'प्रगति को नए पंख' शीर्षक संपादकीय में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को देश की विकासशील आकांक्षाओं का प्रतीक बताया गया है, जो एक सीमा तक उचित भी प्रतीत होता है। यह परियोजना क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, निवेश और रोजगार के नए अवसरों को जन्म देने में सक्षम है, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के लिए। परंतु एक अनुभवी दृष्टिकोण यह संकेत देता है कि केवल आधारभूत ढांचे का विस्तार ही समावेशी और संतुलित विकास सुनिश्चित नहीं कर सकता, जब तक उसके सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों का समुचित मूल्यांकन न किया जाए। वर्तमान परिदृश्य में सबसे गंभीर चुनौती "संख्या बनाम गुणवत्ता" की है। हवाई अड्डों की संख्या में वृद्धि प्रभावशाली अवश्य है, परंतु उनकी सेवाओं, रखरखाव और संचालन दक्षता में समान सुधार अभी भी अपेक्षित है। विमानों की सर्विसिंग के लिए विदेशी निर्भरता इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की अधूरी स्थिति को स्पष्ट करती है। एमआरओ सुविधाओं का विस्तार स्वागतयोग्य है, किंतु इसे स्थानीय युवाओं के कौशल विकास और स्थायी रोजगार से जोड़ना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय संतुलन और विस्थापितों के पुनर्वास जैसे मुद्दे अक्सर विमर्श से बाहर रह जाते हैं, जो भविष्य में सामाजिक असंतुलन को जन्म दे सकते हैं। अतः आवश्यक है कि विकास को एकीकृत दृष्टिकोण से देखा जाए, जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित हो। वास्तविक प्रगति वही होगी, जो आंकड़ों से आगे बढ़कर जनजीवन में सकारात्मक और स्थायी परिवर्तन ला सके।

awanishg30@gmail.com

मेलबाक्स

साझेदारी का सशक्त सेतु

नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह द्वारा भारत के साथ संबंधों को नई ऊंचाई देने की प्रतिबद्धता दोनों देशों के लिए सकारात्मक संकेत है। भारत और नेपाल के रिश्ते केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आधार पर भी गहराई से जुड़े हुए हैं। खुली सीमा, आपसी विश्वास और जन-जन के रिश्ते इस संबंध को विशेष बनाते हैं। रणनीतिक दृष्टि से नेपाल भारत की उत्तरी सुरक्षा और क्षेत्रीय संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वहीं भू-आबद्ध होने के कारण नेपाल के लिए भारत व्यापार, पारगमन और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य मार्ग है। ऐसे में आपसी सहयोग दोनों की आवश्यकताओं को संतुलित करता है। भविष्य में बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, पर्यटन और व्यापार के क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत किया जा सकता है। पारस्परिक सम्मान, संवाद और सहयोग के माध्यम से दोनों देश न केवल अपने हितों को सुरक्षित रख सकते हैं बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि में भी योगदान दे सकते हैं।

अमृतलाल मारू, इंदौर, मप्र

वैश्विक ऊर्जा संकट

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच लगभग एक माह से जारी संघर्ष अब और जटिल हो गया है। ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता का सीधा असर वैश्विक उद्योगों पर पड़ रहा है। तेल और गैस की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव से उत्पादन लागत बढ़ रही है, जिससे विशेष रूप से विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं दबाव में हैं। यूरोप, जो पहले ही ऊर्जा संकट से जूझ चुका है, एक बार फिर असुरक्षा की स्थिति में आ गया है। वहीं एशियाई देशों, खासकर भारत और चीन, को भी आयातित ऊर्जा पर निर्भरता के कारण भारी आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस संघर्ष को रोकने के प्रयास करते तो दिख रहे हैं, लेकिन उनका रुख विरोधाभासी नजर आता है। यदि स्थिति जल्द नियंत्रित नहीं होती, तो इसका असर केवल ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित होंगी, खाद्य संकट गहराएगा और विकास दर में गिरावट आ सकती है। ऐसे में जरूरी है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय तत्काल और प्रभावी कूटनीतिक हस्तक्षेप करे, ताकि इस संकट को और बढ़ने से रोका जा सके।

budawanwalas55@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एजीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

18 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है देश में शहरी विकास के लिए पिछले लगभग 12 वर्षों के दौरान, जबकि शहरी विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए इसमें व्यापक वृद्धि की आवश्यकता है।

मनु त्यागी
manu@nda.jagran.com

आजकल

इतिहास से आधुनिक प्रगति तक का सफर

दिल्ली स्थित आइजीआइ एयरपोर्ट की क्षमता विस्तार की संभावना लगभग समाप्त हो जाने के बाद से पिछले लंबे समय से एनसीआर में एक नए एयरपोर्ट की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। ऐसे में जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन दिल्ली एनसीआर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि के साथ इस क्षेत्र की आर्थिक गति को तेज करने वाला कारक साबित होगा। इस क्षेत्र का इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है, तो वहीं इस एयरपोर्ट का संचालन आरंभ से इसके आधुनिक विकास में एक नया आयाम भी जुड़ गया है

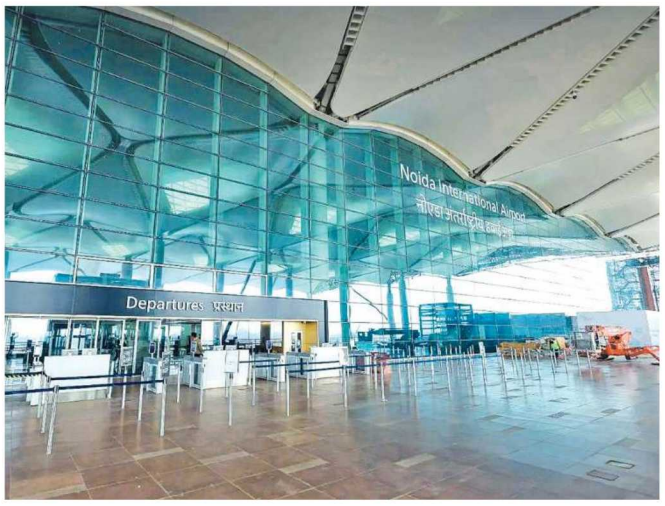

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आरंभ होने से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के विकास को मिलेगी गति। फाइल

मैं जेवर हूं। आज मेरी पहचान कंक्रीट के लंबे रनवे, आसमान से बातें करते गगनचुंबी टावरों और एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक के रूप में हो रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेरी जड़ें उस माटी से जुड़ी हैं, जहां कभी ऋषियों के मंत्र गूंजते थे। त्रेता का तप, द्वापर का युद्ध और आधुनिक भारत के औद्योगिक उदय को मैंने साक्षात देखा है। और अब मेरा सौभाग्य है कि विकास मुझ पर विकसित देश के लिए एक नया अध्याय लिख रहा है। आज दुनिया की निगाहें मेरी ओर टिकी हैं, तो मेरी माटी मिसाल से वैश्विक पहचान का बोध कर रही है। मैंने तो कभी सोचा नहीं था, एक ग्रामीण अंचल से 'वैश्विक हब' की अनुभूति होगी। देश के 'जेवर' के रूप में मेरा उद्घोष होगा।

महर्षि जाबालि का जेवर हूं : आपको शायद पता नहीं होगा, जिस जेवर का नाम आज दुनिया जान रही है, 'एक्स' पर ट्रेंड कर रहा है, गूगल पर सर्चिंग में बार-बार घूम रहा है, इस नाम के पीछे भी एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है। प्राचीन काल में मुझे 'जाबालिपुर' के नाम से जाना जाता था। मेरा यह नाम महर्षि जाबालि के सम्मान में पड़ा, जिन्होंने इसी पावन धरा पर घोर तपस्या की थी। कालांतर में 'जाबालि' अपभ्रंश होते-होते 'जेवर' बन गया। आज भी गांव के बुजुर्ग आपको बता देंगे। मेरी भौगोलिक स्थिति महत्वपूर्ण रही है। यमुना के तट पर बसा मेरा क्षेत्र प्राचीन काल से सांस्कृतिक धरा का केंद्र रहा है। पुरातात्विक अवशेष भी हजारों साल पुरानी पेंटेड ग्रे वेयर (चित्रित धूसर मृदभांड) संस्कृति के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं।

रामायण-महाभारत से क्रांति तक : मेरे आसपास का कोना-कोना लोकगाथाओं और पौराणिक स्मृतियों से भी पल्लवित है। मेरे समीप स्थित 'बिसरख' गांव, वही रावण के पिता का, विश्रवा ऋषि का जन्मस्थान माना जाता है। वहीं 'दनकौर' में गुरु द्रोणाचार्य का प्राचीन आश्रम, जहां कौरवों और पांडवों ने शस्त्र विद्या सीखी थी। एकलव्य की भक्ति और गुरुभक्ति का भी साक्षी बना। अभिभूत हूं अपने इतिहास पर। इन महान चरित्रों की स्मृतियां आज भी मेरी मिट्टी में रची-बसी हैं, जो मुझे आधुनिक शहर के साथ जीवंत सांस्कृतिक धरोहर भी बनाती हैं। क्रांति के दौर को याद करोगे तो भी मेरे गौरव को याद करोगे। वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में यहां के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को धूल चटाई। दादरी और जेवर क्षेत्र के 84 क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने बुलंदशहर के 'काला आम' पर फांसी दी थी। बलिदानी भगत सिंह को कैसे भूल जाऊं, नोएडा-ग्रेटर नोएडा के नलगढ़ा गांव में ही तो भूमिगत रहकर बमों का परीक्षण किया था। मेरी धरती ऐसे ही बलिदानियों के रक्त से अभिसिंचित है।

गांव से शहर और मानचित्र तक : फिर आई, मेरे गांव से शहर हो जाने की बारी, आजादी तक जहां मैं बुलंदशहर का हिस्सा था। विकास के दरवाजे बड़े हुए तो मेरा मिलन नौ जून, 1997 को गौतमबुद्ध नगर जिले से हो गया। धीरे-धीरे मेरी धरा, विकास के बीज बोने लगी, जिसे आपकी भाषा में शहरीकरण भी कहते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे क्या बना, देश की राजधानी भी करीब से दिखने लगी। इस दौर में मेरी भौगोलिक दूरियां तो तेजी से सिमट रहीं थीं, लेकिन वास्तविक पहचान अभी भी एक कृषि प्रधान ग्रामीण क्षेत्र में ही छिपी थी। मेरे किसान भाई देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए विकास को पोषित करने के लिए धरा की बाहें फैलाए खड़े हो गए। और जब मोड़ आया, मेरे आंगन से उड़ान भरने का तो मेरी पहचान, मेरा नाम एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में जुड़ गया। मैं जेवर स्थित सबसे बड़ा एयरपोर्ट पुकारा जाने लगा। देखते ही देखते, गूगल मुझे ट्रेंड करने लगा, हर कोई जेवर की लोकेशन से परिचित होने लगा। मानचित्र में मुझे ऐतिहासिक, पौराणिकता के साथ-साथ विकास की भी पहचान मिल गई। शनिवार को देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मेरे हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन कर मेरे इतिहास को विकास का मजबूत पहिया बना दिया।

इकोनमी का इंजन : जेवर क्षेत्र अब केवल एक तहसील नहीं, बल्कि एक आर्थिक महाशक्ति बन रहा है। गौतमबुद्ध नगर की प्रति व्यक्ति आय 10.17 लाख रुपये तक पहुंच गई है, जो उत्तर प्रदेश के औसत से लगभग 10 गुना अधिक है। यह आंकड़ा इसे वैश्विक स्तर पर उच्च-आय वाले क्षेत्रों की कतार में खड़ा करता है। यमुना प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार, एयरपोर्ट की घोषणा के बाद से क्षेत्र में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित हुआ है। यहां विकसित हो रहे मेडिकल डिवाइस पार्क, टाय पार्क और डाटा सेंटर हब से सालाना अरबों डालर के टर्नओवर की उम्मीद है, जो भारत के निर्यात को बड़ी मजबूती देगा। जेवर की भौगोलिक स्थिति इसे 'मल्टी-माडल कनेक्टिविटी' का सबसे बेहतरीन उदाहरण बनाती है।

इसी जेवर के पास सेक्टर-21 में एक हजार एकड़ में बन रही फिल्म सिटी इस क्षेत्र की 'साफ्ट पावर' को वैश्विक पहचान दिलाएगी। यह न केवल हालीवुड और वालीवुड के स्तर की अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगी, बल्कि डिजिटल मीडिया, एनिमेशन और गेमिंग उद्योगों के लिए भी एक बड़ा केंद्र बनेगी। इससे लगभग 50 हजार प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है, जिससे जेवर एक 'कल्चरल हब' के रूप में चमकेगा। इन विशाल परियोजनाओं को उन किसानों के सहयोग से साकार किया गया है, जिन्होंने अपनी भूमि विकास के लिए दी, जिससे अब वे स्वयं औद्योगिक प्रगति के भागीदार बन रहे हैं।

ग्रोथ इंजन के रूप में नोएडा : नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के उद्घाटन ने न केवल प्रदेश, बल्कि पूरे देश की आर्थिकी को नई दिशा देने का संकेत दिया है। प्रधानमंत्री का संबोधन केवल एक इन्फ्रा परियोजनाओं का बुके यानी पुष्प गुच्छ नहीं था, यह तो बदलते भारत की उस शक्ति का प्रदर्शन था जो वैश्विक संकट के बीच भी अडिग खड़ा है। तभी पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि यह हवाई अड्डा केवल विमानों के आने-जाने का जरिया नहीं, यह अर्थव्यवस्था का गेटवे है यानी लाजिस्टिक गेटवे। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ और गाजियाबाद जैसे क्षेत्रों को इससे सीधा लाभ मिलेगा।

अब तक सभी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पारंपरिक गन्ने के कटोरे और समृद्ध कृषि क्षेत्र के रूप में ही जाना-देखा है। लेकिन जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के उद्घाटन ने पूरे क्षेत्र को, इस पश्चिमी बेल्ट को वैश्विक औद्योगिक हब में बदल दिया है। देश के सबसे बड़े प्रदेश के नाते, उत्तर प्रदेश से केंद्र तक की राजनीति में सबकी दृष्टि इसी पर होती है। उसमें भी पश्चिमी उप्र का किसान वर्ग विशेष तौर पर हर राजनीतिक दल के लिए वोटों की मशीन जैसा होता है। लेकिन किसान उन दलों के लिए राजनीतिक कोण में तो है, पर अब उसका संकल्प, उसका सम्मान, उसकी समृद्धि सिर्फ एक मतदाता बनकर नहीं रह गई है, अब वह देश की वैश्विक पहचान, देश के ग्रोथ इंजन, जीडीपी में भी गर्व से खड़ा हो रहा है। इसलिए उसे केवल मतदाता समझना और आसानी से अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर लेना या रिझा लेना आगामी चुनाव में सत्तासीन और विपक्ष दोनों के लिए ही चुनौती से भरा होगा।

कह सकते हैं कि इस एयरपोर्ट को विकल्प नहीं, जरूरत के रूप में विकसित किया गया है। इसकी सबसे बड़ी ताकत यहां की कनेक्टिविटी भी साबित होगी, जो सिर्फ उड़ानों तक सीमित नहीं है। यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सीधा जुड़ाव। टैक्सी सेवा, रैपिड रेल, मेट्रो नेटवर्क के माध्यम से इसे दिल्ली, नोएडा, मेरठ और आगरा से जोड़ा जा रहा है। हालांकि दिल्ली से यहां तक की सुगम पहुंच के लिए अभी कुछ इंतजार करना होगा। वैसे कार्गो हब, उत्तर भारत का लाजिस्टिक गेटवे ऐसे ही नहीं कहा गया। यह वह बिंदु है जो इसे 'यात्री सेवा' यानी यात्रियों के लैंड तक ही सीमित नहीं रखता, बल्कि 'व्यापार लैंड' तक लेकर जाता है। जेवर स्थित इस एयरपोर्ट के आसपास का क्षेत्र यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यीडा का औद्योगिक गलियारा है, जहां हजारों करोड़ रुपये का निवेश परियोजनाएं आ रही हैं।

जब किसी एयरपोर्ट के चारों ओर एक जीवंत इकोसिस्टम होता है तो उसके आगे इसके भविष्य के संदर्भ में किसी प्रकार की शंका जताने वालों का सोच संकुचित होना ही कहा जा सकता है। अनुमान है कि यह एयरपोर्ट प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने में सक्षम होगा। हां, एक चुनौती है। दिल्ली एनसीआर के ही आइजीआइ एयरपोर्ट के साथ अभी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जरूर रहेगी। इसके लिए एयरपोर्ट अथारिटी और सरकार को ओपन स्काई पालिसी और बेहतर स्लाट मैनेजमेंट पर काम करना होगा। साथ ही मल्टी माडल कनेक्टिविटी जैसी योजनाओं को समय पर पूरा कर लोगों की उम्मीद को विश्वास में बदलना होगा। (मनु त्यागी)

दिल्ली एनसीआर के सभी हिस्सों से जुड़ाव

खरी-खरी

घमंड होता मंद

विनय कुमार पाठक

इस साल के टी 20 विश्व कप में आस्ट्रेलिया का जो हश्र हुआ है, इस बात से यही सीख मिलती है कि सामने वाले को कमजोर नहीं समझना चाहिए। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। हर विश्व कप में कोई न कोई कमजोर समझी जाने वाली टीम मजबूत समझी जाने वाली टीम की हालत पतली कर ही देती है। यही बात युद्ध में भी देखने को मिलती है। और एक बार नहीं कई बार मिला है। पर घमंड होता ही ऐसा है कि हर सीख को धता बताता रहता है। बालि के हाथों परास्त होने वाले रावण को भी घमंड ने कहीं का नहीं छोड़ा था।

अभी अमेरिका का ही हाल ले लीजिए। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ ही विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है यह। घमंड में चूर होकर चले थे ईरान को सबक सिखाने। एक तो यह देश ही अपने आप में घमंडी है और अभी उसे देश के घमंड रूपी करैला पर ट्रंप रूपी नीम भी चढ़ा हुआ है। वे सबक सिखाने के बदले सबक सीख रहे हैं। जब-जब अमेरिका ईरान को धमकाता है ईरान कुछ ऐसा धमाका कर देता है कि ट्रंप खिसियानी हंसी हंसने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। जब-जब अमेरिका ईरान के सर्वोच्च नेताओं के मारे जाने के बाद ईरान में दम नहीं बचने का दावा करता है ईरान उसके सैन्य ठिकानों और उसके पिछलग्गू देशों को बेदम कर देता है। होर्मुज पर नियंत्रण करने के अमेरिका दावों को अभी तक तो ईरान ने खोखला ही साबित किया है। नाटो ने भी साफ कह दिया है कि हम न तो इस मामले में पड़ेंगे और न ही अमेरिका की सहायता करेंगे। अमेरिका की जनता पूछ रही है कि ईरान को डोले शोले दिखाने के चक्कर में अरबों की संपत्ति नष्ट करने की क्या आवश्यकता है।

अमेरिका तक तो शायद ईरान की पहुंच नहीं है। या फिर है तो अभी तक इस पत्ते को ईरान ने खोला नहीं है। पर पश्चिम एशिया में उनके सैन्य ठिकानों का जो हाल ईरान ने किया है, अमेरिकी सैनिक सैन्य ठिकानों को छोड़ कर होटल और कार्यालय रूपी बिल में छिप रहे हैं। वियतनाम में और अफगानिस्तान जाकर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे शक्तिशाली देश लौट कर घर को आ चुका है।

पोस्ट

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ईरानी राष्ट्रपति के साथ बातचीत में इजरायली हमलों की निंदा करते हुए शायद यह भूल जाते हैं कि केवल इजरायल अकेले ही हमला नहीं कर रहा।
स्टैनले जानी@johnstanly

1956 के स्वेज नहर संकट ने ब्रिटिश साम्राज्य के पराभव की बुनियाद रखी थी। इसके 70 साल बाद होर्मुज जलमार्ग संकट अमेरिकी साम्राज्यवाद की नींव हिला सकता है। जिम@jimNjue_

अभी तक ईरान युद्ध रुकने के कोई आसार नहीं दिख रहे और वैश्विक अर्थव्यवस्था मुश्किलों से दो चार है। इसके बावजूद ट्रंप यह कहने में संकोच नहीं कर रहे कि उनका अगला निशाना क्यूबा होगा।
विक्रम चंद्रा@vikramchandra

पाकिस्तान भले ही मध्यस्थता की कोशिशों के माध्यम से सुर्खियों में आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दक्षिण एशिया में भारत बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका तक अपने पड़ोसियों को ईंधन मुहैया करा रहा है। इसे ईंधन कूटनीति कहा जा सकता है।
तेनजिंग लैमसांग@TenzingLamsang

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या 31 मार्च तक देश से माओवाद की समस्या खत्म होती दिख रही है?

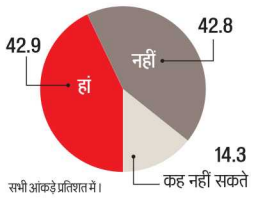

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या बुजुर्गों के लिए एक अलग विभाग खोले जाने से वृद्धजनों की समस्याएं कम होंगी?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

नेता गण भोंपू लिए फैलाते अफवाह,
उनका मकसद एक है रुके प्रगति की राह।
रुके प्रगति की राह करें हंगामा जनता,
जाय भाड़ में देश काम अपना है बनता!
कुटिल चाल चल आप बनेगे नहीं विजेता,
नहीं चाहते लोग कभी भी झूठा नेता!!
– ओमप्रकाश तिवारी

अजय शुक्ला
ajay.shukla@lko.jagran.com

उत्तर प्रदेश डायरी

'गांव' के चुनाव के नाम पर पसरा सन्नाटा

राजनीतिक रूप से मुखर रहने वाले उत्तर प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, लेकिन गांव की सरकार के चुनाव के नाम पर राजनीतिक दल चुप्पी साधे बैठे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जरूर पिछली सुनवाई में सख्त रुख दिखाया और राज्य निर्वाचन आयोग को अपनी तैयारियों का ब्यौरा देने को कहा। साथ ही, स्पष्ट शपथ पत्र देकर यह बताने को कहा कि 26 मई से पहले संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया (नामांकन, मतदान, परिणाम) पूरी की जा सकती है या नहीं। 26 मई को ही ग्राम पंचायतों (प्रधान व सदस्य), क्षेत्र पंचायत (बीडीसी) और जिला पंचायत के पदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है।

कोर्ट ने राज्य सरकार से भी अपेक्षा की कि अगली सुनवाई में एडवोकेट जनरल या एडिशनल एडवोकेट जनरल उपस्थित रहें। कोर्ट ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर दिया। यह सुनवाई 26 मार्च को होनी थी, लेकिन समयाभाव के कारण केस सूचीबद्ध नहीं हो सका और अब संभावना है कि अप्रैल में सुनवाई होगी। तब शायद स्पष्ट हो सके कि राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार की तैयारियां और मंशा क्या है। लेकिन, जिस तरह से पक्ष-विपक्ष दोनों तरफ के राजनीतिक दलों ने इस पर चुप्पी साध रखी है, उससे उनकी मंशा स्पष्ट नजर आने लगी है।

वैसे पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर (सुभासपा) बार-बार आश्वासन दे रहे हैं कि चुनाव जुलाई से पहले हर हाल में हो जाएंगे, लेकिन यह भी कहा है कि कोर्ट का फैसला और राज्य निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया अंतिम होगी। इस बात का कोई स्पष्ट जवाब अभी तक किसी स्तर से नहीं आया है कि जब तय था कि मई में कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो प्रक्रियाएं पहले से क्यों शुरू नहीं की गईं। मसलन, अभी तक नए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हुआ है और पिछले आयोग

प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रतीक्षा। फाइल

का कार्यकाल खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के अनुसार, आयोग को जनगणना 2011 के आधार पर पिछड़ापन तय करना है, फिर आरक्षण रोस्टर तैयार होगा। यह प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। इसमें समय लगेगा। इसके बिना या पिछली संस्तुतियों के आधार पर रोस्टर तैयार किया गया तो उसे आसानी से अदालती प्रक्रिया में उलझाया जा सकता है। अतीत में चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए ऐसा हो चुका है।

भाजपा के कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया जा चुका है कि वे पंचायत चुनाव के बजाय सीधे 2027 की तैयारी में जुटें। हालांकि, औपचारिक रूप से 'पूर्व तैयारी-पूर्ण तैयारी' का नारा देकर कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय करने, मतदाता सूची संशोधन जैसे कामों में लगाया गया है, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर कोई ब्रीफिंग नहीं दी जा रही है और न ही जमीनी स्तर पर भावी प्रत्याशियों के नाम की हलचल है। इसके पीछे कारण यह है कि भाजपा लोकसभा चुनावों में खिसके आधार के कारण 2027 के विधानसभा चुनावों को पहले से अधिक गंभीरता से ले रही है और नहीं चाहती कि पंचायत चुनावों के बहाने जमीनी कार्यकर्ताओं में कोई दोफाड़ हो। लंबे समय से सत्ता में होने के कारण नए कार्यकर्ताओं में भागीदारी का जोश है, जबकि पुराने नेता रास्ता बनाना नहीं चाहते।

अभी 16-17 मार्च को प्रदेश भर के नगर निकायों में 2802 पार्षद, सभासद और सदस्य नामित किए गए तो खुलकर विरोध नजर आया। यही हाल जिला कार्यकारिणी के गठन के बाद नजर आ रहा है। इन्हें समझाने-बुझाने के प्रयास चल रहे हैं। ऐसे में भाजपा नहीं चाहेगी कि पंचायत चुनावों के बहाने बगावत का एक और मोर्चा खुले। अधिकतर पंचायतों पर चूंकि भाजपा का ही अधिकार है, इसलिए वहां प्रशासक बैठाकर काम चलाया जा सकता है।

यह तो सत्ता पक्ष की बात रही, लेकिन विपक्ष भी पंचायत चुनावों को लेकर अन्यमनस्क स्थिति में है। यह तय है कि अब चुनाव तय समय पर नहीं हो सकते, लेकिन विपक्ष की तरफ से कहीं इसकी ठोस मांग नहीं उठ रही। मुख्य विपक्ष समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह आरोप जरूर लगाया कि भाजपा हार के डर से पंचायत चुनाव टाल रही है, लेकिन खुलकर मांग नहीं कर रहे कि तुरंत अधिसूचना जारी हो। दरअसल, सपा भी यह मानकर चल रही है कि लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त का मनोवैज्ञानिक लाभ तभी मिल सकता है जब घर मजबूत रहे। पंचायत चुनाव में कार्यकर्ताओं की निष्ठा में विचलन हो सकता है। कांग्रेस और बसपा का रुख भी इससे अलग नहीं है। शुरुआत में भाजपा के सहयोगी दलों और कांग्रेस ने जरूर यह प्रयास किए थे कि अकेले दम पर पंचायत चुनाव लड़कर ताकत परखी जाए, लेकिन अब उन्हें भी अहसास हो गया है कि विधानसभा चुनावों के पहले घर दुरुस्त रखना ज्यादा श्रेयष्कर है।

पंचायत चुनाव का मामला जनहित याचिका के जरिये पहले ही कोर्ट में पहुंच चुका है। यह तो तय है कि पंचायत चुनाव समय पर नहीं होंगे, लेकिन इसके विधानसभा चुनाव के बाद तक टलने की संभावनाओं पर अटकलें फिर भी कायम हैं। इसके पीछे दो सबसे मजबूत तर्क हैं। एक अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग के गठन की अनिवार्यता और दूसरे इस समय चल रही जनगणना प्रक्रिया में सरकारी कर्मचारियों की व्यस्तता। इन दोनों में ही समय और संसाधन लगेंगे और यह चुनाव टालने का मजबूत आधार बन सकते हैं। नजर अब हाई कोर्ट में दाखिल होने वाले शपथ पत्र और राज्य सरकार के रुख पर रहेगी।

मंथन

शुभम कुमार सानु
असिस्टेंट प्रोफेसर, इंद्रप्रस्थ कालेज फार वूमेन, दिल्ली विवि

नागरिक सुविधाओं का विकास

देश आज अधिकांश क्षेत्रों में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। वहीं, शहरीकरण की गति बहुत तेज है, परंतु उसके अनुरूप नागरिक सुविधाओं का विकास नहीं हो पा रहा है, जो चिंताजनक है

आवास एवं शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति द्वारा हाल ही में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) के लिए बीते पांच वर्षों की तुलना में बजट आवंटन में कमी आई है। वर्ष 2026-27 के लिए कुल बजट का 1.6 प्रतिशत ही शहरी विकास मंत्रालय के लिए आवंटित हुआ है, जो बीते पांच वर्षों में सबसे कम है। वहीं मंत्रालय का खर्चा वर्ष 2022-23 में 39 लाख करोड़ से बढ़कर अब 53 लाख करोड़ हो गया, जबकि बजट में मंत्रालय की हिस्सेदारी 1.9 से घटकर 1.6 प्रतिशत हो गई है। जहां बीते पांच वर्षों के समय अवधि में खर्चे में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो वहीं बजट आवंटन में 18 प्रतिशत की कटौती हुई है।

वर्ष 2026-27 के लिए 97 हजार करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के मुकाबले 12 प्रतिशत कटौती के साथ लगभग 85 हजार करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति दी गई है। जिस पर समिति ने शहरों पर दबाव के मद्देनजर चिंता जाहिर की है। मुख्य रूप से स्वच्छ भारत मिशन, पीएम ई-बस सेवा एवं राष्ट्रीय शहरी डिजिटल जैसी योजनाओं में प्रमुख रूप से कटौती की गई है। बजट आवंटन में गिरावट शहरी क्षेत्र के लिए चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं को प्रभावित कर सकता है।

सरकारी योजनाएं : वर्तमान परिवेश के अनुरूप शहरी क्षेत्र देश के विकास इंजन के तौर पर कार्य करती है, जहां 37.7 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। संबंधित आंकड़ों के अनुसार, 2047 तक देश की लगभग 50 प्रतिशत आबादी शहरों में होगी एवं जीडीपी में लगभग 80 प्रतिशत से अधिक की भागीदारी का अनुमान है। इस क्रम में शहरी क्षेत्र के लिए बजट में प्रमुखता से भागीदारी को सुनिश्चित करना समय की नजाकत है। बढ़ती शहरी आबादी एवं जरूरतों के अनुसार भारत सरकार विभिन्न आयामों को ध्यान में रखकर अनेक प्रकार की सराहनीय योजनाएं चला रही है। शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और मेट्रो परियोजना। शहरी जरूरतमंद लाभार्थियों को हर मौसम काम में आने वाले पक्के घर के लिए शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना। शहरी गरीबों व प्रवासियों को कार्य क्षेत्र के नजदीक किराये के आवास मुहैया कराने के लिए किफायती किराया आवास परिसर योजना। पांच सौ चयनित शहरों में बुनियादी ढांचों से जुड़े चुनौतियों के समाधान हेतु अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)।

सभी शहरों को कचरा मुक्त एवं खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन योजना। शहरों में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने हेतु पीएम बस सेवा योजना। स्ट्रीट वेंडरों को बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, विभिन्न राज्यों में जल आपूर्ति, सीवरेज बोर्ड आदि में सेवरत इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग क्षेत्र विकास योजना। सर्कुलर इकोनमी को बढ़ावा देने एवं जलवायु उन्मुख सुधार, संस्थागत मजबूती एवं ज्ञान प्रसार के लिए सिटी इन्वेस्ट, इन्वेट, इंटीग्रेटेड, सस्टेन योजना। शहरी क्षेत्रों में डिजिटल सेवा से जुड़े आयाम के लिए राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन। इस वर्ष के बजट में शहर के रचनात्मक पुनर्विकास, जल, स्वच्छता एवं शहरों को विकास केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए शहरी चुनौती कोश का प्रस्ताव। बजट 2025-26 में औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े कामगारों के लिए औद्योगिक आवास योजना।

प्रतीकात्मक

भारत सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं एवं आवंटित राशियों को देख कर लगता है कि भारत के शहरी क्षेत्र की सारी समस्याओं का समाधान इन सभी कार्य योजनाओं में ही है। परंतु जब हम आजादी के बाद से चल रही योजनाओं एवं उसके जमीनी स्तर पर परिणाम को देखते हैं तो क्रियान्वयन एवं सुधार के स्तर पर बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। संबंधित आंकड़ों के अनुसार, 2014 से अब तक लगभग 18 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा भारत में शहरी विकास के लिए निवेश किया गया है। आंकड़ों का निरीक्षण यह भी दर्शाता है कि मोटे तौर पर साल दर साल शहरी निवेश में वृद्धि हुई है, परंतु अभी भी इन आर्थिक आयाम से परे शहरों की विभिन्न समस्याएं जस के तस समाधान का राह देख रही हैं।

विभिन्न योजनाओं एवं बजट आवंटन के बाद क्रमशः विभिन्न समस्याओं का आकलन दर्शाता है कि शहरी क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु नियमित रूप से तय जवाबदेही के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। केंद्र, राज्य एवं स्थानिक निकायों को एक प्लेटफार्म पर आकर कार्य करने की जरूरत है। योजनाओं की पहुंच को तय करने के लिए अभी भी बहुत कार्य करना होगा। इसके लिए हमें शहरों के साथ ही गांवों को भी योजना के केंद्र में लाना होगा।

इंटेलियस रीकोड ने सेबी के पास जमा किए आइपीओ दस्तावेज

नई दिल्ली : टेक्नोलाजी से जुड़े समाधान प्रदान करने वाली कंपनी इंटेलियस रीकोड लिमिटेड ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) के जरिये पैसा जुटाने के लिए सेबी के पास प्रारंभिक दस्तावेज जमा किए हैं। दस्तावेजों के अनुसार, इस प्रस्तावित आइपीओ में 117 करोड़ रुपये के नए शेयर और 12.9 लाख प्रमोटर शेयर बिक्री के लिए पेश किए जाएंगे। नए शेयरों की बिक्री से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल डिजिटल कामगारों के विकास, फीस और सामान्य कारपोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। (प्रेट्र)

हमारा आधुनिक जीपीयू आधारित उच्च प्रदर्शन वाला कंप्यूटिंग प्लेटफार्म हेलिओस भारत समेत कई देशों में इस वर्ष की दूसरी छमाही में शुरू हो जाएगा।
— महेश बालासुब्रमण्यन, वरिष्ठ निदेशक, एएमडी

पश्चिम एशिया में संघर्ष से घट सकता है रेमिटेंस

एसबीआइ फंड्स के मुताबिक- कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से दबाव में आ सकता है राजकोषीय संतुलन

नई दिल्ली, एएनआइ: पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के चलते भारत को रेमिटेंस, रुपये में कमजोरी और राजस्व का नुकसान उठाना पड़ सकता है। एसबीआइ फंड्स मैनेजमेंट की एक रिपोर्ट '2026 पश्चिम एशिया संघर्ष और इसके प्रभाव' में बताया गया है कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से भारत का राजकोषीय संतुलन कई तरह से दबावों में आ सकता है। एक मुख्य जोखिम खाड़ी क्षेत्र से आने वाले रेमिटेंस में कमी आना है, जो विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा घर भेजे जाने वाले फंड का एक बड़ा हिस्सा होता है।

रिपोर्ट के अनुसार, कुल आने वाले रेमिटेंस का लगभग 38% हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है। इसमें से भी आधा हिस्सा अकेले संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से आता है। रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं, तो चालू खाता घाटा (कैड) और बढ़ सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कच्चे तेल की कीमत में प्रति बैरल 10 डालर की बढ़ोतरी से सालाना चालू खाता घाटा 15 अरब डालर तक बढ़ जाता है। रिपोर्ट में इस बात की भी आशंका जताई गई है कि अगर कच्चे तेल की कीमत लंबे समय तक 100 डालर प्रति बैरल के आसपास बनी रहती हैं तो चालू खाता घाटा तेजी से बढ़ सकता है। ऊंची कीमतों वाली स्थिति का अनुमान लगाते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू खाता घाटा 70 अरब डालर तक बढ़ सकता है।

38% हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है कुल आने वाले रेमिटेंस का, इसमें यूएई का आधा हिस्सा

10 डालर प्रति बैरल तेल के मूल्य की बढ़ोतरी से सालाना 15 अरब डालर तक बढ़ जाता है चालू खाता घाटा

फर्टिलाइजर महंगाई से 30 हजार करोड़ बढ़ सकता है सब्सिडी बिल

एसबीआइ फंड मैनेजमेंट ने रिपोर्ट में कहा है कि वैश्विक स्तर पर उर्वरकों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। दिसंबर, 2025 के मुकाबले अब यूरिया की कीमत लगभग 50% अधिक हो गई है। यदि लागत का स्तर ऊंचा बना रहता है, तो सब्सिडी की जरूरत काफी बढ़ सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार का उर्वरक सब्सिडी बिल बजट में निर्धारित राशि से काफी अधिक बढ़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गैस की बढ़ती कीमतें और फर्टिलाइजर की महंगाई सब्सिडी की जरूरत को 30 हजार करोड़ रुपये या उससे ज्यादा बढ़ा सकती हैं। रिपोर्ट के अनुसार, भारत के चालू खाते की स्थिति में ढांचागत सुधार और वित्त वर्ष 2014-15 से चालू खाता घाटा के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के दो प्रतिशत से नीचे रहने के बावजूद भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति काफी कमजोर हुई है और इसकी वजह एफडीआइ का प्रवाह लगभग शून्य होना है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसकी वजह से भारत के बुनियादी संतुलन में गिरावट आई है।

2026 में चार से पांच प्रतिशत तक गिर सकता है रुपया : बाहरी क्षेत्र पर पड़ने वाला यह दबाव मुद्रा बाजार पर भी असर डाल सकता है और अगर विदेशी निवेश का प्रवाह अस्थिर बना रहता है तो रुपया और कमजोर हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है, 'यदि एफआइआइ (विदेशी संस्थागत निवेशक) का प्रवाह फिर से नहीं बढ़ता है तो रुपया वैश्विक झटकों के प्रति संवेदनशील बना रहेगा। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2026 में रुपये के मूल्य में 4-5 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है। पहले यह अनुमान 2-3 प्रतिशत था। फिलहाल डालर के मुकाबले रुपया 94.85 पर कारोबार कर रहा है और अगले दो तिमाहियों में इसके 96 के पार पहुंचने की उम्मीद है।

2026 में जीवन, साधारण बीमा कारोबार शुरू करेगी जियो फाइनेंशियल

मुंबई, प्रेट्र: मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह की वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को उम्मीद है कि वह इसी वर्ष जीवन और साधारण बीमा कारोबार शुरू कर देगी। हालांकि, कंपनी की अभी असुरक्षित और उपभोक्ता लोन कारोबार में उतरने की कोई योजना नहीं है।

कंपनी के सीईओ और प्रबंध निदेशक हितेश सेठिया ने हाल ही में कहा था कि नियामकीय मंजूरी मिलने के बाद हम बीमा कारोबार शुरू कर देंगे। कंपनी ने हाल ही में अपने संयुक्त पार्टनर आलियांज के साथ मिलकर री-इंश्योरेंस कारोबार में कदम रखा है। अब साधारण और जीवन बीमा कारोबार के लिए भी इस फ्रेंच कंपनी के साथ भागीदारी की जाएगी। सेठिया ने बताया कि कंपनी बीमा कारोबार में उतरने के लिए जरूरी टीमें बनाने पर भी काम कर रही है। कंपनी पहले ही जियोफाइनेंस एप के जरिये थर्ड-पार्टी लोन उत्पाद बेच रही है।

एनसीआर में तिमाही आधार पर घरों की बिक्री में 17% की गिरावट

नई दिल्ली, प्रेट्र: दिल्ली समेत एनसीआर में जनवरी-मार्च के दौरान घरों की बिक्री पिछली तिमाही के मुकाबले 17 प्रतिशत घटकर लगभग 16 हजार यूनिट रह गई। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के चलते पैदा हुए नकारात्मक माहौल का घरों की बिक्री पर असर दिखाई पड़ा। हालांकि, पिछले साल के कम आधार प्रभाव के कारण सालाना आधार पर मांग में 44 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

रियल एस्टेट कंसल्टेंट एनाराक के मुताबिक, जनवरी-मार्च तिमाही में एनसीआर में घरों की बिक्री 15,985 यूनिट रही, जो अक्टूबर-दिसंबर 2025 के 19,250 यूनिट की तुलना में 17 प्रतिशत कम है। एनसीआर में बिक्री पिछले साल की समान अवधि की 11,120 यूनिट की तुलना में 44 प्रतिशत बढ़ी है। एनाराक के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा कि भारत के आवासीय क्षेत्र की दीर्घकालिक बुनियाद मजबूत बनी हुई है, लेकिन ईरान युद्ध के अल्पकालिक झटके पहली तिमाही में साफ तौर पर दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि युद्ध के कारण पैदा हुई अनिश्चितता ने लोगों के खरीदने के इरादों को प्रभावित किया है। पुरी ने कहा कि यह गिरावट पश्चिम एशिया के उन संभावित घर खरीदारों की बड़ी संख्या से भी मेल खाती है, जो भारतीय रियल एस्टेट में भारी निवेश करते हैं, लेकिन उन्होंने फिलहाल अपना निवेश रोक दिया है। कंसिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर के सीईओ ऋषि राज ने कहा कि घर खरीदार अब ऐसी परियोजनाओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जो स्थान, गुणवत्ता व अनुभव का बेहतरीन मेल पेश करती हैं।

- जनवरी-मार्च 2026 के दौरान इस क्षेत्र में 16 हजार घरों की बिक्री
- अक्टूबर-दिसंबर 2025 के दौरान 19,250 घरों की बिक्री हुई थी

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

बैंकों ने नई विदेशी मुद्रा सीमा के पालन के लिए मांगे तीन महीने

मुंबई, रायटर: बैंकों ने आरबीआइ से नई विदेशी मुद्रा सीमा का पालन करने के लिए तीन महीने का समय देने का आग्रह किया है। बैंकों ने कहा कि अगर इसे जल्दबाजी में लागू किया गया तो अफरातफरी मच सकती है और नुकसान हो सकता है। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद आरबीआइ ने भारतीय रुपये की गिरावट को रोकने और सट्टा व्यापार पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से बैंकों को निर्देश दिया है कि वे आनशोर रुपये में अपनी दिन की अंतिम ओपन पोजिशन को 10 करोड़ डालर तक सीमित करें। केंद्रीय बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को 10 अप्रैल तक दैनिक सीमा अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्देश दिया है।

- आरबीआइ से कहा-अगर इसे जल्दबाजी में लागू किया गया तो मच सकती है अफरातफरी
- बैंकों को आनशोर रुपये में अपनी अंतिम पोजिशन को 10 करोड़ डालर तक रखने का निर्देश

आनशोर स्थितियों पर सीमाएं लगाने का यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब रुपये पर दबाव बढ़ रहा है। यह फैसला लेने की वजह तेल की कीमतों में तेजी और ईरान युद्ध शुरू होने के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआइ) का बड़े पैमाने पर बाहर जाना है। हालांकि, नए नियमों की अधिसूचना जारी होने के बाद स्थानीय और विदेशी दोनों तरह के बैंकों के वरिष्ठ ट्रेजरी अधिकारियों ने आरबीआइ के अधिकारियों से मुलाकात की और अपनी चिंताएं बताईं। उन्होंने कहा कि इन नियमों की वजह से नान-डिलिवरेबल फारवर्ड (एनडीएफ) और आनशोर बाजारों के बीच होने वाले आर्बिट्रेज सौदों को अचानक खत्म करना पड़ सकता है। इससे बैंकों को सौदों पर संभावित नुकसान का जोखिम उठाना पड़ सकता है।

लिखित पुष्टि के बावजूद जेपी समूह की संपत्ति की बोली पर पलटा गया फैसला : अग्रवाल

नई दिल्ली, प्रेट्र: खनन उद्योग के दिग्गज कारोबारी अनिल अग्रवाल ने रविवार को दावा किया कि उनकी कंपनी वेदांत को जेपी समूह की संपत्ति की बोली जीतने की लिखित पुष्टि मिल गई थी, लेकिन बाद में यह फैसला बदल दिया गया। हालांकि, उन्होंने इसके कारणों पर विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी। जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) को जून, 2024 में दिवालिया प्रक्रिया में शामिल किया गया था, क्योंकि कंपनी पर करीब 57,185 करोड़ रुपये का ऋण था।

अग्रवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वेदांत को दिवालिया प्रक्रिया के तहत जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) को खरीदने के लिए सार्वजनिक रूप से सबसे ऊंची बोली लगाने वाला घोषित किया गया था। उन्हें लिखित रूप में यह जानकारी दी गई थी कि उनकी कंपनी बोली जीत चुकी है, लेकिन कुछ दिन बाद यह फैसला बदल दिया गया। जेपी समूह की इस प्रमुख कंपनी के लिए बोली में गौतम अदाणी का समूह ही दूसरा बड़ा दावेदार था। पिछले साल नवंबर में ऋणदाताओं की समिति ने अदाणी समूह की योजना को स्वीकार कर लिया था। नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल ने हाल ही में अदाणी को योजना को मंजूरी दी है।

अनिल अग्रवाल • फाइल फोटो

- वेदांत समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का एक्स पोस्ट में दावा
- पिछले साल नवंबर में अदाणी समूह की योजना हुई थी स्वीकार

अगले माह पांच कंपनियों में हो जाएगा वेदांत का बंटवारा

बेंगलुरु, रायटर: दिग्गज खनन समूह वेदांत का अगले महीने की शुरुआत में पांच सूचीबद्ध कंपनियों में बंटवारा हो जाएगा। फाइनेंशियल टाइम्स ने वेदांत के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के साथ एक इंटरव्यू का हवाला देते हुए यह बात कही है। कंपनी कई वर्ष से पुनर्गठन कार्यक्रम चला रही है, जिसके तहत यह बंटवारा हो रहा है।

तेल से लेकर धातु तक का कारोबार करने वाले वेदांत को पांच अलग-अलग सूचीबद्ध कंपनियों में बांटने की योजना को दिसंबर 2025 में एक ट्रिब्यूनल ने मंजूरी दे दी थी। इस बंटवारे के बाद वेदांत लिमिटेड के पास उसका धातु कारोबार रह जाएगा। वेदांत एल्युमीनियम, तलवंडी साबो पावर, वेदांता स्टील एंड आयरन और माल्को एनर्जी बाकी चार कंपनियां होंगी।

टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए कल तक कर लें निवेश

जागरण संवाददाता, कानपुर: यदि आपने पुरानी कर प्रणाली में अपना रखी है तो सकल आय से कर छूट पाने के लिए करदाताओं को अपने निर्धारित खर्च व निवेश का काम 31 मार्च तक पूरा कर लेना होगा। इस तिथि तक निर्धारित खर्च एवं निवेश नहीं करने वालों को चालू वित्त वर्ष 2025-26 या कर निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए देय आयकर से छूट नहीं मिलेगी।

कर विशेषज्ञ एडवोकेट संतोष कुमार गुप्ता के अनुसार, पुरानी कर प्रणाली में धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये तक की कटौती का लाभ लिया जा सकता है। इस छूट के लिए बीमा एवं बचत योजनाओं में निवेश किया जा सकता है, जिसमें एलआइसी की किस्तें, पीपीएफ, ईपीएफ, और सुकन्या समृद्धि योजना शामिल हैं। बच्चों की ट्यूशन फीस, होम लोन के मूलधन का भुगतान और स्वास्थ्य एवं पेंशन पर भी लाभ लिया जा सकता है। मेडिक्लेम के तहत सामान्य नागरिकों को 25,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये तक की छूट निर्धारित है। होम लोन ब्याज पर भी छूट प्राप्त की जा सकती है, जबकि उच्च शिक्षा के लिए ऋण पर ब्याज की पूरी कटौती मिलती है। नई कर प्रणाली में वेतनभोगियों की 12.75 लाख रुपये और गैर-वेतनभोगियों की 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई कर नहीं है।

31 मार्च को समाप्त होने जा रहा है वित्त वर्ष 2025-26, पुरानी कर प्रणाली वालों को मिलती है निवेश पर कर छूट

सात कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 1.75 लाख करोड़ रुपये घटा

नई दिल्ली, प्रेट्र: बीते सप्ताह घरेलू बाजारों में रही गिरावट का कंपनियों के बाजार पूंजीकरण पर नकारात्मक असर पड़ा है। सप्ताह के दौरान बीएसई में सूचीबद्ध शीर्ष-10 कंपनियों में से सात के बाजार पूंजीकरण में 1.75 लाख करोड़ रुपये की कमी दर्ज की गई है। साप्ताहिक आधार पर बीएसई सेंसेक्स में 949.74 अंक और एनएसई निफ्टी में 204.9 अंक की गिरावट रही है।

बीते सप्ताह रिलायंस इंडस्ट्रीज के पूंजीकरण में सबसे ज्यादा 89,720.3 करोड़ रुपये की कमी आई है। अब कंपनी का पूंजीकरण 18,24,515.62 करोड़ रुपये रहा गया है। इसके अलावा, एचडीएफसी बैंक, एसबीआइ, आइसीआइसीआइ बैंक, भारती एयरटेल, हिंदुस्तान यूनीलिवर और टीसीएस का पूंजीकरण भी घटा है। सप्ताह के दौरान लार्सन एंड टूब्रो, बजाज फाइनेंस और इन्फोसिस का पूंजीकरण संयुक्त रूप से 32,977.34 करोड़ रुपये बढ़ा है।

अंतरराष्ट्रीय

न्यूज गैलरी

यूरोप में 12 टन किटकैट चाकलेट चोरी

ज्यूरिख : स्विटजरलैंड की कंपनी नेस्ले की 12 टन किटकैट चाकलेट बार पिछले सप्ताह यूरोप में चोरी हो गई। इटली से 413,793 चाकलेट ले जा रहा ट्रक अपने अंतिम गंतव्य पोलैंड नहीं पहुंचा। कंपनी ने कहा है कि उपभोक्ता, खुदरा व थोक विक्रेता पैक पर अंकित बैच नंबर स्कैन कर यह पहचान कर सकेंगे कि उत्पाद चोरी की गई खेप का हिस्सा है या नहीं। (रायटर)

भारतीय राजदूत ने की मक्का में हज तैयारियों की समीक्षा

मक्का : सऊदी अरब में गत दिवस भारतीय राजदूत सुहेल खान ने मक्का में हज तैयारियों की व्यापक समीक्षा की और शिविरों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। भारतीय दूतावास ने एक पोस्ट कर कहा, राजदूत डा. सुहेल खान ने महावाणिज्य दूताधिकारी जेद्दा फहद सूरी व हज अधिकारी सदफ चौधरी संग तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। (एएनआइ)

डब्ल्यूटीओ में भारत ने मत्स्य पालन सब्सिडी पर मांगी 25 साल की छूट

नई दिल्ली, प्रेट्र: विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में भारत ने मत्स्य पालन सब्सिडी को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए 25 साल की छूट मांगी है। साथ ही गहरे पानी में मछली पकड़ने वाले औद्योगिक बेड़ों पर कड़े नियम और मछली पालन सब्सिडी समझौते के दूसरे चरण के तहत पारंपरिक तरीके से मछली पकड़ने वालों के लिए एक स्थायी छूट की मांग की है।

वाणिज्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि मछली पालन सब्सिडी उन मुख्य विषयों में से एक थी, जिन पर 26-29 मार्च को कैमरून के याउंडे में आयोजित डब्ल्यूटीओ के 14वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में चर्चा की गई।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उस मंत्रिस्तरीय फैसले को आकार देने में सक्रिय रूप से योगदान दिया, जो मछली पालन सब्सिडी पर दूसरे चरण की बातचीत के भविष्य के मार्ग को निर्धारित करता है। वार्ता के दौरान भारत ने कई बार इस बात पर जोर दिया कि दूसरे चरण की बातचीत में समानता के मूल सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए।

- भारत ने पारंपरिक तरीके से मछली पकड़ने वालों के लिए एक स्थायी छूट मांगी
- वाणिज्य मंत्री ने कहा- मछली पालन भारत की खाद्य सुरक्षा का प्रमुख आधार

पीयूष गोयल। फाइल

पीयूष गोयल ने कहा कि मछली पालन क्षेत्र भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और आजीविका प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह 90 लाख से ज्यादा मछुआरे परिवारों को सहारा देता है, जिनमें ज्यादातर छोटे, पारंपरिक मछुआरे शामिल हैं।

उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि भारत मछली पकड़ने वाला कोई बड़ा औद्योगिक देश नहीं है और ना ही उसके पास गहरे पानी में मछली पकड़ने वाले बड़े बेड़े हैं और ना ही भारी मशीनों से काम होता है।

ई-कामर्स पर कस्टम ड्यूटी छूट बढ़ाने पर बातचीत अटकी

रायटर्स के अनुसार, राजनयिकों ने रविवार को बताया कि डब्ल्यूटीओ में ई-कामर्स पर कस्टम ड्यूटी को लेकर इस महीने खत्म होने जा रही रोक को आगे बढ़ाने पर बातचीत अटक गई है। हालांकि एक व्यापक सुधार योजना पर समझौता होने के करीब है। बातचीत के दौरान अमेरिका और भारत के बीच ई-कामर्स पर लगी रोक को आगे बढ़ाने को लेकर मतभेदों को सुलझाने के प्रयास भी शामिल हैं। यह रोक सबसे पहले 1998 में डिजिटल व्यापार की शुरुआती बढ़त को बढ़ावा देने के लिए अपनाई गई थी।

इतना ही नहीं भारत की मछली पालन सब्सिडी दुनिया में सबसे कम (हर साल प्रति मछुआरा परिवार लगभग 15 डालर) है।

वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, "भारत ने विश्व व्यापार संगठन के 14वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के मंच से अपनी इस बात को जोरदार तरीके से रखा कि जो भी फैसले सामने आते हैं, वे निष्पक्ष हों और कमजोर देशों पर उनका कोई बुरा असर नहीं पड़े।'

ईंधन की खेप भेजने के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति ने मोदी को दिया धन्यवाद

कोलंबो, प्रेट्र : श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने रविवार को द्वीप राष्ट्र में ईंधन आपूर्ति में आई बाधाओं को दूर करने के लिए तेल की खेप भेजने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया। इंडियन आयल कार्पोरेशन के स्थानीय संचालन, लंका आईओसी के माध्यम से आपातकालीन मदद के रूप में 20,000 मीट्रिक टन डीजल, 18,000 मीट्रिक टन पेट्रोल की खेप शनिवार को कोलंबो पहुंची।

दिसानायके ने एक पोस्ट में कहा, "कुछ दिन पहले मैंने पीएम मोदी से पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण श्रीलंका में ईंधन आपूर्ति में आई बाधाओं के बारे में बात की थी। भारत की त्वरित सहायता के लिए आभारी हूं। 38,000 मीट्रिक टन ईंधन कोलंबो पहुंच गया है।" वहीं, एएनआइ के अनुसार श्रीलंका के उप विदेश मंत्री अरुण हेमचंद्र ने कहा, इस तरह का सहयोग दोनों पड़ोसी देशों के बीच गहरे संबंधों व जरूरत के समय तुरंत प्रतिक्रिया देने की क्षमता को दर्शाता है।, "वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में श्रीलंका को ईंधन की आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित करने में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत द्वारा दिए गए समर्थन के लिए हम उनकी सराहना करते हैं।" उन्होंने क्षेत्र में भारत की भूमिका के महत्व पर भी जोर दिया।

- ईंधन आपूर्ति में बाधा आने के बाद पीएम मोदी से की थी बात
- भारत ने की सहायता, 38,000 मीट्रिक टन ईंधन कोलंबो पहुंचा

अनुरा दिसानायके। फाइल

उ. कोरिया ने अमेरिका को निशाना बनाने वाली मिसाइल के इंजन का किया परीक्षण

सियोल, एपी : उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी मुख्यभूमि को निशाना बनाने में सक्षम मिसाइल के इंजन का परीक्षण किया है। इसका अवलोकन नेता किम जोंग उन ने किया। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने बताया कि किम ने इंजन के ग्राउंड जेट परीक्षण को देखा। इंजन की अधिकतम शक्ति 2,500 किलोटन है, जो सितंबर में इसी तरह के ठोस-ईंधन इंजन के परीक्षण में रिपोर्ट की गई 1,970 किलोटन से अधिक है। यह परीक्षण देश के पांच वर्षीय हथियार निर्माण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में किया गया था, जिसका उद्देश्य परमाणु-सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों और अन्य हथियारों को उन्नत करना है।

उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने कहा कि नवीनतम इंजन परीक्षण देश की रणनीतिक सैन्य शक्ति को सर्वोच्च स्तर पर पहुंचाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि यह नहीं बताया गया कि परीक्षण कब और कहां हुआ।

- देश के शासक किम जोंग उन ने इंजन के ग्राउंड जेट परीक्षण को देखा
- 2500 किलोटन है इंजन की अधिकतम शक्ति

दक्षिण कोरिया के शोधकर्ता ली चून ग्यून ने कहा कि उत्तर कोरिया की नवीनतम परीक्षण पर रिपोर्ट "झूठी" हो सकती है, क्योंकि इसमें इंजन के कुल दहन समय जैसी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी गई। उत्तर कोरिया ने सितंबर के महीन में किए गए परीक्षण को ठोस ईंधन इंजन का नौवां और अंतिम जमीनी परीक्षण बताया था, जिसके बारे में उसने पहले कहा था कि इसका उपयोग अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए किया जाएगा।

उस समय पर्यवेक्षकों ने भविष्यवाणी की थी कि उत्तर कोरिया जल्द ही उस इंजन से लैस एक आइसीबीएम का परीक्षण करेगा, लेकिन उसने अभी तक ऐसा नहीं किया है।

राष्ट्रपति ट्रंप जैसी निर्वासन रणनीति अपना रहा यूरोप

ब्रसेल्स, एपी : यूरोपीय संघ (ईयू) अवैध प्रवासियों को ट्रैक करने, उन पर छापे मारने और उन्हें अफ्रीका और अन्य देशों में स्थित "वापसी केंद्रों" में निर्वासित करने की अपनी शक्तियों का विस्तार कर रहा है।

यह कदम चुपचाप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा अपनाई गई विवादास्पद रणनीति की नकल है। इसकी मानवाधिकार समूहों ने कड़ी आलोचना की है। ये कदम 2024 के बाद कई यूरोपीय संघ के देशों में दक्षिणपंथी दलों के उदय के बाद उठाए गए हैं और प्रवासन और शरण पर नए समझौते का हिस्सा हैं, जो 12 जून से प्रभावी होने वाला है।

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयेन ने कहा कि इसका उद्देश्य 2015 के सीरियाई युद्ध से प्रेरित संकट की पुनरावृत्ति को रोकना है, जब लगभग दस लाख लोग शरण मांगने यूरोप पहुंचे थे। उन्होंने कहा, "हमने अतीत से सबक सीखा है और आज, हम बेहतर ढंग से तैयार हैं।"

नेपाल में अब पूर्व ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का गिरफ्तार

विरोध प्रदर्शनों के बीच ओली को पांच दिनों की न्यायिक हिरासत

काठमांडू, प्रेट्र : पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक की गिरफ्तारी के बाद अब नेपाली कांग्रेस के नेता एवं पूर्व ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का को मनी लांड्रिंग के मामले में रविवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नेपाल पुलिस के केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीआइबी) के प्रवक्ता शिव कुमार श्रेष्ठ के अनुसार, यह कार्रवाई 'मनी लांड्रिंग जांच विभाग' के अनुरोध पर की गई है।

- पुलिस ने नेपाली कांग्रेस नेता खड़का पर मनी लांड्रिंग के मामले में की है कार्रवाई
- शनिवार को पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री लेखक हुए थे गिरफ्तार

भ्रष्टाचार और मनी लांड्रिंग के गंभीर आरोप : खड़का पर आरोप है कि उन्होंने ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान परियोजनाओं के लाइसेंस और अनुबंध दिलाने के बदले अनुचित वित्तीय लाभ उठाए थे।

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली की गिरफ्तारी के बाद रविवार को काठमांडू में विरोध प्रदर्शन कर रहे उनके समर्थकों को रोकती पुलिस। रायटर

रविवार को ओली और लेखक को काठमांडू जिला अदालत में पेश किया गया। अस्पताल में भर्ती होने के कारण ओली वर्चुअली पेश हुए, जबकि रमेश लेखक को पुलिस व्यक्तिगत रूप से अदालत लेकर पहुंची। ओली को अदालत ने पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में और तत्काल रिहाई की मांग को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन जारी हैं। उधर, हत्याओं से जुड़ी वारदातों में कथित संलिप्तता की आगे की जांच के लिए दस दिन की हिरासत की मांग करते हुए लेखक को अदालत में पेश किया गया था। उन्हें भी पांच दिन की हिरासत में भेज दिया गया है।

इसके अलावा, पिछले साल हुए 'जेन-जी' विरोध प्रदर्शन के दौरान खड़का, पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और पुष्प कमल दहल के आवासों से जले हुए बैंक नोटों के टुकड़े मिलने की तस्वीरें और वीडियो सामने आए थे, जिनकी पुष्टि बाद में फारेंसिक लैब की जांच में भी हुई थी।

एम्स नर्सिंग की पूर्व छात्रा निशा मेहता बनीं नेपाल की स्वास्थ्य मंत्री

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : एम्स नई दिल्ली के कालेज आफ नर्सिंग की पूर्व छात्रा निशा मेहता को नेपाल का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया है। एम्स प्रबंधन ने उन्हें बधाई देते हुए कहा है कि यह उपलब्धि न सिर्फ संस्थान, बल्कि पूरे नर्सिंग समुदाय के लिए गर्व का विषय है। एम्स की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि निशा मेहता ने वर्ष 2006 से 2010 के बीच एम्स से बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई की थी। छात्र जीवन के दौरान उन्होंने नेतृत्व क्षमता, शैक्षणिक उत्कृष्टता और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी कर अलग पहचान बनाई थी। यही गुण आगे चलकर उन्हें नीति-निर्माण के उच्च स्तर तक ले गए। उनकी यह नियुक्ति इस बात को रेखांकित करती है कि नर्सिंग पेशा केवल मरीजों की देखभाल तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य नीतियों और सिस्टम के निर्माण में भी अहम भूमिका निभा सकता है। गौरतलब है कि निशा मेहता ने गत शुक्रवार को नेपाल की स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर शपथ ली थी।

निशा मेहता।

29 मार्च को पोप लियो ने कहा कि ईश्वर उन नेताओं की प्रार्थनाओं को अस्वीकार करता है, जो युद्ध शुरू करते हैं और जिनके हाथ खून से सने हैं। उन्होंने सेंट पीटर स्क्वायर में हजारों लोगों के सामने पाम संडे की प्रार्थना सभा के दौरान विशेष रूप से पश्चिम एशिया में रहने वाले ईसाइयों के लिए प्रार्थना की।

दैनिक जागरण 11
सोमवार, 30 मार्च, 2026
www.jagran.com

स्कूल पर हमले के लिए दो अमेरिकी अधिकारियों की तस्वीर ईरान ने जारी की

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

- ईरान सरकार बोली - इन्हीं अधिकारियों ने स्कूल पर टामहाक मिसाइलें दागने का दिया था आदेश
- महीने की शुरुआत में मिनाब के स्कूल पर किए गए हमले में गई थी 168 बच्चों की जान

ईरान ने मिनाब के स्कूल पर हुए मिसाइल हमले के लिए अमेरिका नौसेना के दो अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए उनकी तस्वीरें जारी की हैं और कहा है कि इन दो अपराधियों को याद रखें। ईरान की ओर से साझा की गई एक पोस्ट के अनुसार, इन अधिकारियों ने स्कूल पर टामहाक मिसाइलें दागने का आदेश दिया था। इस हमले में 168 बच्चों की जान गई थी।

ईरान ने कहा है कि अमेरिकी युद्धपोत सप्रुआंस के कमांडर लीआर टेट और कार्यकारी अधिकारी जेफरीई यार्क ने मिनाब के स्कूल पर हमले की योजना बनाई थी। उन्होंने तीन बार टामहाक मिसाइलें दागने का आदेश दिया था। ईरान ने दोनों अमेरिकी सैन्य अधिकारियों को युद्ध अपराधी बताया है। इस महीने के शुरुआत में अमेरिकी और इजरायली सेनाओं ने आपरेशन 'एपिक फ्यूरी' के पहले दिन यह हमला किया था। इसमें स्कूल को निशाना बनाने के साथ-साथ पास में स्थित आइआरजीसी द्वारा संचालित एक नौसैनिक अड्डे पर भी एक साथ हमला किया था। अमेरिकी मीडिया ने संकेत दिया था कि स्कूल को नुकसान उस क्षेत्र में मौजूद सैन्य ठिकानों के खिलाफ चलाए जा रहे समन्वित और सटीक अभियानों के हिस्से के तौर पर हुआ था। न्यूयार्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, होर्मुज स्ट्रेट के पास स्थित नौसैनिक अड्डों को निशाना बनाने वाले आधिकारिक अमेरिकी बयानों से यह संकेत मिलता है कि स्कूल पर हमले के पीछे संभवतः अमेरिकी सेनाओं का ही हाथ था।

ईरान युद्ध व ट्रंप के खिलाफ 'नो किंग्स' रैलियों में उमड़ी लाखों लोगों की भीड़

- अमेरिका में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के प्रभुत्व वाले राज्यों में समान रूप से दिखा आक्रोश
- लंदन, पेरिस, रोम जैसे यूरोपीय शहरों में भी ट्रंप के "अनैतिक युद्ध' के विरोध में फूटा गुस्सा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ शनिवार को शिकागो के ग्रांट पार्क में 'नो किंग्स' के नाम से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लोग तख्तियां और झंडे लेकर रैली में शामिल हुए। एएपपी

सेंट पाल, एपी : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार्यशैली, ईरान के साथ युद्ध और सख्त आव्रजन नीतियों के खिलाफ शनिवार को अमेरिका से लेकर यूरोप तक लाखों लोगों ने सड़कों पर उतरकर 'नो किंग्स' रैलियों के जरिये अपना विरोध प्रकट किया। इन प्रदर्शनों में उमड़े जनसैलाब ने दुनिया का ध्यान खींचा है। उल्लेखनीय बात यह है कि यह आक्रोश अमेरिका में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के प्रभुत्व वाले राज्यों में समान रूप से देखने को मिला है। वहीं, दूसरी ओर लंदन, पेरिस और रोम जैसे यूरोपीय शहरों में भी ट्रंप के "अनैतिक युद्ध' के विरोध में लोगों का गुस्सा फूटा है।

छोटे कस्बे से लेकर महानगरों तक विरोध की गूंज : इन प्रदर्शनों की सबसे खास बात यह रही कि इसमें केवल डेमोक्रेट्स के गढ़ वाले 'ब्लू स्टेट्स' ही नहीं, बल्कि रिपब्लिकन प्रभुत्व वाले 'रेड स्टेट्स' में भी भारी भीड़ देखी गई। न्यूयार्क जैसे महानगर (85 लाख आबादी) से लेकर इडाहो के छोटे से कस्बे ड्रिग्स (दो हजार से कम आबादी) तक विरोध की गूंज सुनाई दी।

गौरतलब है कि 2024 के चुनाव में ट्रंप ने इडाहो में 66 प्रतिशत वोट हासिल किए थे। आयोजकों ने बताया कि अमेरिका के सभी 50 राज्यों में 3,200 से अधिक विरोध-प्रदर्शन के कार्यक्रम तय किए गए हैं।

इस बार इन रैलियों में लगभग 90 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, जो पिछले साल अक्टूबर के 70 लाख के आंकड़े को पीछे छोड़ सकता है। चौंकाने वाली बात यह है कि रैलियों के लिए आए डिजिटल आमंत्रणों में से दो-तिहाई हिस्सा प्रमुख शहरों के बाहर से था, जिसमें व्योमिंग, मोंटाना और लुइसियाना जैसे राज्य शामिल हैं।

मिनेसोटा बना विरोध का केंद्र व स्प्रिंगस्टीन का साथ

सेंट पाल, मिनेसोटा में विरोध प्रदर्शन का मुख्य केंद्र रहा, जहां हजारों लोग 'उल्टे अमेरिकी झंडे' (संकट का प्रतीक) लेकर जमा हुए। राक स्टार ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने "स्ट्रीट्स आफ मिनियापोलिस" गाकर प्रदर्शनकारियों में जोश भर दिया। यह गीत फेडरल एजेंटों द्वारा की गई गोलीबारी में मारे गए रेनी गुड और एलेक्स प्रेटी को समर्पित था। लंदन, पेरिस और रोम जैसे यूरोपीय शहरों में भी हजारों लोग सड़कों पर उतरे। रोम में प्रदर्शनकारियों ने ईरान पर अमेरिकी हमलों और सरकार की नीतियों के खिलाफ नारे लगाए। पेरिस में रहने वाले अमेरिकियों ने ट्रंप के युद्धों को "अनैतिक और लापरवाह" करार दिया।

रैलियों को लेकर सत्ता पक्ष की तीखी प्रतिक्रिया

व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अबीगैल जैक्सन ने इन रैलियों को "वामपंथी फंडिंग नेटवर्क" की उपज बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने इसे "ट्रंप डिरेंजमेंट थेरेपी सेशन" का नाम दिया। वहीं, नेशनल रिपब्लिकन कांग्रेसनल कमेटी ने इन्हें "हेट अमेरिका रैलियां" कहते हुए प्रदर्शनकारियों की आलोचना की। दूसरी ओर, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह लड़ाई तानाशाही के खिलाफ है। वाशिंगटन में "क्राउन नीचे रखो, जोकर" जैसे नारों के साथ लोगों ने स्पष्ट संदेश दिया कि वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।

ईरान का दावा, एफ-16 फाइटिंग फाल्कन मार गिराया

अमेरिका ने माना, हमले में एफ-16 को हुआ नुकसान, इजरायली हमले में तेहरान में सैन्य उत्पादन केंद्र हुआ तबाह

- बहरीन ने समुद्री गतिविधियां सीमित कीं, कुवैत में सैन्य शिविर पर हमले में जवान घायल, लेबनान में दो की मौत
- नेतन्याहू ने कहा, हिजबुल्ला के खिलाफ दक्षिणी लेबनान में ज्यादा बड़े क्षेत्र को कब्जे में लिया जाएगा

सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले के बाद, अमेरिकी एयर फोर्स के एडब्ल्यूएसीएस विमान को तबाह हुआ दिखाया गया है। एएफपी

तेहरान और कई शहरों में हवाई हमले, कई घायल

एपी के अनुसार, ईरान ने कहा कि उसके दक्षिणी शहर शिराज पर चार बम हमले हुए हैं, जबकि फार्स प्रांत के अन्य हिस्सों में भी विस्फोट दर्ज किए गए। तेहरान में कतर के अल-अरबी टीवी के आवासीय परिसर के निकट हमले की भी निंदा की गई है। ईरानी रेड क्रेसेंट के अनुसार इस घटना में 10 लोग घायल हुए। तेहरान स्थित ईरान विश्वविद्यालय के बाद इस्फहान की एक यूनिवर्सिटी के आसपास भी विस्फोट दर्ज किए गए। ईरान ने चेतावनी दी कि यदि उसके शैक्षणिक केंद्र निशाने पर रहे तो वह भी अमेरिकी-इजरायली शैक्षणिक प्रतिष्ठानों को निशाना बना सकता है। बता दें कि कतर और यूएई में अमेरिका के जार्जटाउन, न्यूयार्क यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों के परिसर हैं।

तेहरान और इस्फहान में दो विश्वविद्यालयों पर हमले, ईरान ने हमले की दी चेतावनी

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी सैन्य संघर्ष की तीव्रता में एक महीने बाद भी कोई कमी नहीं आई है। रविवार को इजरायल ने दावा किया कि उसने तेहरान स्थित ईरान के महत्वपूर्ण सैन्य उत्पादन ढांचे पर रातभर कई सटीक हमले किए, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइलों के पुर्जे तैयार करने वाले संयंत्र, ड्रोन निर्माण इकाइयां, वायु रक्षा प्रणाली से जुड़े प्रतिष्ठान और मिसाइल भंडारण केंद्र शामिल थे।

इजरायली सेना के अनुसार निशाना बनाया गया संयंत्र ईरान में अपनी श्रेणी के केवल दो प्रमुख उत्पादन केंद्रों में से एक था, जहां से इजरायल की ओर दागी जाने वाली मिसाइलों के संचालन के लिए अहम पुर्जे तैयार होते थे। इधर, ईरान ने इन हमलों के जवाब में इजरायल और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अड्डों की दिशा में मिसाइलों और ड्रोन की नई लहर छोड़ी। ईरान ने अमेरिकी लड़ाकू विमान एफ-16 फाइटिंग फाल्कन और एमक्यू-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने आधिकारिक रूप से इतना स्वीकार किया कि एक एफ-16 विमान को क्षति पहुंची, हालांकि उसे सुरक्षित सैन्य अड्डे पर उतार लिया गया। इजरायल पर हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान के और बड़े हिस्से को कब्जे में लिया जाएगा।

ईरान ने भी इजरायल के औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर जवाबी हमले तेज किए हैं। दक्षिणी इजरायल के नेएत होवाव में एक कीटनाशक बनानेवाली कंपनी अदामा के संयंत्र पर हमला हुआ। कंपनी ने माना कि उसके मख्तेशम संयंत्र को मिसाइल या उसके मलबे से नुकसान पहुंचा है। यहां भयानक आग लगी और काला धुआं उठने लगा। आग बुझाने में 34 दमकल लगाई गईं। लोगों को इस संयंत्र के 800 मीटर के दायरे से दूर रहने को कहा गया है। इस इलाके में खतरनाक केमिकल बनानेवाली कई फैक्ट्रियां स्थित हैं। ईरान के मुख्य सैन्य कमांड के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फाघरी ने दावा किया कि दुबई में ड्रोन गोदाम को नष्ट कर दिया गया, जहां यूक्रेन के 21 ड्रोन रखे गए थे। हालांकि, यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने इसे ईरान का झूठ बताकर दावे को खारिज किया।

न्यूयार्क टाइम्स के अनुसार, खाड़ी देशों में भी ईरान के हमलों का क्रम जारी रहा। कुवैत सेना ने बताया कि एक सैन्य शिविर पर हुए मिसाइल हमले में कई सैनिक घायल हुए, जबकि वायु रक्षा इकाइयों ने अतिरिक्त ड्रोन और मिसाइलों को रोका। बहरीन ने तटीय सुरक्षा को देखते हुए शाम छह बजे से सुबह चार बजे तक मछली पकड़ने वाली नौकाओं, पर्यटक नौकाओं और अन्य समुद्री गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

आइएएनएस के अनुसार, इस बीच इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्ला से जुड़े इस्लामिक हेल्थ कमेटी की एंबुलेंस पर हमला किया, जिसमें एक चिकित्साकर्मी और एक मरीज की मौत हो गई। क्षेत्रीय स्वास्थ्य सूत्रों के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद लेबनान में अब तक दर्जनों चिकित्सा कर्मी मारे जा चुके हैं। सऊदी अरब ने दावा किया कि उसने अपने हवाई क्षेत्र की ओर बढ़ रहे 10 ड्रोन अवरोधित किए, जबकि स्थानीय मीडिया में प्रिंस सुल्तान एयर बेस के पास क्षतिग्रस्त अमेरिकी निगरानी विमान की उपग्रह तस्वीरें सामने आई हैं।

एएनआइ के अनुसार, यूएई ने ईरान की 16 बैलिस्टिक मिसाइल और 42 ड्रोन हमलों को विफल करने का दावा किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने समर्थन देने के लिए इराक के लोगों और धार्मिक नेतृत्व का आभार जताया है। ईरान के सरकारी मीडिया ने मोजतबा का ये बयान जारी किया।

ईरान युद्ध ने तेज की ट्रंप के उत्तराधिकारी की बहस, वेंस और रूबियो पर नजर

डोनाल्ड ट्रंप।

जेडी वेंस।

मार्को रुबियो। फाइल

- ईरान नीति पर जेडी वेंस संयमित, मार्को रुबियो आक्रामक लाइन के सबसे मुखर समर्थक बनकर उभरे
- युद्ध लंबा खिंचा तो वेंस को लाभ, त्वरित सफलता मिली तो रुबियो की दावेदारी मजबूत मानी जा रही

वाशिंगटन, रायटर: ईरान के साथ जारी सैन्य संघर्ष अब केवल पश्चिम एशिया की भू-राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अमेरिकी घरेलू राजनीति और 2028 के राष्ट्रपति चुनाव की संभावित तस्वीर भी इससे प्रभावित होने लगी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने जहां युद्ध को नियंत्रित कर राजनीतिक विरासत बचाने की चुनौती है, वहीं रिपब्लिकन खेमे में उनके संभावित उत्तराधिकारी को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। सत्ता के गलियारों में सबसे अधिक यही पूछा जा रहा है कि ट्रंप जेडी वेंस और मार्को रूबियो में से किसे आगे बढ़ाएंगे।

ट्रंप निजी बैठकों में अपने सहयोगियों और सलाहकारों से यही सवाल पूछ रहे हैं। चूंकि अमेरिकी संविधान के तहत वह 2028 में फिर चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए रिपब्लिकन पार्टी के भीतर उत्तराधिकार का प्रश्न पहले ही आकार लेने लगा है। ईरान युद्ध ने इस बहस को और तेज कर दिया है क्योंकि वेंस और रुबियो दोनों ही इस संकट प्रबंधन में अलग-अलग राजनीतिक शैली के साथ सामने आए हैं।

वेंस का संयमित और सतर्क रुख : उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान युद्ध पर अपेक्षाकृत संयमित और सतर्क रुख अपनाया है। पूर्व मरीन अधिकारी और इराक युद्ध के अनुभवी वेंस लंबे समय से अमेरिका की लंबी विदेशी सैन्य उलझनों के आलोचक रहे हैं। हालांकि उन्होंने ओवल आफिस में ट्रंप के साथ खड़े होकर यह भी कहा कि वह राष्ट्रपति की रणनीति के साथ हैं और ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलने देना चाहिए।

रूबियो का ट्रंप की तरह आक्रामक अंदाज : इसके विपरीत मार्को रुबियो ने ट्रंप की आक्रामक नीति का खुलकर समर्थन किया है। विदेश मंत्री होने के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में भी उनकी भूमिका बढ़ी है। व्हाइट हाउस के भीतर उन्हें संकट के दौरान स्थिर और निर्णायक चेहरा माना जा रहा है। विश्लेषकों का आकलन है कि यदि युद्ध अमेरिकी हितों के अनुकूल शीघ्र समाप्त होता है तो इसका लाभ रुबियो को मिल सकता है।

सर्वकालिक न्यूनतम स्तर पर ट्रंप की रेटिंग : ईरान युद्ध के चलते ट्रंप की लोकप्रियता पर दबाव बढ़ा है। रायटर/इप्सोस के चार दिन के सर्वेक्षण में ट्रंप की रेटिंग घटकर 36 प्रतिशत पर आ गई, जो उनके दूसरे कार्यकाल में अब तक का सबसे निचला स्तर है। इसका बड़ा कारण ईंधन कीमतों में तेजी और युद्ध को लेकर बढ़ती सार्वजनिक असहमति मानी जा रही है। रिपब्लिकन मतदाताओं में हालांकि अमेरिकी हमलों के समर्थन का स्तर अब भी मजबूत है- करीब 75 प्रतिशत रिपब्लिकन सैन्य कार्रवाई के पक्ष में हैं, जबकि डेमोक्रेट मतदाताओं में समर्थन बहुत कम है।

उधर, रिपब्लिकन रणनीतिकारों का मानना है कि यदि संघर्ष लंबा खिंचता है और अमेरिकी सैनिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी बढ़ती है तो वेंस यह कह सकेंगे कि उन्होंने पार्टी के युद्ध-विरोधी वर्ग की भावना पहले ही समझ ली थी। वहीं यदि सैन्य दबाव के जरिए ईरान झुकता है तो मार्को रुबियो डोनाल्ड ट्रंप के सबसे भरोसेमंद संकट प्रबंधक के रूप में उभरेंगे। उन्हें ट्रंप का उत्तराधिकारी और रिपब्लिकन नेता माना जा सकता है।

रूबियो की स्वीकार्यता तेजी से बढ़ी

हाल में आयोजित कंजर्वेटिव पालिटिकल एक्शन कांफ्रेंस (सीपैक) के स्ट्रा पोल में वेंस को स्पष्ट बढ़त मिली। 1600 से अधिक प्रतिभागियों में से 53 प्रतिशत ने उन्हें अगले रिपब्लिकन राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में पसंद किया, जबकि रुबियो 35 प्रतिशत समर्थन के साथ दूसरे स्थान पर रहे। पिछले वर्ष रुबियो को केवल तीन प्रतिशत समर्थन मिला था, जिससे साफ है कि उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता तेजी से बढ़ी है।

रूस ने अमेरिकी हवाई अड्डों की सेटेलाइट तस्वीरें ली थीं: जेलेंस्की

- कहा, रूस पर ईरान को खुफिया जानकारी मुहैया कराने का आरोप लगने के बावजूद प्रतिबंध हटाना पाखंडपूर्ण

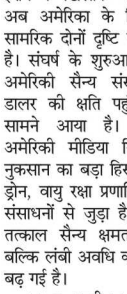

वलोदिमीर जेलेंस्की।

तस्वीरों का इस्तेमाल अमेरिका, ब्रिटेन व पश्चिम एशिया के ठिकानों पर हमले के लिए किया जा सकता है

कीव, एएनआइ : यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को दावा किया कि रूस ने ईरानी हमले से पहले खाड़ी क्षेत्र में स्थित अमेरिकी हवाई अड्डों की कई बार सेटेलाइट तस्वीरें ली थीं। इनमें सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयर बेस भी शामिल है। रूसी उपग्रहों ने ये तस्वीरें 24 और 25 मार्च को ली थीं, जिससे संकेत मिलता है कि वे आगे के हमले की तैयारी कर रहे हैं।

जेलेंस्की ने कहा कि रूस पर ईरान को खुफिया जानकारी मुहैया कराने का आरोप लगने के बावजूद प्रतिबंध हटाना पाखंडपूर्ण कदम है। इस जानकारी का इस्तेमाल अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिम एशिया के ठिकानों पर हमले के लिए किया जा सकता है। जेलेंस्की ने कहा, "आज सुबह मुझे बताया गया कि पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की तस्वीरें रूसी उपग्रहों द्वारा ईरान के हितों के लिए ली गई हैं। 24 मार्च को उन्होंने चागोस द्वीपसमूह में स्थित डिएगो गार्सिया में अमेरिकी-ब्रिटिश संयुक्त सैन्य ठिकाने की तस्वीरें लीं। कुवैत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और ग्रेटर बुरगान तेल क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के कुछ हिस्सों की तस्वीरें भी खींचीं। 25 मार्च को सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयर बेस की तस्वीरें लीं। साथ ही सऊदी अरब में शायबा तेल और गैस क्षेत्र, तुर्किये में इंसिरलिक एयर बेस और कतर में अल उदैद एयर बेस की भी तस्वीरें ली गईं।"

यूएसएस त्रिपोली 3500 सैनिकों के साथ पहुंचा

अमेरिका की तैयारी

- 5000 मरीन और 1000 पैराट्रूपर से लैस 82वीं एयरबोर्न डिविजन पहले से तैनात
- 10000 अतिरिक्त पैदल सैनिकों को अगले चरण में भेजा जाएगा
- स्ट्राइकर हेलीकाप्टर और बख्तरबंद वाहनों के साथ सामरिक युद्ध उपकरणों का जमावड़ा

यूएसएस त्रिपोली। फाइल

न्यूयार्क, आइएएनएस: ईरान के साथ जारी सैन्य तनाव के बीच अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य उपस्थिति और मजबूत कर दी है। अमेरिकी केंद्रीय कमान (सेंटकाम) ने पुष्टि की है कि 3,500 मरीन और नाविकों का एक विशेष टास्क फोर्स पश्चिम एशिया पहुंच चुका है। यह बल यूएसएस त्रिपोली (एलएचए-7) नामक अमेरिका श्रेणी के एंफीबियस पोत पर सवार होकर 27 मार्च को सेंटकाम के दायरेवाले क्षेत्र में पहुंचा। सेंटकाम ने बयान में कहा कि यह तैनाती क्षेत्रीय सुरक्षा अभियानों और सैन्य विकल्पों को विस्तार देने के उद्देश्य से की गई है।

ये युद्धपोत त्रिपोली एंफीबियस रेडी ग्रुप/31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट का प्रमुख हिस्सा है। इसमें लगभग 3,500 नाविक और मरीन तैनात हैं, जिनके साथ परिवहन विमान, स्ट्राइक फाइटर जेट, एंफीबियस हमला क्षमता और सामरिक युद्ध उपकरण भी मौजूद हैं। सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार ऐसी इकाइयों का उपयोग सामान्यतः त्वरित तैनाती, तटीय ठिकानों पर नियंत्रण, नागरिक निकासी और सीमित जमीनी अभियानों के लिए किया जाता है।

इजरायली पोर्टल वाइनेट न्यूज के अनुसार एंफीबियस फोर्स की विशेषता यह है कि वे समुद्र से मिसाइल प्रहार और तटीय इलाकों में सैनिक उतारने- दोनों प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं।

इसी बीच वाल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट में बताया है कि पेंटागन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कूटनीति से आगे बढ़कर अतिरिक्त सैन्य विकल्प देने के लिए 10,000 तक अतिरिक्त जमीनी सैनिक पश्चिम एशिया भेजने पर विचार कर रहा है। रक्षा विभाग के अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि इस बल में पैदल सेना, बख्तरबंद वाहन और सहायक युद्ध इकाइयां शामिल हो सकती हैं। यदि यह निर्णय लागू होता है तो यह बल पहले से क्षेत्र में मौजूद लगभग 5,000 मरीन तथा 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के हजारों पैराट्रूपर्स के साथ मिलकर अमेरिकी सैन्य क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। खलीज टाइम्स के अनुसार, सैनिकों की अंतिम तैनाती का स्थान सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन संभावना है कि इन्हें ऐसे ठिकानों पर रखा जाएगा जहां से ईरान और विशेष रूप से खार्ग द्वीप तक शीघ्र सैन्य पहुंच संभव हो। फारस की खाड़ी में स्थित खार्ग द्वीप ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात केंद्र है।

खार्ग द्वीप पर अमेरिकी कब्जे से ईरान को लगेगा भारी आर्थिक झटका

प्रथम पृष्ठ से आगे

खलीज टाइम्स के अनुसार, रणनीतिक चर्चा के केंद्र में खार्ग द्वीप है, जो फारस की खाड़ी में ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात केंद्र माना जाता है। यहां से ईरान के अधिकांश कच्चे तेल का समुद्री निर्यात होता है। अमेरिकी सैन्य योजनाकारों का मानना है कि यदि इस द्वीप पर कब्जा किया जाए या समुद्री नाकेबंदी की जाए तो तेहरान को भारी आर्थिक झटका लगेगा और वार्ता में अमेरिका की स्थिति मजबूत हो सकती है। इसी तरह लारक द्वीप भी प्रमुख विकल्पों में है, क्योंकि यह होर्मुज जलडमरूमध्य की निगरानी में अहम भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त अबू मूसा द्वीप और उसके आसपास के छोटे द्वीपों पर भी सैन्य विकल्प तैयार किए गए हैं। इस क्षेत्र पर यूएई भी अपना दावा करता है। अमेरिकी रणनीति के तहत यहां नियंत्रण स्थापित कर ईरान की समुद्री निगरानी क्षमता सीमित की जा सकती है। एक अन्य विकल्प क्षेत्र में ईरानी तेल ले जाने वाले जहाजों को रोकना और समुद्री निरीक्षण के नाम पर उनके आवागमन को नियंत्रित करना है।

ईरान युद्ध में अमेरिका को अब तक तीन अरब डालर का नुकसान: रिपोर्ट

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

- विमानों, ड्रोन और वायु रक्षा प्रणालियों को क्षति के बाद पेंटागन ने अतिरिक्त बजट का प्रस्ताव तैयार किया
- थाड, रीपर ड्रोन और टैंकर बेड़े पर असर; खाड़ी क्षेत्र में सैन्य संसाधनों की सुरक्षा नई चुनौती

ईरान के खिलाफ जारी सैन्य अभियान अब अमेरिका के लिए आर्थिक और सामरिक दोनों दृष्टि से भारी पड़ने लगा है। संघर्ष के शुरुआती तीन सप्ताह में अमेरिकी सैन्य संसाधनों को अरबों डालर की क्षति पहुंचने का आकलन सामने आया है। रक्षा सूत्रों और अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार नुकसान का बड़ा हिस्सा लड़ाकू विमानों, ड्रोन, वायु रक्षा प्रणालियों और नौसैनिक संसाधनों से जुड़ा है, जिससे न केवल तत्काल सैन्य क्षमता प्रभावित हुई है बल्कि लंबी अवधि की तैनाती लागत भी बढ़ गई है।

द वाल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार पेंटागन ने व्हाइट हाउस को युद्ध व्यय के लिए लगभग 200 अरब डालर तक के संभावित अतिरिक्त सैन्य प्रविधान का प्रारंभिक प्रस्ताव भेजा है। इसमें क्षेत्रीय तैनाती, अतिरिक्त सैनिक, समुद्री अभियानों, मिसाइल अवरोधन और क्षतिग्रस्त सैन्य उपकरणों की भरपाई की लागत शामिल है। युद्ध के दौरान अमेरिकी वायुसेना को सबसे अधिक झटका लड़ाकू और सहायक विमानों के मोर्चे पर लगा है। कुवैत क्षेत्र में फ्रेंडली फायर की एक घटना में तीन एफ-15ई स्ट्राइक ईगल विमानों के नष्ट होने की जानकारी सामने आई है। प्रत्येक विमान की अनुमानित कीमत लगभग 10 करोड़ डालर मानी जाती है। इसके अतिरिक्त एफ-35ए लाइटनिंग-2 को गंभीर तकनीकी क्षति के बाद आपात लैंडिंग करानी पड़ी। हवा में ईंधन भरने वाले अमेरिकी टैंकर बेड़े को भी नुकसान हुआ। एक केसी-135 स्ट्रैटोटैंकर इराक में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जबकि सऊदी अरब में तैनात पांच अन्य टैंकर विमानों को हमलों या छर्रों से क्षति पहुंची। केसी-135 अमेरिकी वायुसेना की लंबी दूरी अभियानों की रीढ़ माना जाता है, हालांकि अब धीरे-धीरे इसकी जगह केसी-46 पेगासस ले रहा है।

ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों के कारण अमेरिकी ड्रोन बेड़े पर भी असर पड़ा है। एक दर्जन से अधिक एमक्यू-9 रीपर ड्रोन या तो मार गिराए गए या परिचालन से बाहर हुए हैं। एमक्यू-9 रीपर अमेरिका का बहुउद्देश्यीय निगरानी और प्रहारक ड्रोन है, जिसका उपयोग खाड़ी क्षेत्र में लक्ष्य निगरानी, मिसाइल लोकेशन व हमलों के लिए किया जा रहा था। प्रत्येक ड्रोन की कीमत लगभग 3 से 3.5 करोड़ डालर मानी जाती है।

अराघची को आशंका, अमेरिका-इजरायल युद्ध का दायरा बढ़ाने की कर सकते हैं कोशिश

प्रथम पृष्ठ से आगे

एएनआइ के अनुसार, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने ग्रीस के विदेश मंत्री जार्जियोस गेरापेत्रितिस से फोन पर बातचीत में आशंका जताई कि अमेरिका और इजरायल युद्ध का दायरा बढ़ाने के लिए तीसरे देशों को इसमें खींच सकते हैं या "फाल्स फ्लैग आपरेशन" करा सकते हैं, यानी ऐसे हमले जिनका आरोप ईरान पर लगाया जाए।

ईरानी नेतृत्व ने घरेलू स्तर पर भी जनता से लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहने को कहा है। तेहरान, मशहद व इस्फहान सहित कई शहरों में सरकार समर्थक रैलियां आयोजित की गईं, जहां अमेरिका विरोधी नारे लगाए गए। गलीबाफ ने कहा कि युद्ध केवल मोर्चे पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय धैर्य और राजनीतिक इच्छाशक्ति की भी परीक्षा है।

ईरान की तैयारी महीनों नहीं, वर्षों की : एपी के अनुसार, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आइआरजीसी) के पास ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें और तटीय रक्षा तंत्र है, जिससे खार्ग या लारक जैसे द्वीप अत्यधिक विवादित युद्धक्षेत्र बन सकते हैं। पूर्व अमेरिकी रक्षा अधिकारियों का कहना है कि किसी द्वीप पर कब्जा करना कठिन नहीं, लेकिन वहां सैनिकों को सुरक्षित रखना बड़ी चुनौती होगी। इसलिए अमेरिकी रणनीति तेज, सीमित और उच्च गतिशीलता वाली कार्रवाई पर आधारित है। इस दौरान भविष्य में ईरान की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

अब्बास अराघची। फाइल

मिस्र, तुर्किये और सऊदी विदेश मंत्री इस्लामाबाद पहुंचे

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पश्चिम एशिया में तनाव के बीच सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किये के विदेश मंत्री चर्चा के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी नेताओं के साथ मिलकर ये नेता क्षेत्र में तनाव कम करने के तरीकों पर विचार करेंगे।

मिस्र के विदेश मंत्री बद्र आब्देलेत्ती और तुर्किये के विदेश मंत्री हकान फिदान शनिवार को ही इस्लामाबाद आ गए थे। जबकि उनके सऊदी समकक्ष प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद रविवार को इस्लामाबाद पहुंचे। ये सभी नेता पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री इशाक डार के बुलावे पर इस्लामाबाद आए हैं। इस बैठक के जरिये पाकिस्तान की कोशिश होगी कि वह शांति की कोशिश करता दिखाई दे। । डार ने शनिवार-रविवार रात ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से भी टेलीफोन पर बात की है और बैठक का उद्देश्य बताया है।

रोहित-रिकल्टन के तूफान में उड़ा केकेआर

मुंबई इंडियंस ने केकेआर को छह विकेट से दी शिकस्त, रोहित-रिकल्टन ने जड़े तेज अर्धशतक

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: रोहित शर्मा और रेयान रिकल्टन की तूफानी पारियों की बदौलत मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को छह विकेट से हराकर आइपीएल के 19वें सीजन में विजयी आगाज किया। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने टास जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 220 रन बनाए और मुंबई के सामने 221 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस ने घरेलू मैदान का पूरा फायदा उठाया और 19.1 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम की जीत में रोहित शर्मा और रेयान रिकल्टन ने अहम भूमिका निभाई। दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक जड़े और पहले विकेट के लिए 72 गेंदों पर 148 रन की शानदार साझेदारी की। रोहित ने महज 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और 38 गेंदों पर 78 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, रिकल्टन ने रोहित से एक गेंद ज्यादा लेते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया और 81 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में उतरे सूर्यकुमार यादव बड़ी पारी नहीं खेल सके और 16 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि, शुरुआती साझेदारी इतनी मजबूत रही कि मुंबई को लक्ष्य हासिल करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई।

रहाणे-ऐलन ने की अच्छी शुरुआत: इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स को कप्तान अजिंक्य रहाणे और फिन ऐलन ने तेज शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए तेजी से रन जोड़ते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। पावरप्ले में केकेआर ने तेजी से रन बनाए और मुंबई के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। हालांकि, पावरप्ले के अंतिम ओवर में टीम को पहला झटका लगा, जब फिन ऐलन छठे ओवर की दूसरी गेंद पर आउट हो गए। ऐलन ने 17 गेंदों में छह चौके और दो छक्कों की मदद से 37 रन बनाए। उन्होंने रहाणे के साथ पहले विकेट के लिए 32 गेंदों में 69 रन की साझेदारी की। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने इसके बाद जिम्मेदारी भरी पारी खेली। उन्होंने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 27 गेंदों में तीन चौके और चार छक्कों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया। रहाणे ने 40 गेंदों में 67 रन बनाकर टीम के स्कोर को मजबूत आधार दिया। दूसरी ओर कैमरन ग्रीन बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे और 10 गेंदों में 18 रन बनाकर शार्दुल की गेंद पर आउट हो गए।

अंगकृष और रिंकू ने की अर्धशतकीय साझेदारी: मध्य ओवरों में अंगकृष रघुवंशी और रिंकू सिंह ने पारी को संभालते हुए टीम को बड़े स्कोर की ओर बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 30 गेंदों में 60 रन की अहम साझेदारी की। अंगकृष ने शानदार अर्धशतक जड़ा और 29 गेंदों में 51 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में तेजी से रन जुटाते हुए मुंबई के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। दूसरी ओर, रिंकू सिंह ने भी अंत में 21 गेंदों में 33 रन बनाकर टीम को 220 के पार पहुंचाया।

महंगे साबित हुए हार्दिक: मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में महंगे साबित हुए। उन्होंने पारी का चौथा ओवर किया, जिसमें क्रीज पर अजिंक्य रहाणे और फिन ऐलन मौजूद थे। दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर में आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 26 रन बटोर लिए। यह आइपीएल में हार्दिक पांड्या के एक ओवर में संयुक्त रूप से दूसरे सबसे ज्यादा रन हैं। इससे पहले उन्होंने 2024 में वानखेड़े में सीएसके के विरुद्ध भी एक ओवर में 26 रन खर्च किए थे।

मुंबई के गेंदबाज रहे फ्लाप: मुंबई के गेंदबाज पूरे मैच में संघर्ष करते नजर आए। हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली टीम ने छह गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, लेकिन शार्दुल ठाकुर और हार्दिक पांड्या को छोड़कर किसी अन्य गेंदबाज को सफलता नहीं मिली। शार्दुल ठाकुर ने चार ओवर में 39 रन देकर तीन विकेट झटके और टीम को कुछ राहत दिलाई। वहीं, हार्दिक पांड्या ने तीन ओवर में 39 रन देकर एक विकेट हासिल किया। ट्रेंट बोल्ट, गजनफर, बुमराह, मयंक मारकंडे को कोई सफलता नहीं मिली।

शाट लगाते रोहित शर्मा • एपी

23 गेंदों में बनाया गया अर्धशतक रोहित शर्मा का आइपीएल में सबसे तेज अर्धशतक है। इससे पहले उनका सबसे तेज अर्धशतक 25 गेंदों में था, जो उन्होंने 2015 के फाइनल में ईडन गार्डेंस में चेन्नई के विरुद्ध बनाया था

300 वां टी-20 मैच खेलने उतरी मुंबई इंडियंस। क्रिकेट की दुनिया में यह उपलब्धि हासिल करने वाली मुंबई पहली फ्रैंचाइजी टीम बन गई

आइपीएल में सबसे ज्यादा 50 या उससे अधिक स्कोर

72	विराट कोहली
66	डेविड वार्नर
53	शिखर धवन
50	रोहित शर्मा
45	केएल राहुल

स्कोर बोर्ड

टास : मुंबई इंडियंस (गेंदबाजी) परिणाम : मुंबई छह विकेट से जीता

केकेआर : 220/4 (20 ओवर)

	रन	गेंद	4/6
राहणे का. हार्दिक बो. शार्दुल	67	40	3/5
ऐलन का. तिलक बो. शार्दुल	37	17	6/2
ग्रीन का. रदरफोर्ड बो. शार्दुल	18	10	1/1
अंगकृष का. तिलक बो. हार्दिक	51	29	6/2
रिंकू अविजित	33	21	4/0
रमनदीप अविजित	4	4	0/0
अतिरिक्त : 10 (लेबा : 2, वा : 7, नोबा : 1)			

विकेटपतन: 1-69 (ऐलन, 5.2), 2-109 (ग्रीन, 8.5), 3-145 (राहणे, 13.3), 4-205 (अंगकृष, 18.3)

गेंदबाजी: बोल्ट 4-0-38-0, हार्दिक 3-0-39-1, गजनफर 4-0-51-0, बुमराह 4-0-35-0, शार्दुल 4-0-39-3, मयंक 1-0-16-0

मुंबई इंडियंस : 224/4 (19.1 ओवर)

	रन	गेंद	4/6
रिकल्टन रन आउट	81	43	4/8
रोहित का. अनुकुल बो. वैभव	78	38	6/6
सूर्यकुमार का. रिंकू बो. कार्तिक	16	8	3/0
तिलक का. सब बो. सुनील	20	14	4/0
हार्दिक अविजित	18	11	3/0
नमन अविजित	5	2	1/0
अतिरिक्त : 6 (लेबा : 2, वा : 3, नोबा : 1)			

विकेटपतन: 1-148 (रोहित, 11.5), 2-179 (सूर्यकुमार, 14.2), 3-184 (रिकल्टन, 15.2), 4-215 (तिलक, 18.4)

गेंदबाजी: वैभव 4-0-52-1, मुजरबानी 3-0-34-0, वरुण 4-0-48-0, कार्तिक 4-0-43-1, सुनील 3-0-30-1, अनुकूल 1.1-0-15-0

आइपीएल में मुंबई के लिए सबसे बड़ी साझेदारियां

साझेदारी	जोड़ी	बनाम	साल	विकेट
167*	रोहित-गिब्स	केकेआर	2012	दूसरा
163*	स्मिथ-तेंदुलकर	राजस्थान	2012	पहला
148	रोहित-रिकल्टन	केकेआर	2026	पहला
143*	सूर्य-तिलक	हैदराबाद	2024	चौथा

सीजन के पहले मैच में रहाणे का प्रदर्शन

रन	बनाम	साल
56	आरसीबी	2025
67	मुंबई	2026

आइपीएल में किसी विदेशी खिलाड़ी द्वारा खेले गए सर्वाधिक मैच

मैच	खिलाड़ी
190	सुनील नारायण
189	कीरोन पोलार्ड
184	एबी डी विलियर्स

राजस्थान रायल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला आज

पुरानी टीम के सामने होंगे संजू-जडेजा

गुवाहाटी, प्रेट्र: पिछले एक दशक से अधिक राजस्थान रायल्स के कप्तान रहे संजू सैमसन अब आइपीएल में सोमवार को उसी टीम के विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में नजर आएंगे, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स टीम का हिस्सा रहे रवींद्र जडेजा अब राजस्थान रायल्स के लिए खेलने जा रहे हैं। पिछले दस साल से अधिक समय से सैमसन रायल्स टीम के कप्तान और स्टार बल्लेबाज रहे हैं। उनकी कप्तानी में रायल्स 2022 में फाइनल तक पहुंची थी। जिस तरह से चेन्नई की पहचान महेंद्र सिंह धौनी हैं, वैसे ही रायल्स की पहचान सैमसन बन गए थे लेकिन इस सत्र से पहले हुई अदला बदली में अब जडेजा रायल्स के लिए खेलेंगे और भारत की टी-20 विश्व कप जीत के नायक रहे सैमसन चेन्नई टीम का हिस्सा होंगे।

सैमसन ने टी-20 विश्व कप में वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के विरुद्ध आखिरी तीन मैचों में 50 से अधिक रन बनाकर भारत की खिताबी जीत में सूत्रधार की भूमिका निभाई। वह चेन्नई के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ के साथ पारी की शुरुआत करेंगे और टीम के कोर नेतृत्व का भी हिस्सा होंगे, हालांकि, धौनी फिटनेस कारणों से कम से कम दो सप्ताह नहीं खेल पाएंगे। धोनी टीम के साथ गुवाहाटी नहीं आए हैं और उनकी गैर मौजूदगी में सैमसन तथा गायकवाड़ पर नजरें रहेंगी।

प्रशांत वीर को मिल सकता है मौका: धौनी की गैर मौजूदगी में 20 साल के बाएं हाथ के स्पिनर आलराउंडर प्रशांत वीर को मौका मिल सकता है, जिन्होंने घरेलू टी-20 मैचों में प्रभावित किया। उनके अलावा 14.2 करोड़ रुपये में खरीदे गए कार्तिक शर्मा भी फोकस में होंगे जो घरेलू सर्किट में छक्के लगाने के अपने हुनर के लिए जाने जाते हैं। चेन्नई की बल्लेबाजी मजबूत लग रही है। डेवाल्ड ब्रेविस अब परिपक्व हो चले हैं, जबकि शिवम दुबे मध्यक्रम के भरोसेमंद बल्लेबाज बन गए हैं। युवा आयुष म्हात्रे भी तेजी से निखरते जा रहे हैं। गेंदबाजी में नूर अहमद, अकील हुसैन, मैट हेनरी और खलील अहमद जिम्मेदारी संभालेंगे।

रियान की कप्तानी में एक नए दौर की शुरुआत: राजस्थान रायल्स के लिए सैमसन का जाना एक युग का अंत है और रियान पराग की कप्तानी में एक नए दौर की शुरुआत है जो अपने घरेलू मैदान से कप्तानी की शुरुआत करेंगे। जडेजा के आने से टीम का अनुभव और संतुलन बढ़ा है। उनकी बल्लेबाजी का दारोमदार यशस्वी जायसवाल पर रहेगा।

उनके साथ गत आइपीएल में 35 गेंदों में शतक लगा चुके युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और फार्म में चल रहे शिमरोन हेटमायेर हैं। राजस्थान रायल्स के लिए बड़ी चिंता का सबब उसकी गेंदबाजी है। पिछले सत्र के बाद टीम में कई बदलाव हुए हैं लेकिन जोफ्रा आर्चर की अगुआई में तेज गेंदबाजों को निरंतरता पर काम करना होगा। स्पिन का जिम्मा जडेजा और रवि बिश्नोई संभालेंगे।

2022 में आइपीएल के खिताबी मुकाबले में संजू सैमसन की कप्तानी में पहुंची थी राजस्थान रायल्स की टीम, हालांकि, गुजरात टाइटंस के विरुद्ध उन्हें हार का सामना करना पड़ा था

संजू सैमसन • आइएएनएस

जडेजा • प्रेट्र

टीमें

राजस्थान रायल्स: रियान पराग (कप्तान), ध्रुव जुरैल, डोनोवन फरेरा, लुआन ड्रे प्रिटोरियस, रवि सिंह, अमन पेराला, शिमरोन हेटमायेर, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, रवींद्र जडेजा, सैम कुर्रन, एडम मिल्ने, बृजेश शर्मा, जोफ्रा आर्चर, कुलदीप सेन, क्वेना मफाका, नांद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई और संदीप शर्मा।

चेन्नई सुपर किंग्स: रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), संजू सैमसन, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, आयुष म्हात्रे, मैट हेनरी, अकील हुसैन, नूर अहमद, जैमी ओवर्टन, मैथ्यू शार्ट, खलील अहमद, जाक फोकेस, अंशुल कंबोज, नाथन एलिस, सरफराज खान, राहुल चाहर, कार्तिक शर्मा, उर्विल पटेल, अमन खान, रामाकृष्णा घोष, प्रशांत वीर, श्रेयस गोपाल, गुरजपनीत सिंह और मुकेश चौधरी।

खेल डायरी

जापान ग्रां पि में 19 वर्षीय एंटोनेली बने चैंपियन

सुजुका, एपी: मर्सिडीज के 19 वर्षीय ड्राइवर किमी एंटोनेली ने रविवार को जापानी ग्रां पि में मैकलारेन के आस्कर पियास्त्री को पछाड़ते हुए लगातार दूसरी फार्मूला-1 रेस जीत ली। इटली के एंटोनेली ने आस्ट्रेलिया के ड्राइवर पियास्त्री को 13.7 सेकेंड के अच्छे अंतर से पछाड़ दिया। वहीं फरारी के चार्ल्स लेक्लेर्क तीसरे और मर्सिडीज के जार्ज रसेल चौथे स्थान पर रहे। मैकलारेन के लैंडो नारिस पांचवें और फेरारी के लुईस हैमिल्टन छठे स्थान पर रहे। एंटोनेली ने अपने करियर की पहली फार्मूला-1 रेस दो सप्ताह पहले चीन में जीती थी और वह इतिहास के दूसरे सबसे कम उम्र के विजेता हैं। सबसे कम उम्र के विजेता का रिकार्ड मैक्स वेरस्टैपेन के नाम है। उन्होंने 2016 में 18 साल की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी। तीन रेस में एंटोनेली के 72 अंक हैं। वह अब सत्र की तालिका में शीर्ष पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। एंटोनेली ने कहा कि चैंपियनशिप के बारे में सोचना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन हम अच्छी स्थिति में हैं।

विश्व वुशू चैंपियनशिप में भारतीय चमके

तियानजिन, प्रेट्र: भारतीय खिलाड़ियों ने रविवार को 10वीं विश्व वुशू चैंपियनशिप में दो कांस्य पदक जीते, जबकि चार अन्य भी अलग-अलग वर्ग में फाइनल में पहुंच गए। भारत की अनु लड़कियों के वर्ग के सेमीफाइनल में चीन की झांग लिनिंग के सामने थीं, लेकिन वह कड़े मुकाबले में हार गईं। जिससे उन्हें कांस्य पदक मिला। वहीं लड़कों के सेमीफाइनल में गौतम मनकास अपने प्रतिद्वंद्वी से हार गए, जिससे उन्हें भी कांस्य पदक मिला। इसके अलावा उपेंद्रो थौगम मिस्र के अहमद मोहम्मद को हराकर, जबकि पामा हेइबा सिंह ने सेनेगल के अलीमौ सी को हराकर, युवराज ने फिलीपींस के जिविएल बंताली को हराकर फाइनल में पहुंचे। विक्टर ने मिस्र के सईद करीम मोहम्मद को हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई।

एरिना सबालेंका ने फाइनल में कोको गफ को रोमांचक मुकाबले में दी शिकस्त

लगातार दूसरी बार चैंपियन बनीं सबालेंका

ट्राफी के साथ सबालेंका • एपी

मियामी ओपन

मियामी, रायटर: एरिना सबालेंका ने शनिवार को मियामी ओपन के फाइनल में घरेलू खिलाड़ी कोको गफ को 6-2, 4-6, 6-3 से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब पर कब्जा जमाया और सनशाइन डबल पूरा किया। इसके अलावा एक खास क्लब में शामिल हो गईं। दुनिया की नंबर एक सबालेंका ने मैच में अपने पहले सर्विस पाइंट्स में 73 प्रतिशत जीते और जीत के रास्ते में केवल दो ब्रेक प्वाइंट का सामना किया। यह मुकाबला 2025 फ्रेंच ओपन फाइनल का रीमैच था, जिसे गफ ने जीता था।

सबालेंका इंडियन वेल्स और मियामी खिताब लगातार जीतने वाली सिर्फ पांचवीं महिला खिलाड़ी बनीं। कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में होने वाले इन टूर्नामेंट्स को साथ जीतने को सनशाइन डबल कहा जाता है। सबालेंका ने कहा कि मैं कोको से शुरुआत करना चाहती हूं। तुम एक फाइटर हो और मुझे बेहतर खिलाड़ी बनने के लिए मजबूर करती हो। मुझे हमारी प्रतिद्वंद्विता पसंद है। गफ के विरुद्ध उनका करियर रिकार्ड अब 7-6 हो गया है। सबालेंका 2019 और 2021 में एश्ले बार्टी के बाद मियामी में लगातार खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं। 2020 का टूर्नामेंट कोविड-19 के कारण रद हुआ था। बेलारूस की सबालेंका अब इगा स्वियातेक (2022), विक्टोरिया अजारेंका (2016), किम क्लाइस्टर्स (2005) और स्टेफी ग्राफ (1994, 1996) के साथ 'सनशाइन डबल' पूरा करने वाली खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गई हैं। सबालेंका ने इस साल अपना रिकार्ड 23-1 कर लिया। उन्हें एकमात्र हार आस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में रिबाकिना से मिली थी, जिन्हें उन्होंने बाद में इंडियन वेल्स फाइनल और मियामी सेमीफाइनल में हरा दिया।

सबालेंका इंडियन वेल्स और मियामी खिताब लगातार जीतने वाली पांचवीं महिला खिलाड़ी बनीं

पेशेवर मुक्केबाजी में उतर सकती हैं मैरी काम

मैरी काम

नई दिल्ली, प्रेट्र: ओलिंपिक कांस्य पदक विजेता और छह बार की विश्व चैंपियन भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी काम ने रविवार को कहा कि वह पेशेवर मुक्केबाजी में उतर सकती हैं। लंदन ओलिंपिक 2012 में कांस्य पदक जीतकर ओलिंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज बनी 43 वर्ष की मैरी काम ने कहा कि अमैच्योर सर्किट पर खेलने के लिए अब उनकी उम्र निकल चुकी है।

उन्होंने संडे आन साइकिल्स कार्यक्रम से इतर कहा कि छह विश्व चैंपियनशिप जीतना खास रहा। अब मैं उस उम्र में हूं कि देश के लिये अमैच्योर सर्किट पर नहीं खेल सकती। पेशेवर मुक्केबाजी एक नया मौका हो सकता है। उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में सोच रही हूं। मैं कड़ी मेहनत करके वापसी की कोशिश में हूं ताकि लोगों को बता सकूं कि मैं क्या कर सकती हूं।

ब्रेक से वापसी में मदद मिली : कोहली

आइपीएल डायरी

बेंगलुरु, प्रेट्र: आइपीएल के 2026 सत्र की शुरुआत नाबाद अर्धशतक से करने वाले महान बल्लेबाज विराट कोहली का मानना है कि नियमित अंतराल पर खेल से ब्रेक लेने से उन्हें थकान से बचने और मानसिक रूप से तरोताजा होकर वापसी करने में मदद मिली। सनराइजर्स हैदराबाद के विरुद्ध आइपीएल के इस सत्र के पहले मैच में गत चैंपियन रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु को छह विकेट से मिली जीत में कोहली ने 38 गेंद में पांच चौकों और पांच छक्कों की मदद से नाबाद 69 रन बनाए।

कोहली ने कहा कि वापिस यहां आकर अच्छा लग रहा है। आखिरी मैच मैंने पिछले साल आइपीएल फाइनल खेला था लेकिन हाल ही में वनडे सीरीज में जिस तरह से बल्लेबाजी की, उससे मुझे लय हासिल करने में मदद मिली। अंतरराष्ट्रीय टी-20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके कोहली ने कहा कि मैं वह शाट्स नहीं खेल रहा था जो आम तौर पर नहीं खेलता। मुझे पता है मैं लय में हूं।

विराट कोहली • फाइल फोटो

इस उम्र में कोहली की ऊर्जा और जोश बेजोड़ : अश्विन

बेंगलुरु: विराट कोहली की जमकर तारीफ करते हुए भारत के पूर्व आफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि टेस्ट और वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने के बावजूद अपनी बेजोड़ ऊर्जा और जोश के दम पर जो कहते हैं, वह करके दिखाते हैं। अश्विन ने जियोस्टार के शो पर कहा कि वह जो कहते हैं, करके दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि वह लोगों को दिखा रहे हैं कि कैसे खेला जाता है। इसे जोरदार ढंग से खेलो और वैसे ही खेलो, जैसे खेला जाना चाहिए।

फिट्जपैट्रिक ने वापसी कर जीता इंडियन ओपन गोल्फ खिताब

गुरुग्राम, प्रेट्र: हीरो इंडियन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट में रविवार को आखिरी दिन शीर्ष पर चल रहे गत चैंपियन यूजेनियो चकारा से चार शाट पीछे से शुरुआत करने वाले इंग्लैंड के एलेक्स फिट्जपैट्रिक ने 18वें ग्रीन पर पहुंचते-पहुंचते चार शाट की बढ़त बनाकर अपना पहला डीपी वर्ल्ड टूर खिताब जीत लिया। फिट्जपैट्रिक ने आखिरी होल में डबल बोगी की, लेकिन तब तक वह ट्राफी जीतने के लिए दो शाट की बढ़त बना चुके थे।

फिट्जपैट्रिक और स्पेन के चकारा के बीच लंबे समय से प्रतिद्वंद्विता चली आ रही है। एक साल पहले, जब चकारा ने हीरो इंडियन ओपन 2025 का खिताब जीता था, तब फिट्जपैट्रिक 17वें स्थान पर बराबरी पर थे। अब फिट्जपैट्रिक ने 3-अंडर 69 का स्कोर किया, जिससे हफ्ते का उनका कुल स्कोर 9-अंडर रहा, जिसमें उनके राउंड 70-68-72-69 के रहे। वहीं, चकारा के लिए आखिरी दिन किसी बुरे सपने जैसा रहा, जिसमें उन्होंने छह बोगी कीं, जिनमें से चार पिछले नौ होल में थीं और उन्होंने अपने आखिरी चार होल में से तीन में शाट गंवाए। 67-69-75 के राउंड के साथ उन्होंने आखिरी दिन 10-अंडर से शुरुआत करने के बाद 7-अंडर पर खेल खत्म किया। फिट्जपैट्रिक को हीरो मोटोकोर्प के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डा. पवन मुंजाल ने ट्राफी और लगभग 4.11 करोड़ रुपये (433,500 डालर) का चेक सौंपा। टूर्नामेंट में तीन खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के एमजे डफ्यू (73), फ्रांस के उगो कुसौद (69) और इंग्लैंड के एंडी सुलिवन (71) तीसरे स्थान पर बराबरी पर रहे। इन सभी का कुल स्कोर 5-अंडर 283 रहा। वहीं भारतीय गोल्फरों में ओम प्रकाश चौहान (81) और एस मनोज (76) T-43वें स्थान पर रहे, जबकि क्षितिज नावेद कौल (80) टी-82वें स्थान पर रहे। इस हफ्ते की शुरुआत करने वाले 30 भारतीयों में से सिर्फ तीन ही कट में जगह बना पाए थे।

फिट्जपैट्रिक ने 585 अंक भी हासिल किए और रेस टू दुबई रैंकिंग में छठे स्थान पर पहुंच गए। अगर फिट्जपैट्रिक इस रैंकिंग में शीर्ष-10 में जगह बना लेते हैं तो उन्हें पीजीए टूर कार्ड कार्ड मिल सकता है और वह अपने बड़े और अधिक मशहूर भाई मैथ्यू के साथ यूनाइटेड स्टेट्स में खेल सकते हैं। फिट्जपैट्रिक ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं। उम्मीद है कि मैं इसी तरह आगे बढ़ता रहूंगा।

ट्राफी के साथ हीरो इंडियन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट के विजेता फिट्जपैट्रिक • आयोजक

फिट्जपैट्रिक ने गत चैंपियन चकारा से चार शाट पीछे रहते हुए की अखिरी दिन की शुरुआत

विश्व कप से पहले वार्मअप मैच में एक भी गोल नहीं कर सकीं मैक्सिको और पुर्तगाल की टीम

रोनाल्डो के बिना पुर्तगाल को खेलना पड़ा ड्रा

फुटबाल डायरी

मेक्सिको सिटी, एपी: मेक्सिको और पुर्तगाल के बीच फीफा फुटबाल विश्व कप 2026 से पहले शनिवार देर रात वार्मअप मैच ड्रा रहा। स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बिना मैदान पर उतरी पुर्तगाल की टीम इस मुकाबले में एक भी गोल नहीं कर सकी, जबकि मैक्सिको की टीम भी गोल पोस्ट को भेदने में नाकाम रही। विश्व कप के लिए दो साल के नवीनीकरण के बाद खोले गए मैक्सिको सिटी के एज्टेका स्टेडियम में यह मुकाबला हुआ।

मैच में गोल करने का सबसे अच्छा मौका पुर्तगाल के गोंकालो रामोस को 26वें मिनट में मिला। हालांकि, उनका शाट गोलपोस्ट से टकरा गया। मुकाबले में मेक्सिको की टीम में चोट के कारण 12 खिलाड़ी शामिल नहीं थे। वहीं पुर्तगाल की टीम रोनाल्डो के अलावा राफेल लेओ भी गैरमौजूद थे। मैक्सिको का ऐतिहासिक एज्टेका स्टेडियम इस विश्व कप में पांच मैचों की मेजबानी करेगा। मेक्सिको 11 जून को मेक्सिको सिटी में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध विश्व कप का उद्घाटन मैच खेलेगा। वहीं पुर्तगाल 17 जून को जमैका या कांगो के विरुद्ध अभियान की शुरुआत करेगा।

वार्मअप मैच में गेंद के लिए संघर्ष करते मैक्सिको और पुर्तगाल के खिलाड़ी • रायटर

बड़े सपने देख रहे अमेरिका को बेल्जियम से मिली शिकस्त

अटलांटा, एपी: विश्व कप के बड़े सपने देख रही अमेरिका टीम को बेल्जियम ने बुरी तरह से हरा दिया। इस मैत्री मुकाबले में अमेरिका को बेल्जियम के विरुद्ध 5-2 से हार का सामना करना पड़ा। अमेरिकी टीम ने लगातार पांच गोल खाए।1959 में इंग्लैंड के हाथों 8-1 से हारने के बाद अमेरिका टीम की अपने घरेलू मैदान पर यह तीन गोल के अंतर से पहली हारी थी, जिसमें मैच का पहला गोल अमेरिका टीम ने ही किया था। अमेरिका टीम लगातार पांच मैचों में अजेय रहने के बाद इस मैच में उतरी थी। उनकी ओर से एंटोनी राबिंसन और पैट्रिक एग्येमांग ने 87वें मिनट में गोल किया। इन दो गोलों के बीच में बेल्जियम के डोडी लुकेबाकियो ने दो गोल, जेनो डेबास्ट, अमादौ ओनाना और चार्ल्स डी केटेलेरे ने एक-एक गोल किया।

क्रिकेट और स्पोर्ट्स की अन्य खबरों के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

साक्षात्कार

अंग्रेजी की कवयित्री का हिंदी में आना, फिर कविता से कथा साहित्य में प्रवेश और कहानी, उपन्यास, संस्मरण आदि विधाओं में स्थापित हो जाना... इस अविराम यात्रा में ममता कालिया के जीवन और लेखन में विविध रंग हैं, स्त्रीविमर्श का मूल भाव है तो जीवन का निज दृष्टिकोण भी। उन्हें 'जीते जी इलाहाबाद' पर साहित्य अकादमी पुरस्कार-2025 (हिंदी भाषा) देने की घोषणा हुई है। 31 मार्च को उन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। ममता कालिया से विवेक भटनागर की बातचीत के अंश...

रोज एक कहानी लिख सकती हूं

चित्र : संजीव कुमार

• **साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए बधाई। कैसा अनुभव कर रही हैं?**

धन्यवाद। 15-20 वर्ष पहले जो होना चाहिए था, वह अब हुआ। यह अटका हुआ फैसला था। न्याय मिलने में देर हुई, पर आश्वस्त हुई कि अब साहित्य अकादमी को अक्ल आ गई।

• **पिछले साल दिसंबर में पुरस्कार घोषित होना था, पहले ही लोग फेसबुक पर लिखने लगे कि ममता कालिया को पुरस्कार घोषित होगा। फिर पुरस्कार स्थगित हो गए और अब घोषित हुए। क्या तब आपको भी पता था कि पुरस्कार आपको मिल रहा है?**

किसी ने फोन पर बताया था कि आपका नाम है, लेकिन वह खटाई में पड़ गया है। साहित्य अकादमी से मेरा कोई व्यक्तिगत संपर्क नहीं है। जब मुझे पता चला कि पुरस्कार स्थगित हो गया तो मैंने कहा कि भाड़ में जाए, क्योंकि अवार्ड रोक देने से अकादमी की प्रतिष्ठा संदिग्ध होने लगी थी। सरकार ने अब नाम घोषित करके प्रायश्चित किया है।

• **जब आप उस दौर के इलाहाबाद (अब प्रयागराज) की स्मृतियों को अक्षरों में संजो रही थीं, तब क्या आपको लगा कि 'जीते जी इलाहाबाद' पर यह पुरस्कार मिल सकता है?**

पुरस्कार को दृष्टि में रखकर मैं कभी नहीं लिखती। 'तद्भव' के संपादक अखिलेश ने मुझसे इलाहाबाद पर लिखने को कहा था। वैसे भी इलाहाबाद मेरे अस्तित्व का एक हिस्सा है। मैं बनी ही इलाहाबाद में ही हूं। मैं तो बंबई (अब मुंबई) से गई थी और अंग्रेजी की लेखिका थी। अंग्रेजी में दो कविता संग्रह आ चुके थे। पढ़ाती भी अंग्रेजी ही थी। सोचा भी नहीं था कि हिंदी में लिखूंगी।

• **फिर हिंदी में कैसे लिखने लगीं?**

– इलाहाबाद में मेरी ट्रेनिंग हुई। पिता हिंदी-अंग्रेजी, दोनों भाषाओं के विद्वान थे। चाचा भारत भूषण अग्रवाल हिंदी कवि थे। वह जोर से कविता लिखते थे। हमारे यहां यह नखरा नहीं है कि लेखक एकांत में लिखेगा। हम जीवन के बीच बैठकर लिखते हैं। मैंने पहला उपन्यास 'प्रेम कहानी' भी शोर के बीच लिखा। बच्चा छोटा था, कनस्तर को कलछी से पीट-पीटकर गाता था। मेरा अंग्रेजी कविता संग्रह 'ट्रिब्यूट टु पापा' चर्चित था, इसलिए मुझे अपनी कविताओं पर बड़ा घमंड था। यह घमंड इलाहाबाद जाकर टूटा, जब अमरकांत जी ने वह संग्रह फेंक दिया और कहा- यह कोई कविता है।

• **...फिर कविता से कहानी लिखने लगीं?**

1965 में विवाह से पहले रवींद्र कालिया एक सेमिनार में मिले, कहने लगे- कविता-वविता ही लिखती हैं, कहानी लिखना नहीं आता? मैं अ-कविता लिखती थी। रवींद्र कहते थे कि यह कोई कविता है, यह तो जुमलेबाजी है। रवि ने मुझे इतना क्षुब्ध किया कि मैंने सोचा कि इस आदमी को कहानी लिखकर दिखाती हूं। इलाहाबाद में कहानी, नई कहानियां, कथा, मनोरमा कहानी छापती थीं। मैं कहानी की ओर पूरी तरह मुड़ गई।

• **आपने बताया कि आप आरंभ में अ-कविता लिखती थीं और रवींद्र कालिया अ-कहानी के प्रवर्तकों में प्रमुख थे। आप लोगों के साथ यह 'अ' का क्या चक्कर था?**

हम सब 'अ' थे। (हंसती हैं, फिर गंभीर होकर) 1965 तक भारतीय कविता पर अमेरिकी प्रभाव आ गया था। दो अमेरिकी 'क्रुद्ध कवि' एलेन गिंसबर्ग और पीटर आर्लोव्स्की भारत में लंबे समय तक रहे। एलन गिंसबर्ग की 'हाउल' कविता प्रसिद्ध थी। ये दोनों नियम तोड़ने के पक्षधर थे। उनके प्रभाव में अ-कविता लिखी गई। उस समय यह आकर्षक लगता था कि हम क्रुद्ध और विरुद्ध लोगों में शामिल हैं। इसी प्रकार अ-कहानी भी विरोध से उपजी। उस समय 'नई कहानी' के नाम पर मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर ने कहानी पर कब्जा किया हुआ था। उनके बनाए कहानी के ढांचे से रवि को चिढ़ थी। उसके प्रतिरोध में अ-कहानी लिखी गईं।

• **आपने 200 से अधिक कहानियां लिखी हैं और आज भी लिख रही हैं। क्या एक व्यक्ति के जीवन में इतनी घटनाएं घटित होती हैं कि कहानी लिखी जा सकें?**

सब कुछ स्वयं पर घटित नहीं होता। दूसरों पर घटित भी अपना अनुभव लगने लगता है। कालेज में पढ़ाते हुए लड़कियों की पीड़ा देखी, जो मेरे अंदर एकत्रित है। इतनी बदलियां थीं कि जिसको छेड़ो, वही बरस पड़ती थी। मेरे पास तो इतने अनुभव शेष हैं कि मैं रोज एक कहानी लिख सकती हूं।

• **आरंभ में किस कहानी से प्रेरित हुईं...?**

जब पुणे में 12वीं में पढ़ती थी, तब मैंने मन्नू भंडारी की पहली कहानी 'मैं हार गई' पढ़ी थी। मेरे पापा ने राष्ट्रवाणी पत्रिका लाकर दी थी और कहा था- यह कहानी पढ़ो, ऐसे लिखते हैं। तब कहानी की बड़ी मांग थी। अजमेर की 'लहर' पत्रिका के संपादक प्रकाश जैन पोस्टकार्ड लिखते थे- ममता इस बार कहानी दो। जैसे ही उनकी चिट्ठी आती, मैं लिखने बैठ जाती थी। मुझे तो संपादकों ने ही बनाया है। 'ज्ञानोदय' के संपादक शरद देवड़ा, 'सुप्रभात' के संपादक रामानंद दोषी थे। इंदौर में जब मैं कविताएं लिखती थी तो जागरण और नई दुनिया में हर रविवार को मेरी कविताएं छपती थीं। रचना न भेजो तो नई दुनिया के संपादक राहुल बारपुते की चिट्ठी आ जाती कि लिखना बंद कर दिया क्या? जागरण के दीवाली विशेषांक के लिए मुझे दस रुपये पारिश्रमिक मिला था।

• **संस्मरण लेखन की क्या चुनौतियां हैं?**

– सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो हम लिख रहे हैं, उस समय के लोग यह बताने के लिए जीवित हैं कि आपने सही लिखा या गलत। एक सुरक्षित रास्ता यह निकलता है कि यह मेरे हिस्से का यथार्थ है। 'जीते जी इलाहाबाद' में मैंने एक प्रसंग इलाहाबाद के जज मार्कंडेय काटजू और कथाकार भैरव प्रसाद गुप्त का लिखा है। किसी ने लिखा कि ममता जी ने गलत लिख दिया है। संस्मरण को कोई भी चुनौती दे सकता है, लेकिन वह मेरे हिस्से का सच है। नई पीढ़ी में संस्मरण में स्वयं को प्रोजेक्ट करने का चलन हो गया है। मन्नू जी पर मैंने 'उनका घर एक रौशनदान था' संस्मरण लिखा था। उनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी, जो गरिमा के विरुद्ध हो। हां, राजेंद्र यादव बड़े शरारती थे। उनके जीवन में आकर मैत्रेयी पुष्पा ने मन्नू जी का दांपत्य चौपट कर दिया। उसने राजेंद्र यादव के कहने पर देहवादी रचनाएं लिखीं। राजेंद्र यादव ने रवींद्र की 'गालिब छुटी शराब' को दस किस्तों में छापा था। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा- ममता, तुम यह लिखो कि शराब पीकर उसने तुम्हारी क्या छीछालेदर की। खूब गहरा करके लिखो। मैंने कहा- क्षमा करें, मुझे रवि से कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने घर की जिम्मेदारियां पूरी कीं, तब जो मर्जी किया।

• **अब क्या लिख रही हैं?**

एक कहानी संग्रह आएगा। इलाहाबाद के रानी मंडी मुहल्ले पर संस्मरण लिखा है। पापा पर उपन्यास लिखूंगी।

पूरा साक्षात्कार पढ़ने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।

vivekbhatnagar@nda.jagran.com

ममता कालिया : प्रमुख कृतियां व सम्मान

उपन्यास : बेघर, नरक दर नरक, दुक्खम सुक्खम, सपनों की होम डिलिवरी, कल्चर-वल्चर।

कहानी संग्रह : छुटकारा, उसका यौवन, मुखौटा, जांच अभी जारी है, सीट नंबर छह, निर्मोही, प्रतिदिन, थोड़ा-सा प्रगतिशील, एक अदद औरत, पच्चीस साल की लड़की।

कविता संग्रह : ए ट्रिब्यूट टु पापा, पोएम्स 79, खांटी घरेलू औरत, कितने प्रश्न करूं, पचास कविताएं।

संस्मरण : कल परसों के बरसों, सफर में हमसफर, कितने शहरों में कितनी बार, अंदाजे-ए-बयां उर्फ रवि कथा, शेष कथा।

प्रमुख सम्मान : साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, साहित्य भूषण, यशपाल स्मृति सम्मान, महादेवी स्मृति पुरस्कार, कमलेश्वर स्मृति सम्मान आदि।

गजल

नज्म सुभाष
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

तन्हाई में डूब गया

सूरज पश्चिम की खाई में डूब गया।
मैं भी अपनी तन्हाई में डूब गया।

संबंधों के ताने-बाने उधड़े थे,
सारा जीवन तुरपाई में डूब गया।

उसकी शादी पर मुझको कुछ होश नहीं,
मेरा किस्सा शहनाई में डूब गया।

इसका, उसका, सबका कर्ज चुकाना था,
एक अकेला भरपाई में डूब गया।

बेशक ऊंचे लोग फलक तक जा पहुंचे,
मैं छोटा था परछाई में डूब गया।

हम दोनों के बीच उदासी चीख रही,
अपना रिश्ता रुसवाई में डूब गया।

रोज बुढापा कोसा करता मुझको नज्म,
'ये तो भैया तरुणाई में डूब गया'।

nazmsubhash97@gmail.com

संगीतायन

डा. राजेश कुमार व्यास
जयपुर, राजस्थान

गायन में जीवन-अनुभूतियों की छटाएं

पटियाला घराने के प्रसिद्ध और सिद्ध गायक बड़े गुलाम अली खान ने ठुमरी की अपनी पृथक शैली विकसित की। [illegible] उन्होंने फिल्म में गाया और इतिहास बनाया। मखमली आवाज वाले इस स्वरसाधक की जन्मजयंती (2 अप्रैल) पर विशेष...

बड़े गुलाम अली खान को सुनना जीवनानुभूतियों की भिन्न-भिन्न छटाओं को सहज छलकते हुए देखना है। उनका लचीलापन, अप्रत्याशित स्वर-संयोजन और तानों की अविश्वसनीय गति विलक्षण है। राग मालकौंस, दरबारी कान्हड़ा, [illegible] खमाज, बागेश्री, शुद्ध कल्याण, हंसध्वनि में समय को जैसे वह गायन में रूपांतरित करते हैं। स्वरों का माधुर्य ऐसा कि उसमें खिलती धूप, बादलों के घिरने-बरसने, फूलों के खिलने, सांझ घिरने आदि को देख-सुन सकते हैं। आलाप को घंटों तक खींचने की बजाय वह संक्षिप्त प्रस्तुति में उसे सजाते-संवारते थे। ठुमरी के कालजयी प्रभाव को समझना हो तो उनके स्वर में 'का करूं सजनी आए न बालम' सुनें, लगेगा विछोह की व्यथा जैसे अंतर्मन की अनुभूति बन गई है। उनकी गाई 'प्रेम जोगन बन के' [illegible] 'नैना मोरे तरस गए' जैसी ठुमरियां भी संवेदनाओं का [illegible] अंदाज है, जिसमें सभी रंग घुले हैं। उन्होंने सबरंग नाम से खयाल और ठुमरी की विरल रचनाएं दीं।

बड़े गुलाम अली फिल्मों में गाने के विरुद्ध थे, पर 'मुगल-ए-आजम' में उन्होंने गाया। कहते हैं, फिल्म के एक दृश्य में तानसेन को गाते हुए दिखाना था। नौशाद की इच्छा थी बड़े गुलाम अली खान साहब उसे गाएं। के. आसिफ के आग्रह को उन्होंने ठुकरा दिया, पर जब आसिफ नहीं माने तो उन्होंने 25 हजार रुपये मांग लिए, ताकि उन्हें गाना न पड़े। उस समय लता मंगेशकर को भी गाने के पांच सौ रुपये मिलते थे। पर आसिफ ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने इस फिल्म में राग सोहनी और रागेश्वरी में 'प्रेम जोगन...' गाया, जो मिसाल बन गया। कभी उन्होंने 'हरिओम तत्सत' भजन गाते हुए तपस्वी की भांति स्वर-साधना की। वह सुरमंडल संग अपनी स्वयं की आविष्कृत पटियाला-कसूर शैली में राग जयजयवंती, जौनपुरी, हमीर गाकर मंत्रमुग्ध कर देते।

लाहौर के निकट कसूर में जन्मे बड़े गुलाम अली के पिता अली बख्श कश्मीर के महाराजा के दरबारी गायक थे। चाचा काले खां से संगीत सीखा। कोलकाता संगीत सम्मेलन में उन्होंने जब सार्वजनिक प्रस्तुति दी तो उनकी आवाज ने श्रोताओं के मन जीत लिए। उन्होंने बाद में खयाल गायन में ध्रुपद, ग्वालियर घराने और जयपुर घराने की शैलियों का रस घोलकर अपनी स्वयं की गायन-शैली विकसित की।

वह संगीत को ओढ़ते-बिछाते थे। एक बार उनका आपरेशन हुआ। चिकित्सकों ने पूर्ण विश्राम करने को कहा, पर जल्द ही उन्होंने तीन सप्तकों तक फैली एक तान गा दी। टोका गया तो बोले, देखना था कि मेरी आवाज पर तो आपरेशन का असर नहीं पड़ा। महाराष्ट्र सरकार के एक कार्यक्रम में मंच पर रोशनी केवल उन पर थी। दर्शक दीर्घा की बत्तियां बुझी हुई थीं। उन्होंने कहा, 'नहीं गा सकता। मुझे अपने श्रोताओं के दर्शन होंगे तभी गाऊंगा?' उनका गायन सदा मन को मोहता था। इसीलिए वह उस्तादों के उस्ताद हैं। जग गायक!

drrajeshkumarvyas@gmail.com

लघुकथा

राजिंदर सिंह राजन
पठानकोट, पंजाब

बीस डालर

मिंदा पत्नी और दो बच्चों के साथ कनाडा में दस साल से रहता था। वह केवल दो बार ही अपने गांव आकर माता-पिता से मिल सका था। माता-पिता उसकी प्रतीक्षा करते। उनका एक-एक दिन वर्षों की तरह बीतता। मिंदा के पिता बलदेव खेतों में मेहनत करके समय काट लेते, पर मां जीतो के लिए हर पल बहुत भारी था। जीतो अक्सर मिंदा को फोन करती और एक ही बात कहतीं- 'पुत्तर, अब आ भी जा, दिल बहुत उदास हो गया है। बच्चों को देखने को तरस गई हूं।' मिंदा हर बार दिलासा देता- 'मां, अगले साल छुट्टियों में जरूर आएंगे।'

साल बीतते रहे और 'अगला साल' नहीं आया। एक दिन सुबह जीतो घबराकर उठ बैठी। रात उसने अजीब सपना देखा था, उसके दोनों पोते दौड़ते हुए आकर उससे लिपट गए थे। सपने की वह मीठी झलक उसके दिल में और भी तड़प जगा गई। सुबह होते ही उसने मिंदा का नंबर मिलाया। उसकी आवाज भावुक थी, 'पुत्तर मिंदा, इस महीने आकर बच्चों को जरूर मिला जा, मैं तुझे 20 डालर दूंगी।'

उसे यह नहीं पता था कि 20 डालर की क्या कीमत होती है। उसके मन में तो बस यही खयाल था कि 20 डालर बहुत बड़ी रकम होगी। मां की यह बात सुनकर मिंदा खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसके हंसने में मां की मासूमियत के लिए प्रेम था। वह हंसकर बोला- 'मां, तुम अपने डालर अपने पास ही रखो, मैं इस महीने बच्चों को लेकर जरूर आऊंगा। यह मेरा वादा है।' मिंदा ने कनाडा से टिकट कटवाई और गांव आ पहुंचा। जैसे ही वह घर के आंगन में आया, मां दौड़ती हुई आई और मिंदा को गले लगा लिया। दोनों पोते दादा-दादी से लिपट गए। बहू ने भी आगे बढ़कर माथा टेका और आशीर्वाद लिया।

मां की आंखों में खुशी के आंसू बह रहे थे। पिता की आंखें भी नम थीं, पर चेहरे पर मुस्कान खिली हुई थी। आंगन में खेलते पोते देखकर जीतो की खुशी का ठिकाना नहीं था। जैसे घर में फिर से बीस साल की जवानी उतर आई हो। उस दिन जीतो को एहसास हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत डालर नहीं होती, सबसे बड़ी दौलत तो अपने बच्चों की एक झलक होती है।

rajan_pathankot@yahoo.com

पुस्तक परिचय

साहित्यकारों की चिट्ठियां

चिट्ठियों का दौर समाप्त हो गया है, लेकिन पुराने दौर की चिट्ठियां उस कालखंड को समझने का बोध देती हैं। दिविक रमेश 112 साहित्यिक व्यक्तित्वों द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह लेकर आए हैं- चिट्ठियों के आईने में। इसमें बच्चन, अंचल, शमशेर, धर्मवीर भारती, जगदीश गुप्त, विद्यानिवास मिश्र, विष्णु प्रभाकर आदि बहुत से प्रसिद्ध कवि-लेखकों की चिट्ठियां हैं। **प्रकाशक :** अद्विक पब्लिकेशन, **मूल्य :** 400 रुपये

पुस्तक मिली

राहतों के नाम पर बेचैनियां (गजल संग्रह)
लेखिका : अनामिका सिंह
प्रकाशक : श्वेतवर्णा प्रकाशन

आज का राशिफल – 30 मार्च 2026 सोमवार

पं. के.ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति
चैत्र मास शुक्ल पक्ष द्वादशी [illegible]

आज का राहुकाल : प्रात: 07 बजकर 30 मिनट से 09 बजे तक।

आज का दिशाशूल : पूर्व

आज का पर्व एवं त्योहार : सोम प्रदोष, मदन द्वादशी

कल 31 मार्च, 2026 का पंचांग

2	1 गु. / 12 सू. श. / 11 बु. रा. मं.	10
3 गु.		9
4	6	8
	5 के. चं. / 7	

कल का दिशाशूल : उत्तर

कल का पर्व एवं त्योहार : श्री महावीर जयंती (जैन)

विक्रम संवत 2083 शके 1948 उत्तरायण, उत्तरगोल, वसंत ऋतु चैत्र मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी 06 घंटे 57 मिनट तक तत्पश्चात चतुर्दशी, पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र 15 घंटे 21 मिनट तक तत्पश्चात उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र, गंड योग 15 घंटे 42 मिनट तक तत्पश्चात वृद्धि योग, सिंह में चंद्रमा 21 घंटे 33 मिनट तक तत्पश्चात कन्या में।

मेष : शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी।

वृष : पारिवारिक समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। सम्मान में वृद्धि होगी। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

मिथुन : किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी।

कर्क : आर्थिक योजना फलीभूत होगी। मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में प्रयास फलीभूत होगा।

सिंह : बहुप्रतीक्षित कार्य संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, फिर भी अज्ञात भय रहेगा।

कन्या : यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व उत्साहवर्धक होगी। पारिवारिक व्यस्तता बढ़ेगी।

तुला : शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। शासनसत्ता का सहयोग रहेगा।

वृश्चिक : कार्यों में रुचि लेंगे। अधिकारी का सहयोग मिलेगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी।

धनु : धार्मिक या सांस्कृतिक मामलों में सफलता मिलेगी। पिता या धर्म गुरु का सहयोग मिलेगा।

मकर : जीवनसाथी पक्ष से तनाव मिल सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है।

कुंभ : जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगा।

मीन : पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी।

वर्ग पहेली-3290

1			2	■	3	■	4		5
	■	■		■	6			■	
7	8			■		■		■	
■		■	9	10	■	11			
12			■	13	14		■	■	■
■	■	■	15			■	16	17	
18		19		■	20	21	■		■
	■		■	22	■	23			24
	■	25			■		■	■	
26			■		■	27			

© Bird Features & Writing Agency

बाएं से दाएं :
1 संकट को दूर करना, युक्ति (4)। 4 मांगनेवाला, प्रार्थी (3)। 6 अपने से भिन्न (3)। 7 'गीत-गोविंद' पुस्तक के रचयिता (4)। 9 सूर्य, दिनकर (2)। 11 जबर्दस्त, उद्दंड (4)। 12 जान से मारना (3)। 13 सामंत, सरदार, छोटा राजा (3)। 15 बावला, विक्षिप्त (3)। 16 अनाज, अन्न (3)। 18 बातचीत (4)। 20 मृत्यु के देवता (2)। 23 प्रलय, आफत (4)। 25 चटाई, बिस्तर (3)। 26 इमली को अरबी में कहते हैं... (3)। 27 दर्द से भरा (4)।

ऊपर से नीचे :
1 कमल, पंकज (3)। 2 श्रीकृष्ण का एक नाम (4)। 3 त्रेता और कलियुग के बीच का युग (3)। 4 खानाबदोश, घुमंतू (4)। 5 ऋणी (4)। 8 भरोसा (3)। 10 अरुचि, विरक्ति (3)। 11 यथार्थ, सच्चाई (2)। 14 कुंडल (3)। 15 अपराध कसूर (2)। 17 प्रियतम, प्रेम पात्र (3)। 18 संतोष की बात (4)। 19 तरबतर (4)। 21 मनोरथ (4)। 22 नियत अवधि तक का (3)। 24 जल्दी-जल्दी, चटपट (3)।

कल का हल

ज[1]	■	दु[2]	का	न[3]	■	का[4]	ला	ती	त
ब	■	र्भा	■	सी[5]	र	त	■	■	■
र	■	व[6]	ज	ह	■	र[7]	स[8]	म	य[9]
न[10]	हा[11]	ना	■	त[12]	न	■	फे	■	कृ
■	ति	■	डा[13]	■	■	खि[14]	द	म[15]	त
ह[16]	म	जो[17]	ली	■	■	न्न	■	वा	■
द	■	खि	■	ह[18]	द[19]	■	ग[20]	द	र[21]
स[22]	ला	म	त[23]	■	ह[24]	ज	म	■	ण
■	■	■	र[25]	जि	श	■	गी	■	क्षे
ड[26]	ग	म	ग	■	त[27]	प	न	■	त्र

सुडोकू-3290

1		5	9			4		2
	2		6					
9				4	1	7		8
	1		7				9	
8					6	2		4
	4		5				8	
6					2	1		5
		8	1		5		4	
5				6				7

कल का हल

7	4	6	1	2	5	8	3	9
2	5	3	4	8	9	1	7	6
1	9	8	7	6	3	5	2	4
9	3	4	2	5	7	6	1	8
8	7	1	6	3	4	2	9	5
6	2	5	8	9	1	3	4	7
5	1	9	3	7	8	4	6	2
4	8	2	9	1	6	7	5	3
3	6	7	5	4	2	9	8	1

राष्ट्रीय फलक

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर रणथंभौर के पास नहीं होगी वाहनों से वन्य जीवों की भिड़ंत

- एक्सप्रेसवे पर रणथंभौर के पास खोला गया देश का सबसे बड़ा वन्यजीव ओवरपास
- वाहनों के तेज शोर से जानवरों को नहीं होगी परेशानी, यातायात भी होगा सुगम

जागरण संवाददाता, जयपुर

अब रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाले दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मनुष्यों और वन्यजीवों में कोई टकराव नहीं होगा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर जोन से गुजर रहे इस एक्सप्रेसवे के करीब 12 किलोमीटर लंबे हिस्से पर वन्यजीवों की सुरक्षित आवाजाही के लिए विशेष अंडरपास और ओवरपास बनाए गए हैं। एक्सप्रेसवे पर वन्यजीवों और यातायात के सह-अस्तित्व को न्यूनतम व्यवधान के साथ सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंजीनियरिंग उपाय किए गए हैं। ओवरपास को प्राकृतिक रूप देने के लिए आसपास बड़ी संख्या में पेड़-पौधे लगाने के साथ ही उसे झाड़ियों से ढंका गया है।

बता दें कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बने देश के सबसे बड़े 11.5 किमी लंबे ओवरपास को रविवार को खोल दिया गया है। इस ओवरपास का अहम हिस्सा 3.7 किमी लंबा है, जो 500-500 मीटर के पांच ओवरपास और 1.2 किमी अंडरपास से लैस है। इसका उद्देश्य जानवरों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करना है। यह देश का सबसे लंबा वन्यजीव अंडरपास है। वहीं ओवरपास 11.5 किलोमीटर लंबा है।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर खोला गया देश का सबसे बड़ा वन्यजीव ओवरपास। इंटरनेट मीडिया

एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ चार मीटर ऊंची दीवार बनाने के साथ ही दो मीटर ऊंचे ध्वनि अवरोधक लगाए गए हैं, जिससे वाहनों के शोर से जानवरों को परेशानी नहीं हो। पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील 12 किलोमीटर लंबे क्षेत्र से गुजरने वाली 765 केवी के बिजली के तारों को भी स्थानांतरित किया गया है। इस कोरिडोर को प्राकृतिक जंगल के अनुरूप डिजाइन किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के परियोजना प्रबंधक संदीप ने अग्रवाल ने बताया कि वन्य जीवों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए प्रत्येक किलोमीटर पर उच्च गुणवत्तायुक्त कैमरे लगाए गए हैं। लार्सन एंड टुब्रो द्वारा लगभग 900 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह ओवरपास रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और कूनो राष्ट्रीय उद्यान के कुछ हिस्सों सहित प्रमुख वन्यजीव आवासों को जोड़ता है, जिससे एक निरंतर पारिस्थितिक गलियारा बनता है। एक्सप्रेसवे पर लगभग 1,500 एलईडी लाइटें लगाई गई हैं ताकि वाहन चालक ढके हुए रास्तों से गुजर सकें और वन्य जीवों की आवाजाही को प्रभावित किए बिना सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

झारखंड में रामनवमी जुलूस के दौरान तीन की हत्या

जागरण संवाददाता, हजारीबाग: झारखंड के हजारीबाग में रामनवमी जुलूस के दौरान अलग-अलग कार्यक्रमों में तलवारबाजी के दौरान तीन युवकों की हत्या कर दी गई। वहीं, जुलूस व शस्त्र प्रदर्शन के दौरान 658 से अधिक लोग घायल हो गए। ज्ञात हो, हजारीबाग में रामनवमी के साथ ही दशमी व एकादशी को भी जुलूस निकाला जाता है।

सूत्रों के मुताबिक, शनिवार देर रात अस्त्र-शस्त्र प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति को चाकू मार दी गई। उपचार के लिए रांची ले जाने के दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने हत्या का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। इसी प्रकार जुलूस के दौरान एक अन्य व्यक्ति को किसी ने चाकू मार दिया। गंभीर हालात में उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। इसके अलावा जुलूस में शामिल एक व्यक्ति को सिर पर हाकी स्टिक से हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया।

विमान यात्री ने इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश की, कहा-अनजाने में हुई गलती

जागरण संवाददाता, वाराणसी

बेंगलुरु से वाराणसी आ रहे इंडिगो के विमान (उड़ान संख्या 6 ई185) में शनिवार रात उस समय अफरातफरी का माहौल हो गया, जब मऊ निवासी यात्री मो. अदनान ने लैंडिंग से थोड़ा पहले इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश की। उस समय विमान रनवे को टच करने वाला था। विमान में चालक दल के सदस्यों सहित 156 लोग सवार थे। यात्री की इस अप्रत्याशित हरकत से सभी दहशत में आ गए। पायलट ने इसकी सूचना एटीएस को दी और विमान को हवा में लेते गए। करीब आधे घंटे बाद रात 10.35 बजे विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई। विमान के उतरते ही सीआइएसएफ ने आरोपित यात्री को पुलिस को सौंप दिया। पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया।

आरोपित मोहम्मद अदनान। स्रोत-इंटरनेट मीडिया

पुलिस की पूछताछ में अदनान ने बताया कि वह सीट संख्या 13-एफ पर बैठा था। विमान लैंड होने से पहले वह नींद में था। वाशरूम जाने के लिए खड़ा हुआ तो उसका हाथ इमरजेंसी गेट में लगे हैंडल पर लग गया। इससे डोर में लगा कवर खुल गया। इसकी सूचना उसने खुद चालक दल के सदस्यों को दीं। उन्होंने कवर को बंद किया और पायलट को सूचना दी। विमान के उतरते ही उसे फूलपुर पुलिस को सौंप दिया गया। आइबी, एटीएस, क्राइम ब्रांच आदि की टीम ने भी उससे पूछताछ की। विमानन सुरक्षा नियम के अनुसार यदि कोई यात्री जाने या अनजाने में विमान से किसी तरह की छेड़छाड़ करता है तो उसे दोषी माना जाता है। अदनान के खिलाफ बीएनएस की धारा 125 के तहत केस दर्ज कर नोटिस जारी करते हुए छोड़ दिया गया।

राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

आजकल

सोमवार, 30 मार्च, 2026

14

www.jagran.com

बड़ी रियासतों के विलय के साथ हुआ राजस्थान राज्य का गठन

1949 में आज ही जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर जैसी बड़ी रियासतों के विलय के बाद 'वृहद राजस्थान' का गठन हुआ था। सरदार वल्लभभाई पटेल के प्रयासों से राजस्थान की एकता और पहचान को नया आयाम मिला, और भारत के सबसे बड़े राज्य का उदय हुआ।

पहली बार हुआ एनेस्थीसिया का सफल प्रयोग

1842 में आज ही अमेरिकी चिकित्सक डा. क्राफर्ड लान्ग ने पहली बार सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया के रूप में ईथर का उपयोग किया था। एक मरीज की गर्दन से ट्यूमर निकालने के लिए उसे ईथर सुंघाया, जिससे मरीज को दर्द का अहसास नहीं हुआ। इसने आधुनिक सर्जरी की नींव रखी।

देविका रानी की पारखी नजरों ने पहचाना था दिलीप कुमार का हुनर

देविका रानी का जन्म 1908 में आज ही विशाखापत्तनम में हुआ था। लंदन में अभिनय और संगीत की शिक्षा ली। 1933 में फिल्म कर्मा से हिंदी सिनेमा में शुरुआत की, जिसमें उनके अभिनय ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उन्होंने पति हिमांशु राय के साथ मिलकर बांबे टाकीज स्टूडियो की स्थापना की। देविका रानी ने ही दिलीप कुमार जैसे महान अभिनेता को खोजा और उन्हें ब्रेक दिया। 1969 में उन्हें पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देविका न केवल एक बेहतरीन अभिनेत्री थीं, बल्कि एक साहसी फिल्म निर्माता भी थीं जिन्होंने रूढ़ियों को तोड़ा।

बालू मक्खी का हो जाएगा समूल नाश, थमेगा कालाजार

अध्ययन ▶ बालू मक्खियों पर 100% प्रभावी मिले कीटनाशक अल्फासाइपरमेथ्रिन को इंसेक्टिसाइड बोर्ड ने किया पंजीकृत

अध्ययन को 'अमेरिकन जर्नल आफ ट्रापिकल मेडिसिन एंड हाइजीन' ने दी प्रकाशन की स्वीकृति

गजाधर द्विवेदी • जागरण

बालूमक्खी। फाइल

यह अध्ययन कालाजार उन्मूलन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। अल्फासाइपरमेथ्रिन की 100 प्रतिशत प्रभावशीलता हमें एक भरोसेमंद हथियार देती है। अब आवश्यकता है कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से लागू किया जाए, ताकि कालाजार जैसी घातक बीमारी को जड़ से समाप्त किया जा सके।

– डा. हरिशंकर जोशी, निदेशक आरएमआरसी

गोरखपुर : जानलेवा बुखार कालाजार के खिलाफ लड़ाई में विज्ञानियों को बड़ी सफलता मिली है। कालाजार फैलाने वाली मादा बालू मक्खी को खत्म करने के लिए एक प्रभावी कीटनाशक की पहचान कर ली गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) की शाखा क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र (आरएमआरसी) के अध्ययन में अल्फासाइपरमेथ्रिन नामक कीटनाशक को बालू मक्खियों के खिलाफ सौ प्रतिशत प्रभावी पाया गया है। इस महत्वपूर्ण खोज से देश में कालाजार उन्मूलन अभियान को नई गति मिलने की उम्मीद है। भारत सरकार के इंसेक्टिसाइड बोर्ड ने भी इस अध्ययन पर अपनी मुहर लगा दी है, इसे पंजीकृत कर लिया है। अब पूरे देश में बालू मक्खी के खिलाफ इस कीटनाशक का प्रयोग किया जा सकेगा।

आरएमआरसी के विज्ञानियों द्वारा जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 के बीच किए गए इस अध्ययन में पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया और कुशीनगर जिलों को शामिल किया गया। इन मक्खियों पर चार अलग-अलग कीटनाशकों- डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईमेथ्रिन (डीडीटी), मैलाथियान, अल्फासाइपरमेथ्रिन और डेल्टामेथ्रिन का परीक्षण किया गया। प्रत्येक कीटनाशक का प्रयोग 450-450 मक्खियों पर किया गया। अध्ययन में पाया गया कि डीडीटी की प्रभावशीलता मात्र 49 प्रतिशत रही, जबकि मैलाथियान और डेल्टामेथ्रिन 98 प्रतिशत तक सफल पाए गए। वहीं अल्फासाइपरमेथ्रिन 100 प्रतिशत कारगर मिला। 'अमेरिकन जर्नल आफ ट्रापिकल मेडिसिन एंड हाइजीन' ने इस अध्ययन के प्रकाशन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। साथ ही भारत सरकार के इंसेक्टिसाइड बोर्ड ने भी अल्फासाइपरमेथ्रिन को आधिकारिक रूप से पंजीकृत करते हुए आरएमआरसी के निष्कर्षों पर अपनी मुहर लगा दी है। इस अध्ययन को निदेशक डा. हरिशंकर जोशी के निर्देशन में डा. गौरवराज द्विवेदी, डा. बृजनंदन मिश्रा और डा. नलिनी मिश्रा की टीम ने किया है।

कालाजार के बारे में जानें : कालाजार लीशमैनिया परजीवियों के कारण होता है, जिसकी संवाहक बालू मक्खी है। दो सप्ताह से अधिक समय तक रुक-रुक कर बुखार आना, तेजी से वजन घटना, कमजोरी, एनीमिया (खून की कमी) और प्लीहा व लिवर का बढ़ना शामिल है। इस बीमारी में त्वचा का रंग भूरा पड़ सकता है, इसी वजह से इसे कालाजार कहते हैं।

यहां पाई जाती है बालू मक्खी : बालू मक्खी गर्म व आर्द्र क्षेत्रों, अंधेरी व नम जगहों जैसे मिट्टी की दीवारों की दरारों, चूहों के बिलों, मलबे और गीली मिट्टी के पास पनपती हैं। ये मक्खियां अक्सर सूर्यास्त के बाद सक्रिय होती हैं।

लियारी के लोगों ने धुरंधर-2 की कमाई में मांगा हिस्सा

पाकिस्तान स्थित लियारी। फाइल

जेएनएन, नई दिल्ली : फिल्म 'धुरंधरः द रिवेंज' की बाक्स आफिस पर कामयाबी ने पाकिस्तान के कराची स्थित लियारी के लोगों की आंखें भी चौंधिया दी हैं। हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर कर्ज की भीख मांगने वाली पाकिस्तान सरकार से निराश लियारी की आवाम ने भारतीय फिल्म निर्माताओं से फिल्म से हो रही आय का 80 प्रतिशत तक हिस्सा देने की मांग की है।

पाकिस्तान में प्रतिबंधित फिल्म पर लियारी के लोगों ने हक जताते हुए कहा कि यहां की सड़कें बनाने और मेनहोल के ढक्कन लगवाने के लिए पांच सौ करोड़ रुपये दें। एक अन्य ने 80 प्रतिशत तक हिस्सा देने की राय दी। यह मांग तब उठी जब फिल्म ने वैश्विक स्तर पर डेढ़ हजार करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म में लियारी के इर्द-गिर्द कहानी बुनी गई है। हालांकि फिल्म पाकिस्तान में शूट नहीं हुई है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में स्थानीय लोगों ने तर्क दिया कि चूंकि फिल्म ने लियारी के नाम व पृष्ठभूमि का उपयोग किया, इसलिए लियारी को वित्तीय लाभ मिले। एक निवासी ने कहा कि यहां की सड़कें तभी सुधर सकती हैं, अगर भारत भुगतान करे"। एक युवा को यह भी दावा करते दिखाया गया कि फिल्म की शूटिंग लियारी में हुई है और रणवीर सिंह व अन्य कलाकार रात में आकर शूटिंग करके सुबह भारत लौट जाते थे।

इधर-उधर

पुरानी फोटो से ढूंढ निकाला 33 साल पहले बिछड़ा भाई

बचपन में ही अनाथ हो गए थे ली लिन और ली शिन। इंटरनेट मीडिया

बीजिंग, एजेंसी : चीन में एक महिला ने सिर्फ बचपन की एक फोटो के सहारे छोटे भाई को 33 साल बाद ढूंढ निकाला। 44 साल की ली लिन हुबेई की रहने वाली हैं। वह बचपन में भाई ली शिन से बिछड़ गई थीं। मां की मौत और पिता के घर छोड़कर चले जाने के बाद दोनों अनाथ हो गए थे। एक दिन वे भूखे-प्यासे सड़कों पर भटक रहे थे। तभी एक बुजुर्ग महिला आई और उसने ली शिन को ब्रेड दिलाने की बात कही। ली ने भाई को जाने दिया, लेकिन वह फिर कभी वापस नहीं आया।

मोटापा और खानपान की गड़बड़ी से किडनी स्टोन का खतरा

- कैल्शियम और विटामिन डी का ज्यादा मात्रा में सेवन करने से किडनी में पथरी होने का खतरा
- किडनी में पथरी होने पर सबसे पहले पीठ या पेट के निचले हिस्से में होता रहता है तेज दर्द

प्रतीकात्मक

नई दिल्ली, नेशनल डेस्क : दुनियाभर में क्रानिक बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। जीवनशैली और खान-पान की गड़बड़ी ने जिन अंगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, किडनी उनमें से एक हैं। किडनी से संबंधित बीमारियां पहले उम्र बढ़ने के साथ होने वाली समस्याएं मानी जाती थीं। हालांकि अब कम उम्र वाले, यहां तक कि बच्चों में भी किडनी की बीमारी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में किडनी स्टोन (पथरी) गंभीर बीमारी बनकर उभरी है।

अगर किसी बीमारी के कारण किडनी सही से काम न करे तो इससे विषैले तत्व जमा होने लगते हैं। जिन लोगों का खानपान ठीक नहीं रहता है उनमें किडनी स्टोन होने का खतरा अधिक देखा जाता है। किडनी में किसी समस्या के कारण जब कैल्शियम आक्सलेट, यूरिक एसिड जैसे पदार्थ ठीक तरीक से फिल्टर होकर शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो इनके छोटे-छोटे क्रिस्टल मिलकर पथरी बनाने लगते हैं। पथरी के कारण अत्यधिक दर्द और असहजता हो सकती है। कम पानी पीने से पेशाब गाढ़ा हो जाता है, जिससे पथरी होने का खतरा बढ़ जाता है। मोटापा और खानपान की गड़बड़ी जैसे जंक फूड, नमक चीनी ज्यादा खाना, फाइबर की कमी से भी पथरी होने का खतरा बढ़ता है। कई रिपोर्ट्स में अलर्ट किया जाता रहा है कि भारतीयों में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसका हड्डियों पर सीधा असर होता है। इन पोषक तत्वों की कमी के लिए लोग लंबे समय तक या बिना डाक्टरी सलाह के लिए सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं। कई बार ये गलती आप पर भारी पड़ सकती है।

कैल्शियम और विटामिन डी का ज्यादा मात्रा से खतरा : स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि कैल्शियम और विटामिन डी का ज्यादा मात्रा में और लंबे समय तक एक साथ सेवन करने से किडनी में पथरी होने का खतरा बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विटामिन डी का स्तर ज्यादा होने पर शरीर में कैल्शियम का अवशोषण भी ज्यादा होने लगता है, जिससे पेशाब में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है। इसे हाइपरकैल्सीयूरिया कहते हैं और इसी वजह से ऐसे लोगों में पथरी बनने का खतरा भी बढ़ जाता है। वैसे तो संतुलित मात्रा में और डाक्टर की सलाह पर सप्लीमेंट्स लेना सुरक्षित है, पर इसकी ज्यादा डोज या लंबे समय तक सप्लीमेंट्स लेने से जोखिम बढ़ सकता है।

पीठ या पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द : विटामिन-डी की अधिकता मात्रा आंतों में कैल्शियम का अवशोषण बढ़ा देती है, जिससे पेशाब के जरिए कैल्शियम का उत्सर्जन बढ़ जाता है। कैल्शियम सप्लीमेंट को भोजन के साथ लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इन्हें अकेले लेने से भी पथरी बनने का खतरा ज्यादा देखा जाता रहा है। किडनी में पथरी होने पर सबसे पहले पीठ या पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द होता रहता है। इसके साथ पेशाब करते समय जलन, खून आने, बार-बार पेशाब आने की दिक्कत देखी जाती है। इससे बुखार और उल्टी की दिक्कत भी होती है।

क्या है निदान : इसके निदान के लिए अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट के माध्यम से जांच की जाती है। उपचार के लिए दर्द निवारक और पथरी को घोलने/बाहर निकालने वाली दवाएं ली जाती हैं। आवश्यक होने पर सर्जरी की जाती है। इसमें आधुनिक लेजर सर्जरी से जल्दी छुट्टी मिल जाती है।

भूरी वसा को कैलोरी बर्निंग मशीन में बदलने वाले प्रोटीन की पहचान

अनुसंधान

विज्ञानियों ने ब्राउन फैट (भूरी वसा) में छिपी एक ऐसी प्रणाली को उजागर किया है, जो आपके शरीर को कैलोरी जलाने वाली भट्टी में बदलने में मदद कर सकती है। शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि कैसे एक महत्वपूर्ण प्रोटीन एसएलआइटी3 इस ऊष्मा उत्पन्न करने वाले ऊतक में रक्त वाहिकाओं और तंत्रिका संबंधों के विकास को बढ़ावा देकर भूरे वसा को सक्रिय करने में मदद करता है।

अध्ययन में मोटापे से निपटने के एक संभावित नए तरीके पर प्रकाश डाला गया है, जो भूख कम करने के बजाय शरीर द्वारा खर्च की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा बढ़ाने पर केंद्रित है।

शोधकर्ताओं ने कहा कि शरीर की अधिकांश वसा व्हाइट (सफेद वसा) होती है, जो अतिरिक्त ऊर्जा को संग्रहित करती है और जब इसका स्तर बहुत अधिक हो जाता है तो मोटापे का कारण बन सकती है। मनुष्यों और अन्य स्तनधारियों में भूरी वसा की मात्रा कम होती है, जो विशेष प्रकार का ऊतक है, जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है और मेटाबोलिज्म और वजन नियंत्रण से जुड़ा है। ठंड के संपर्क में आने पर भूरी वसा ग्लूकोज और लिपिड का उपयोग करके ऊष्मा उत्पन्न करती है। एनवाईयू कालेज आफ डेंटिस्ट्री में सहायक प्रोफेसर फरनाज शम्सी ने कहा, थर्मोजेनेसिस के दौरान वह सारी रासायनिक ऊर्जा शरीर में सफेद वसा के रूप में जमा होने के बजाय गर्मी के रूप में नष्ट हो जाती है। (एएनआइ)

स्क्रीन शाट

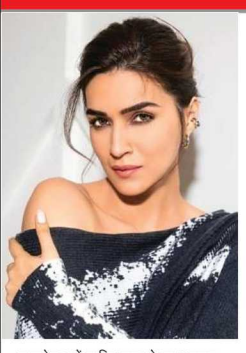

काकटेल 2 में शाहिद कपूर के साथ नजर आएंगी कृति। फाइल

दिल की सुननी चाहिए: कृति सैनन

फिल्म हीरोपंती से अभिनय में कदम रखने वाली अभिनेत्री कृति सैनन की बीसवीं फिल्म काकटेल 2 होगी। उनका मानना है कि फिल्म मिमी उनकी जिंदगी का टर्निंग प्वाइंट रही, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। एक कार्यक्रम के दौरान कृति ने कहा कि मेरा मानना है मैंने हर प्रोजेक्ट से साथ आगे बढ़ने की कोशिश की है। सफलता या विफलता आपके हाथ में नहीं होती है। आप उस सफर से कितना सीखते हो या कितना बदलते हो, यह आपके हाथ में होता है। तो बहुत सारी फिल्मों ने निश्चित रूप से मुझे थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ाया है, लेकिन एक फिल्म का नाम लेना हो तो वह मिमी होगी। मेरा वह जिंदगी का टर्निंग प्वाइंट थी। मुझे लगता है कि उसने मुझे बतौर कलाकार पंख दिए। उसने मुझे यकीन दिलाया कि मैं यह कर सकती हूं मुझे बस खुद पर थोड़ा और भरोसा करने की जरूरत है। मुझे जोखिम उठाने की जरूरत है। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि था तुम मां की भूमिका कर रही हो। तुम्हें टाइपकास्ट कर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि आपको अपने दिल की सुननी चाहिए वह कभी झूठ नहीं बोलता। आगे काकटेल 2 को लेकर उन्होंने कहा कि यह साल 2012 में आई फिल्म काकटेल की रीमेक या सीक्वल नहीं है। यह फ्रेंचाइज है। यहां पर भी दो लड़की और एक लड़के की कहानी है लेकिन यह दुनिया और कहानी एकदम अलग है।

अब मैं जिंदगी को बिल्कुल अलग नजरिए से देखती हूं: कियारा आडवाणी

पिछले साल मां बनी अभिनेत्री कियारा आडवाणी अब फिल्म टाक्टिस : फेयरी टेल फार ग्रोन अप्स में नजर आएंगी। इसमें कन्नड़ अभिनेता यश डबल रोल में होंगे। मातृत्व अवकाश के बाद रिलीज होने वाली यह कियारा की पहली फिल्म है। उनका कहना है कि मां बनने के बाद उनकी जिंदगी और सोच पूरी तरह बदल गई है। कियारा ने कहा कि शादी के बाद उनके और सिद्धार्थ (अभिनेता और पति सिद्धार्थ मल्होत्रा) के रिश्ते में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। उन्होंने बताया कि शादी से उन्हें अपने घर को संभालने और साथ रहकर जीवन संवारने की स्वतंत्रता मिली, लेकिन उनका रिश्ता पहले जैसा ही बना हुआ है। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि शादी से पहले भी सिद्धार्थ और मैं मजाक-मस्ती करते थे और साथ में घूमना पसंद करते थे, और ये सब आज भी वैसा ही है। हम साथ में फिल्में देखते हैं और सिनेमा प्रेमी और कलाकार होने के नाते उन पर चर्चा करना हमें बहुत अच्छा लगता है। वहीं मातृत्व के बारे में बात करते हुए कियारा ने कहा कि मैं अब और ज्यादा शेरनी बन गई हूं। अब मैं जिंदगी को बिल्कुल अलग नजरिए से देखती हूं। ऐसा लगता है कि कुछ भी मायने नहीं रखता और साथ ही सब कुछ मायने रखता है। वो छोटी सी बच्ची अब भी मेरे अंदर है। कियारा और सिद्धार्थ साल 2023 में शादी के बंधन में बंधे थे।

फिल्म टाक्सिक में अभिनेता यश के साथ नजर आएंगी कियारा। फाइल

एक सीन में भी अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं: संजय कपूर

कई कलाकार किरदार की लंबाई से ज्यादा भूमिका पर जोर देते हैं। अभिनेता संजय कपूर भी उनमें से एक हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा में प्रेम फिल्म से कदम रखा था। उसके बाद उन्होने बतौर लीड कई फिल्में की, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिली। ओटीटी पर मिल रहे मौकों में वह भले ही केंद्रीय भूमिका में न हो, लेकिन उन्हें सशक्त भूमिकाएं मिल रही हैं। हालिया रिलीज वेब सीरीज संकल्प में वह राजनेता की भूमिका में नजर आए हैं। संजय कहते हैं मुझे लगता है कि अभी भी मैं जो कर रहा हूं लीड रोल ही है। बतौर निर्माता मैं ज्यादा पैसे बना सकता हूं, लेकिन कलाकार के तौर पर कैमरे के सामने संतुष्टि मुझे ज्यादा मिलती है। अगर मेरी भूमिका कहानी को आगे बढ़ा रही है, तो वह मेरे लिए अहम है। किरदार की लंबाई नहीं उसका प्रभाव कितना है, वो ज्यादा अहम है। उसके अलावा बेहतरीन कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिल रहा होता है। बाकी आप अपनी भूमिका को खुद अहम बना सकते हैं। मेरा मानना है कि आप एक सीन में अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं।

नेता की भूमिका में होंगे संजय। (@sanjaykapoor2500)

सही लेखक, सही जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं

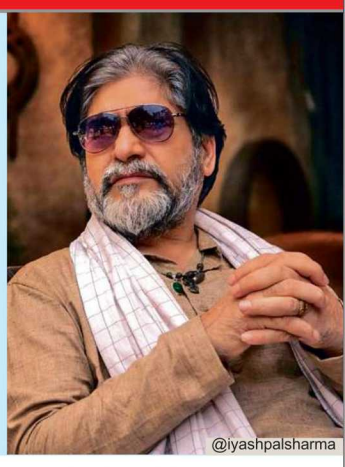

@iyashpalsharma

सात सवाल

गंगाजल, सिंह इज किंग और राउडी राठौर फिल्मों के अभिनेता यशपाल शर्मा इन दिनों कमर्शियल हिंदी फिल्मों के साथ-साथ छोटे बजट की विषय प्रधान और क्षेत्रीय हरियाणवी फिल्में भी कर रहे हैं। आगामी दिनों में उनकी वेब सीरीज दुपहिया सीजन 2, वेटिंग और ग्लोरी तथा वेलकम टू द जंगल समेत कई प्रोजेक्ट आने की कतार में हैं। पिछले करीब ढाई दशक से हिंदी सिनेमा में सक्रिय यशपाल से उनकी प्राथमिकताओं, वर्तमान सिनेमा और अभिनय सफर पर बातचीत:

• कमर्शियल फिल्मों के साथ-साथ, छोटे बजट की विषय प्रधान फिल्में और वेब सीरीज भी करना क्या रणनीति है?

– मेरी छोटे बजट की फिल्में ज्यादा हैं, क्योंकि उसमें रोल ज्यादा बड़ा और अच्छा मिलता है। उनकी कहानी किसी न किसी सामाजिक विषय पर आधारित होती हैं। मुझे वो फिल्में करने में मजा आता है। बाकी डिजिटल प्लेटफार्म पर मुझे जो कहानी और रोल पसंद आता है, वही करता हूं।

• सिंह इज किंग और राउडी राठौर के बाद वेलकम टू द जंगल में फिर अक्षय के साथ काम किया है। क्या अनुभव रहे?

– वेलकम टू द जंगल में किसी के साथ किसी की जोड़ी नहीं है। उसमें करीब 45-50 कलाकार हैं। फिर आप सोचिए उसमें किस कलाकार को कितना स्क्रीनटाइम मिला होगा। कमर्शियल सिनेमा साल में एक-दो करना पड़ता है, इसलिए वो फिल्म कर लिया है।

• पैन इंडिया फिल्मों के इस दौर में दक्षिण भारतीय सिनेमा के सामने दूसरे क्षेत्रीय सिनेमा को कितना स्थान मिल पा रहा है?

– क्षेत्रीय सिनेमा तो हमारा भविष्य है। क्षेत्रीय सिनेमा में बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं, मेरी भी चार-पांच फिल्में आ जाती हैं। सभी डिजिटल प्लेटफार्म पर हर भाषा की क्षेत्रीय फिल्में उपलब्ध हैं। मलयालम सिनेमा इन दिनों पूरी दुनिया में छाया हुआ है, उसका कंटेंट लाजवाब है। तमिल, तेलुगु, मराठी और गुजराती सिनेमा भी अब तो बहुत अच्छा करने लगा है। अब हरियाणा में भी अच्छी फिल्में बनने लग गई हैं।

• फिर तेलुगु और तमिल सिनेमा जैसे बजट और कमाई के आंकड़े दूसरे क्षेत्रीय सिनेमाओं में क्यों नहीं दिख रहे हैं?

– सुपरस्टार सिस्टम, तेलुगु और तमिल सिनेमा के अलावा किसी दूसरे क्षेत्रीय सिनेमा में अभी उतना नहीं है। रजनीकांत, विजय सेतुपति और दूसरे सुपरस्टार्स के नामों से फिल्में बिकती हैं। इसलिए कोई भी फिल्मकार उनके नामों पर सौ करोड़ रुपये लगा सकता है। बाकी हरियाणवी, पंजाबी या मराठी स्टार्स पर सौ करोड़ रुपये कौन लगाएगा? हमारे यहां वैसे दर्शक भी नहीं है। दर्शक क्षेत्रीय स्तर पर कम बजट की वास्तविकता के करीब बनी फिल्में पसंद करते हैं।

• हिंदी सिनेमा को लेकर अपनी जड़ों से भटकने जैसी बातें भी हो रही हैं। आपको कहां बदलाव की आवश्यकता दिखती है?

– हमारे यहां समस्या यह है कि अच्छे लेखकों की बहुत कमी है। सही लेखक, सही जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसीलिए वो डिजिटल प्लेटफार्म या आर्ट फिल्मों में चले जाते हैं। इसमें निर्माताओं की भी कमी है कि वो उनको सही मौके नहीं दे पा रहे हैं। वो भी ऐसी जगह ही पैसे लगाते हैं, जहां कोई स्टार दिख जाए। होमबाउंड जैसी कुछ अच्छी फिल्में बनती भी हैं तो कमर्शियली नहीं चल पाती हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छा सिनेमा नहीं बन रही हैं। अच्छा सिनेमा बन रहा है, लेकिन उसे सही दर्शक नहीं मिल रहे हैं।

• निर्देशक प्रकाश झा के साथ आपका जुड़ाव रहा, अब कैसा तालमेल है?

– हमारी शुरुआत गंगाजल से हुई थी। उनके पास अच्छे कलाकारों को काम मिलता था। फिर सुपरस्टार्स का दौर शुरू होने पर उन्होंने बड़े सितारों को लेना शुरू कर दिया। अब तो उन्होंने बतौर अभिनेता भी काम करना शुरू कर दिया है। श्याम बेनेगल व प्रकाश झा के साथ मेरी ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी। श्याम बेनेगल अब नहीं रहें। प्रकाश पुराने कलाकारों को भूलते चले गए, जिसमें मैं भी शामिल हूं।

• दादा लखमी के बाद बतौर निर्देशक और अभिनेता आगे क्या योजनाएं हैं?

– मुझे दादा लखमी पार्ट 2 बनानी है, अभी उसमें थोड़ा समय लूंगा। हरियाणवी तथा हिंदी सिनेमा और ज्यादा बनाना है।, फिलहाल अगले दो-तीन साल में सिर्फ एक्टिंग पर पूरा ध्यान दूंगा। पिछले छह साल मैंने हरियाणावी सिनेमा को दिया, अब कुछ समय अपने परिवार और अपने आपको देना चाहता हूं।

(दीपेश पांडेय)

मनोरंजन से जुड़ी अन्य खबरों के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

रहमान के बाद शुक्राचार्य की भूमिका में अक्षय खन्ना

फिल्म महाकाली में शुक्राचार्य की भूमिका में नजर आएंगे अक्षय। (PrasanthVarma)

फिल्म छावा में औरंगजेब और फिर धुरंधर में रहमान डकैत की भूमिका में सराहना बटोरने वाले अभिनेता अक्षय खन्ना पिछले साल खूब छाए रहे। हालिया प्रदर्शित और टिकट खिड़की पर रिकार्डतोड़ कमाई कर रही फिल्म धुरंधर : द रिवेंज जब रिलीज हुई तो भी लोगों ने उन्हें काफी याद किया। शनिवार को अक्षय 51 वर्ष के हो गए। उनकी इस जन्मतिथि पर प्रशंसकों को तोहफा देते हुए निर्देशक प्रशांत वर्मा ने अपनी आगामी फिल्म महाकाली से अक्षय का लुक जारी किया। पौराणिक कथाओं पर आधारित इस फिल्म में अक्षय दैत्य गुरु शुक्राचार्य की भूमिका निभा रहे हैं। एक्स पर अक्षय का लुक साझा करते हुए प्रशांत ने लिखा, 'अक्षय खन्ना सर, जन्मदिन की शुभकामनाएं। एक सच्चे कलाकार जिन्होंने साबित किया कि असली प्रतिभा को शोर मचाने की आवश्यकता नहीं होती है। स्क्रीन पर बहुत ही सहज, दमदार परफार्मेंस और बेजोड़ क्लास से हमेशा सबसे अलग दिखते हैं। आपके साथ काम करना बहुत सम्मान की बात है। दुनिया को यह दिखाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि हमने मिलकर क्या बनाया है।' बता दें कि इस फिल्म में अभिनेत्री भूमि शेट्टी देवी महाकाली की भूमिका में हैं।

फिल्म गोलमाल 5 में फिर कामेडी करते दिखेंगे अरशद। @arshad_warsi

सामने वाले कलाकार के कारण अरशद ने छोड़ीं बड़ी फिल्में

फिल्म बनाना एक टीमवर्क होता है, जिसमें अलग-अलग लोग एक साथ मिलकर एक अच्छा प्रोजेक्ट तैयार करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अगर साथ में काम करने वाले लोग अपने मन के और सहज महसूस कराने वाले हो तो काम बेहतर निकल के आता है। मुन्ना भाई एमबीबीएस तथा जाली एलएलबी फिल्मों के अभिनेता अरशद वारसी ने इसी सहजता को देखते हुए कुछ बड़ी फिल्में छोड़ दी। इस बारे में अरशद ने हाल ही में फिल्म जाली एलएलबी 3 में अपने सहकलाकार रह चुके अभिनेता अक्षय कुमार से बातचीत में बताया, 'बतौर कलाकार जब आप किसी ऐसे कलाकार के साथ काम कर रहे होते हैं, जो आपको सहज महसूस कराने वाला होता है, आपको हैरान नहीं कर रहा होता है तो काम करने में मजा आता है।' आगे अरशद ने कहा कि मैं एक ऐसी एक-दो बड़ी फिल्म छोड़ चुका हूं, क्योंकि मुझे लगा कि यार मैं इस बंदे (सामने वाले कलाकार) को झेल नहीं पाऊंगा। जब आप किसी फिल्म में काम करते हैं, तो पूरी टीम साल-डेढ़ साल तक साथ में बिताती है। अगर वो चल जाए तो आगे भी काम करते हैं। ऐसे में अगर आपके पास यह चुनने का विशेषाधिकार हो कि आप किसके साथ काम कर सकते हैं? तो यह बहुत बढ़िया है।